चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

29 जुलाई–04 अगस्त 2013

तीसरा मोर्चा

कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

यूं तो तीसरा मोर्चा बनाने की नूरा-कुश्ती हिंदुस्तान की सियासत में पिछले पच्चीस सालों से चल रही है, लेकिन इस कवायद में लगे नेताओं की, मैं भी प्रधानमंत्री-मैं भी प्रधानमंत्री वाली हसरतों ने इसे ठोस शक्ल अख्तियार करने ही नहीं दिया. आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र तीसरे मोर्चे के गठन में एक बार फिर सियासी बवंडर उठने लगे हैं, लेकिन इसमें शामिल होने वाले मौकापरस्त और शातिर नेता झूठी हेकड़ी की वजह से अपनी ज़मात इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे. नतीजतन, इसकी आड़ में चौथा मोर्चा तो आकार लेता नज़र आ रहा है, पर तीसरे मोर्चे की परिकल्पना एक बार फिर हवा-हवाई होती दिख रही है.

> **मुलायम सिंह यादव और मायावती किसी भी क़ीमत पर एक साथ खड़े नहीं हो सकते. तमिलनाडु में एम करुणानिधि भी जयललिता के साथ चलने के लिए राजी नहीं हैं. उधर, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में भले ही करुणानिधि की पार्टी द्रमुक के प्रत्याशी को समर्थन दिया हो, पर इस बात की संभावना नहीं केबराबर ही दिखती है कि करुणानिधि अगले लोकसभा चुनाव में यूपीए को समर्थन भी देंगे. जयललिता भले ही नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्त हों, पर वह भाजपा के साथ खड़ी नहीं हो सकतीं, क्योंकि जयललिता ने हमेशा तीसरे मोर्चे के पक्ष में ही बयान दिया है.**

रूबी अरुण

राजनीति में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता. 1975 और 1989 के तजुर्बे भी यही बताते हैं कि सियासत की मजबूरियां धुर विरोधी दलों और विचारधाराओं को भी एक साथ खड़ा कर सकती हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने के ख्वाहिशमंद दलों के नेताओं में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके बीच वैचारिक स्तर पर आपस में कोई सामनजस्य ही नहीं है. ये नेता एक-दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते. मसलन, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों को ही तीसरे मोर्चे की तलाश है, पर मुलायम सिंह यादव और मायावती किसी भी क़ीमत पर एक साथ खड़े नहीं हो सकते. तमिलनाडु में एम करुणानिधि भी जयललिता के साथ चलने के लिए राजी नहीं हैं. उधर, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में भले ही करुणानिधि की पार्टी द्रमुक के प्रत्याशी को समर्थन दिया हो, पर इस बात की संभावना नहीं के बराबर ही दिखती है कि करुणानिधि अगले लोकसभा चुनाव में यूपीए को समर्थन भी देंगे. उधर, जयललिता भले ही नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्त हों, पर वह भाजपा के साथ खड़ी नहीं हो सकतीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तीसरे मोर्चे के पक्ष में ही बयान दिया है. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर जयललिता ने नए विकल्पों पर बात की है. हालांकि वह इस मसले पर फ़ैसला चुनाव के बाद ही करेंगी. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू भी इसी कश्मकश से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये दोनों दल एक साथ किसी एक मोर्चे में नहीं रह सकते. ऐसे में जाहिर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की लड़ाई चौतरफ़ा ही होगी और यूपीए एवं एनडीए, दोनों गठबंधनों के चुनावी समीकरणों में उलट-फेर होने की पूरी गुंजाइश भी बनती है. इन नेताओं की अदावत पर नज़र डालें, तो बड़ी ही सहजता से चौथा मोर्चा अपनी शक्ल लेता हुआ नज़र आता है.

बहरहाल, हम बात कर रहे हैं तीसरे मोर्चे के गठन और

उनकी संभावनाओं की. इन दिनों कुछ चुनावी सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि देश के लोगों का मिजाज क्षेत्रीय दलों की ओर झुक रहा है. इस लिहाज़ से अगले लोकसभा चुनाव में ये तमाम क्षेत्रीय दल मिल-जुल कर एक बड़ी ताक़त के तौर पर भी उभर सकते हैं. यही वज़ह है कि इस तीसरे मोर्चे में वह हर पार्टी शामिल होना चाहती है, जो अपने आपको भाजपा और कांग्रेस से अलग दिखाना चाहती है. पर तीसरे मोर्चे की विडंबना यह है कि पिछले पच्चीस सालों में हिंदुस्तान की सियासत में यह बस एक मिथक बनकर रह गया है, लेकिन जब-जब तीसरे मोर्चे के गठन की बयार बहती है, तब-तब कुर्सी की जंग में तीसरा मोर्चा बनते-बनते बिखर जाता है. दरअसल, तीसरा मोर्चा इतनी बार बना और बिखरा है कि अब इसे देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती. इसलिए पिछले दिनों जब मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे का अपना पुराना राग अलापा, तो वहीं उनकी बात गंभीरता से नहीं ली गई. इसकी एक वज़ह शायद यह भी रही कि एक तरफ़ मुलायम सिंह भाजपा से अलग दिखने की जद्दोजहद में तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ़ उनके भाई राम गोपाल यादव लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ में कसीदे काढ़ते नज़र आते हैं. हालांकि यह वही समाजवादी पार्टी है, जिसकी पहल पर यूएनपीए बना था और जिसमें वे सभी पार्टियां शामिल हुई थीं, जो न एनडीए में थीं और न ही यूपीए में, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ही यूएनपीए से अलग हो गई और उसने यूपीए के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया.

मौक़े की नजाकत भांपते हुए जहां एक ओर ममता बनर्जी ने फेडरल फ्रंट के नाम से एक नया सियासी शिगूफा छोड़ा, तो वहीं दूसरी ओर तेलगु देशम प्रमुख चंद्र बाबू नायडू ने भी अपना क़दम बढ़ा दिया. उधर नवीन पटनायक भी देश की जनता के सामने अपने आपको कांग्रेस एवं भाजपा से दूर और अलग दिखाने की कोशिश में तीसरे मोर्चे की आग को हवा देने में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जनतंत्र आए, देश में जनता का राज हो : अन्ना 03

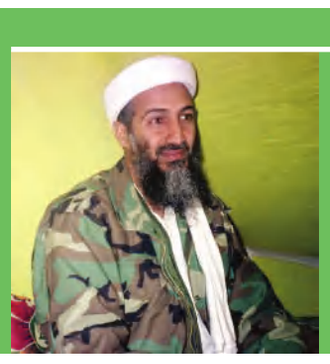

अमेरिकी और पाक सरकार की नई मुसीबत 05

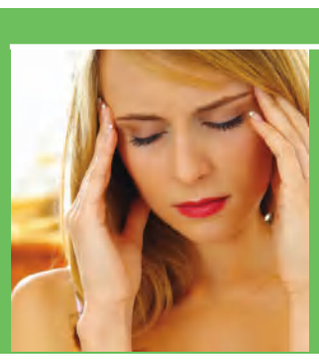

कहीं माइग्रेन तो नहीं 07

साई की महिमा 12

कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री

पृष्ठ एक का शेष

लग गए. तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे नेताओं में से नवीन पटनायक को छोड़कर, बाकी सभी की इस सियासी जंग में पहचान गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी की ही रही है, पर मुश्किल फिर वही आएगी कि ममता के फेडरल फ्रंट में मुलायम सिंह यादव शामिल नहीं हो सकते, तो ऐसे में उनके क़रीबी वामदलों का तो ममता के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

यही वज़ह है कि कई मौक़ों पर कांग्रेस के संकटमोचक बने मुलायम सिंह यादव कोई अलग राह तलाश रहे हैं, तो कांग्रेस के हर फ़ैसले में तक़रीबन उसकी हमक़दम रहने वाली एनसीपी को भी तीसरे मोर्चे की ज़रूरत महसूस हो रही है. कृषि मंत्री एवं एनसीपी नेता शरद पवार ने अपनी रणनीति पर बाकायदा अमल करना भी शुरू कर दिया है. पवार ने बीजू जनता दल एवं सीपीआई (एम) से लोकसभा चुनाव के पहले ही गठबंधन की बात की है, तो साथ ही साथ वह एनडीए एवं यूपीए में शामिल अन्य दलों से भी बातचीत कर रहे हैं. चुनाव के बाद के समीकरणों को नज़र में रखते हुए उन्होंने शरद यादव से भी बातचीत की है, लेकिन फिलहाल पेंच वहीं आकर फंस रहा है, यानी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर. शरद पवार की पुरानी हसरत है कि वह प्रधानमंत्री बनें और ऐसे ही सपने उन सभी महारथियों के भी हैं, जो तीसरे मोर्चे का परचम लहराना चाहते हैं. उस पर तुर्रा यह कि ये सभी नेता एवं पार्टियां मिलकर भी सवा सौ–डेढ़ सौ से ज़्यादा सांसद लोकसभा में नहीं ला सकते. इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे मोर्चे के गठन के लिए जिस तरह की एकजुटता, लचीलेपन, समन्वय, अनुभव, ढांचे और वैचारिक एकता की ज़रूरत है, उसकी घोर कमी नज़र आती है. ममता बनर्जी ने भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका फेडरल फ्रंट एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा, या गैर कांग्रेस और गैर भाजपा मोर्चा के तौर पर. सवाल यह है कि क्या फेडरल फ्रंट देश की सत्ता पर इसी बहाने काबिज़ होने की भी जुगत करेगा. दरअसल, मुद्दों के अकाल के बीच तीसरे मोर्चे के गठन का सियासी बवंडर खड़ा करना भी आज राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा है. मोर्चे का गठन हो न हो, पर फौरी तौर पर इसके बड़े फ़ायदे जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि कम से कम इसी बहाने राष्ट्रीय राजनीति के हाशिए पर पड़े नेता चर्चा में आ जाते हैं. हालांकि देश को इस वक़्त तीसरे मोर्चे की सख्त ज़रूरत है, लेकिन यह तभी संभव है, जब कांग्रेस और भाजपा, दोनों को ही मिलाकर लोकसभा में दो सौ बहत्तर से भी कम सीटें लाएं. उदाहरण के तौर पर हम एग्जिट पोल पर भी नज़र डालें, तो उसके हिसाब से कांग्रेस एक सौ पच्चीस और भाजपा दो सौ के आसपास सीटें ला सकती है. अगर हम इसे सही मान लें, तो यह आंकड़ा कुल मिलाकर तीन सौ पच्चीस होगा. अब क्या ऐसे में तीसरा मोर्चा सत्ता में आ सकता है या वह सरकार बना सकता है? तब इस तीसरे मोर्चे को सरकार बनाने में मदद लेने के लिए भाजपा या कांग्रेस का ही मुंह देखना पड़ेगा. बात फिर वही हो जाएगी. या तो देश में कांग्रेस नीत सरकार बनेगी या फिर भाजपा नीत. ऐसे में तीसरे मोर्चे का कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा. मतलब यह कि तीसरा मोर्चा एक बार फिर मुंह की खाएगा.

देश को इस वक़्त तीसरे मोर्चे की सख्त ज़रूरत है, लेकिन यह तभी संभव है, जब कांग्रेस और भाजपा, दोनों को ही मिलाकर लोकसभा में दो सौ बहत्तर से भी कम सीटें आएं. उदाहरण के तौर पर हम एग्जिट पोल पर भी नज़र डालें, तो उसके हिसाब से कांग्रेस एक सौ पच्चीस और भाजपा दो सौ के आसपास सीटें ला सकती है. अगर हम इसे सही मान लें, तो यह आंकड़ा कुल मिलाकर तीन सौ पच्चीस होगा. अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे में तीसरा मोर्चा सत्ता में आ सकता है या वह सरकार बना सकता है? तब इस तीसरे मोर्चे को सरकार बनाने में मदद लेने के लिए भाजपा या कांग्रेस का ही मुंह देखना पड़ेगा.

चलिए पल भर के लिए मान लेते हैं कि तीसरा मोर्चा बन गया और उस स्थिति में कांग्रेस एवं भाजपा, दोनों ही मिलकर दो सौ बहत्तर सीटें नहीं ला पाईं, तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी. तब सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि तीसरे मोर्चे में शामिल नेताओं में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इस पार्टी में लगभग सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे! अगर यहां प्रधानमंत्री बनने का मानक यह तय किया जाएगा कि जो पार्टी सबसे बड़ी होगी, यानी सबसे ज़्यादा सीटें ले आएगी, उसका नेता प्रधानमंत्री बनेगा, तब तो एक अनुमान के तौर पर, फिलहाल हम यह मानकर चलें कि सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह तीसरे मोर्चे में सबसे अधिक सीटें लेकर आएंगे, तो क्या ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा. पर यहां एक और स्थिति खास होगी. वह यह कि लगभग सभी पार्टियों की ताक़त बराबर होगी. तब कौन, किसकी सुनेगा? क्या सभी किसी भी मसले पर एक राय हो सकेंगे? अब अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या यह बात मुलायम सिंह सह पाएंगे? फ़र्ज़ कीजिए कि नीतीश बन भी गए, तो फिर वह सरकार मुलायम सिंह के रहमोकरम पर ही रहेगी. ऐसे में उस सरकार के कितने दिनों तक टिकने की संभावना रहेगी, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं. मतलब यह है कि यदि इन विचारधाराओं के आधार पर भी फिलहाल आकलन करें, तो कोई गैर भाजपा या गैर कांग्रेसी ताक़त आकार लेती नज़र नहीं आ रही है. पर हां, इटली की तर्ज़ पर हिंदुस्तान में भी एक नया राजनीतिक प्रयोग देखने को ज़रूर मिल सकता है, जिसमें एनडीए और यूपीए की शक्ल में दो मोर्चों की बजाय चार मोर्चे नज़र आएं. हालांकि इटली के लिए यह राजनीतिक प्रयोग बेहद घातक सिद्ध हुआ है. यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत आज बहुत नाज़ुक है, लेकिन अपने देश के संदर्भ में हम बेहतर की ही उम्मीद करें, तो अच्छा है.

अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे के संदर्भ में वामदलों की भूमिका और उनके नज़रिए की. हिंदुस्तान में थर्ड फ्रंट की अगुवाई हमेशा वामपंथी दलों ने ही की है, क्योंकि उन्हें भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति की मुखालफत करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की अवधारणा कायम रखनी थी. इसलिए भी वामपंथी दलों ने अपने आर्थिक और अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा अन्य दलों से बिल्कुल अलग रखी. देश के सियासी हालात में तेज़ी से आते बदलाव और ममता बनर्जी की कोशिशों ने वामदलों के अंदर अकुलाहट भर दी है. वैसे भी, वामपंथियों को पश्चिम बंगाल में अपना वजूद कायम रखने की लड़ाई अभी भी लड़नी है. इसलिए ममता के साथ किसी मोर्चे में शामिल होने की बात वे सपने में भी नहीं सोच सकते. अपना अस्तित्व बनाए रखने की खातिर, उनके लिए बेहद ज़रूरी है गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी विकल्प बनाने की, ताकि उनकी जद्दोज़हद जारी रहे. यही वज़ह रही कि जहां एक ओर माकपा नेता सीताराम येचुरी ने शरद यादव से इस मसले पर मुलाक़ात की और तमिलनाडु के राज्यसभा चुनाव में द्रमुक को समर्थन देने का फ़ैसला किया, तो वहीं दूसरी ओर भाकपा महासचिव ए बी वर्धन से भी मिलकर इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया. जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक़, वामपंथी नेताओं ने अपनी रणनीति के तहत लामबंदी की शुरुआत भी कर दी है. संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि वामपंथी और लोकतांत्रिक दल कोई औपचारिक मोर्चा न बनाएं, बल्कि वे चुनावी तालमेल का ही कोई रास्ता अख्तियार कर लें. वज़ह यह है कि इस वक़्त वामपंथी दल भटकाव की हालत में हैं. वरना जब तीसरे मोर्चे की आवश्यकता सबसे ज़्यादा महसूस हो रही हो, उस समय देश के सबसे बड़े वामपंथी नेता प्रकाश करात अगर यह कहें कि चुनाव के पहले तीसरे मोर्चे के गठन की कोई संभावना ही नहीं बनती है, तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल वामदलों की धुरी में केंद्र नहीं है. जिस समय मुलायम सिंह, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक सभी ममता बनर्जी की बात कर रहे हों, ऐसे में यदि उसी समय प्रकाश करात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चीन नीतियों की तारीफ करने लगें, तो यह बात सहज ही समझ में आ जाती है कि वामपंथी चाहते हैं कि कांग्रेस की मदद से पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकें, ताकि वहां वे अपना वजूद फिर से कायम कर सकें. इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि वे कांग्रेस का समर्थन भी कर सकते हैं. इन तमाम हालात, राजनीतिक दलों के निजी हितों और उनके आधार पर बनते–बिगड़ते समीकरणों पर यदि गौर करें, तो बस एक ही बात समझ में आती है कि तीसरे मोर्चा बनाने की आपाधापी करने वाले तमाम राजनीतिक दलों का मकसद यह कतई नहीं कि वे तीसरा मोर्चा बनाकर देश को एक नई सरकार दें, जो वाकई धर्मनिरपेक्ष हो. जिसका उद्देश्य देश को साफ़–सुथरा एवं भ्रष्टाचार विरोधी शासन देना हो, जो ऐसी नीतियां बनाए, जिससे आम हिंदुस्तानी रोज़मर्रा की दुश्वारियों से निजात पा सके और उसकी ज़िंदगी सहज और आसान हो सके. इसके विपरीत उनका मकसद सिर्फ़ इतना भर है कि वे सभी दल मिल–जुल कर एक ऐसा तीसरा मोर्चा बनाएं, जो किसी तरह केंद्र में बनने वाली किसी भी सरकार पर दबाव बनाए रख सकें, जिससे उनकी जायज़–नाजायज़ सियासी ख्वाहिशें पूरी होती रहें. ■

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 05 अंक 21
दिल्ली, 29 जुलाई–04 अगस्त 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
6452888
011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला

दिल्ली में यद्यपि अगले पुलिस कमिश्नर को लेकर चीजें व्यवस्थित रहीं, लेकिन बिना उचित विकल्प के गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस के 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले से राजधानी में उपायुक्त स्तर के अधिकारियों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से घटा दिया है. बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच इसका असर दिल्ली पुलिस के काम पर पड़ना तय है. जिन अधिकारियों का तबादला किया गया, उनमें अजय चौधरी, विनय विक्रम चौधरी, धीरज कुमार, राजीव रंजन, देवेंद्र आर्य समेत कई अन्य शामिल हैं. ये अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित राज्य कैडर के हैं, लेकिन इन्हें विभिन्न राज्यों में पोस्ट किया गया है. नवंबर में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह कहना कठिन होगा कि कैसे दिल्ली पुलिस अधिकारियों के टोटे के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगी. ■

पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पुलिस सुधार लागू करने को लेकर राज्य सरकारें गंभीर नहीं हैं. ऐसे राज्यों से अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से निपटने का मन बना लिया है. इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए शीर्षस्थ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को सम्मन भेजा है और कहा है कि वे कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताएं कि पुलिस सुधार के लिए उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है. जिन लोगों को कोर्ट ने सम्मन भेजा है, उनमें श्रीमती शीला बालाकृष्णन (तमिलनाडु), जावेद उस्मानी (उत्तर प्रदेश), पी के मोहंती (आंध्र प्रदेश) और जे के बंथिया (महाराष्ट्र) प्रमुख हैं. सूत्रों का कहना है कि भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त प्रकाश सिंह द्वारा तैयार किए गए पुलिस सुधारों को लागू कर दिया गया होता, लेकिन राजनीतिज्ञों द्वारा अड़ंगा लगाने से इसे लागू नहीं किया जा सका. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़े कदम उठाने के बाद पुलिस सुधार के क्षेत्र में कुछ प्रगति देखने को मिल सकती है. ■

महाराष्ट्र में महीनों से खाली बैठे हैं अधिकारी

सरकार की उदासीनता की इससे बड़ी बानगी शायद ही कहीं मिले. महाराष्ट्र में वरिष्ठ अधिकारियों की एक खेप महीनों से खाली बैठने को मजबूर है. उनके पास करने को कोई काम नहीं है. सूत्रों की मानें, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या करीब 24 है. इनमें से कुछ को नए कार्यभार का इंतजार है, तो कई को स्थानातंरित होने का, लेकिन फिर भी सरकार बेफिक्र है. इस स्थिति को लेकर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. इनमें से कुछ बाबुओं ने बताया कि अस्पष्ट स्थानांतरण नीति इसकी सबसे बड़ी वजह है. तानाजी सातरे भी इसी उधेड़बुन का शिकार हैं. वह नगर एवं औद्योगिक विकास निगम में प्रबंध निदेशक थे, लेकिन बीते तीन महीनों से वह अपने नए कार्यभार की प्रतीक्षा कर रहे हैं. यही हाल महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के सीईओ एसएस शिंदे और औरंगाबाद नगरपालिका आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर का भी है. उन्हें भी अपने पदों से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन पृथ्वीराज चह्वाण सरकार से अभी तक नया कार्य नहीं मिला है. अधिकारियों की कमी के बीच इस नीति का राज्य प्रशासन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. पता चला है कि 1988 बैच के सभी अधिकारी जल्द ही मिड–करियर ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं. ऐसी स्थिति में क्षमता और घट जाएगी. ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ सकते हैं सिहाग

1983 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी भारती एस सिहाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बतौर अतिरिक्त सचिव का कार्यभार संभाल सकते हैं. वह 1982 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी जितेंद्र शंकर माथुर का स्थान लेंगे.

डब्ल्यूडीआरए में जाएंगे रणवीर सिंह

1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी रणवीर सिंह नए संयुक्त सचिव के तौर पर वेयरहाउसिंग विकास नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का प्रभार संभालेंगे. वह 1988 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी रवनीत कौर का स्थान लेंगे.

दीपांकर होंगे नए जूट उपायुक्त

भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त कैडर के 1998 बैच के अधिकारी दीपांकर महतो कपड़ा मंत्रालय, कोलकाता में नये उपायुक्तका पदभार संभालेंगे. वह गुजरात कैडर की 2001 बैच की आईएएस अधिकारी आरती कंवर की जगह लेंगे.

राजीव सदानंद श्रम मंत्रालय से जुड़ने को तैयार

1985 बैच के कोलकाता कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव सदानंद बतौर जेएस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़ने को तैयार हैं. वह 1981 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनिल स्वरूप की जगह लेंगे.

अपराजिता का भू–संसाधन विभाग में जेएस बनना तय

1994 बैच की ओडिशा कैडर की आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी के भू–संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनने की प्रबल संभावना है. वह 1981 बैच की राजस्थान कैडर के आईएफएस अधिकारी डॉक्टर सविता आनंद की जगह लेंगी.■

> अन्ना 15 जुलाई को शिवपुरी और गुना पहुंचे. लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की दयनीय हालत के लिए केंद्र सरकार और उसकी गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं. इसलिए अब किसानों को एक मंच पर लाकर उनकी समस्याओं को दूर करना जरूरी हो गया है, लेकिन इससे पहले लोकपाल जरूरी है. जनता को भ्रष्टाचार मुक्त रखने और सरकार के भ्रष्ट महकमों पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल बहुत ही जरूरी है.

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

यह सरकार भ्रष्ट है

समाजसेवी अन्ना अपनी जनतंत्र यात्रा के क्रम में 13 जुलाई को शाहगढ़ और धुबरा पहुंचे. भारी संख्या में लोग गांधीवादी अन्ना के स्वागत में सभा स्थल पर पहुंचे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवा थे. अन्ना ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश को धोखा दिया है. सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहती. उन्होंने कहा कि सरकार ने मजबूत लोकपाल को लेकर भी देश को धोखा दिया है. उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल पास करवाना मेरा पहला लक्ष्य है और मैं इसे पास करवा कर रहूंगा. अन्ना से मिलने किसान भी पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि पहले लोकपाल पास हो जाए, इसके बाद किसानों के हितों की लड़ाई लड़ूंगा. जनतंत्र यात्रा के क्रम में अन्ना 14 जुलाई को दतिया और ग्वालियर पहुंचे. यहां भी लोग हजारों की तादाद में अन्ना को देखने–सुनने पहुंचे थे. लोग अन्ना के समर्थन में नारे लगा रहे थे. हर तरफ से यही आवाज आ रही थी, अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अन्ना ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आगे बढ़ कर देश की कमान संभालनी पड़ेगी. यह सरकार पहले वादा करती है, फिर धोखा देती है. खुद हमारे प्रधानमंत्री वादा नहीं निभाते. अन्ना की सभा में गांव और शहरों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे.

अन्ना 15 जुलाई को शिवपुरी और गुना पहुंचे. लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की दयनीय हालत के लिए केंद्र सरकार और उसकी गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं. इसलिए अब किसानों को एक मंच पर लाकर उनकी समस्याओं को दूर करना जरूरी हो गया है, लेकिन इससे पहले लोकपाल जरूरी है. जनता को भ्रष्टाचार मुक्त रखने और सरकार के भ्रष्ट महकमों पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल बहुत ही जरूरी है. 16 जुलाई को अन्ना बेवारा और शाजापुर पहुंचे. यहां अन्ना के स्वागत में बच्चे, बुढ़े, युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ पहुंची थी. लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं है, जहां भ्रष्टाचार नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार इस बात से अनजान है, लेकिन वह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए गंभीर नहीं है. अन्ना ने कहा कि हमें मजबूत लोकपाल चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे. समाजसेवी अन्ना हजारे जनतंत्र यात्रा के पांचवें चरण के आखिर में 17 जुलाई को उज्जैन, देवास और इंदौर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से लोकपाल के मुद्दे पर ऐसी उम्मीद नहीं थी. यह काम तो सरकार को खुद करना चाहिए था, लेकिन यह सरकार इतनी भ्रष्ट है कि उसे इस बारे में सोचने का समय ही नहीं है. कोई ऐसा दिन नहीं होता, जिस दिन सरकार की गलत नीतियों, उसके महकमों में फैले भ्रष्टाचार और घोटाले की बात सामने नहीं आती. इसी के साथ ही अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा का मध्य प्रदेश दौरा समाप्त हो गया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

जनतंत्र आए, देश में जनता का राज हो : अन्ना

चौथी दुनिया ब्यूरो

मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि श्री नरेंद्र मोदी को मैं सांप्रदायिक मानता हूं या नहीं, तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता. लेकिन समाचार छापा कि अन्ना ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं हैं, जो कि गलत है. इसका मतलब यह नहीं है कि वे सांप्रदायिक है या नहीं है. वे ऐसे दल में हैं, जिस दल की यह मान्यता है कि वह एक समुदाय के पक्ष में है और कुछ समुदायों के खिलाफ है, खासकर एक समुदाय के बहुत खिलाफ है और यह सर्वविदित भी है.

अब रहा सवाल मेरे कथन का, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है. यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि मैंने किसी को सांप्रदायिक नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया है. सर्टिफिकेट देने वाला मैं कोई नहीं हूं. भारत का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है. इसलिए सब पार्टियों को उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा. जो पार्टियां उसके अनरूप नहीं चलेंगी, उनको बहुमत नहीं मिल सकता. एक दल जिस तरह की बात करता है, उन बातों से लगता है कि उसका रुझान सांप्रदायिक है. मैं नहीं चाहता कि यह बात मैं व्यक्ति विशेष को लेकर कहूं, क्योंकि यह तो उनके पूरे दल का मामला है. भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है. इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी का जो मत है, उसी को प्रतिबिंबित करेंगे. मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता. मैं तो देश में जनतंत्र अभियान चला रहा हूं. भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जगा रहा हूं. जनतंत्र लाना चाहिए, भष्टाचार हटना चाहिए, जनलोकपाल का कानून बनना चाहिए और सीबीआई सहित जांच एजेंसियों को स्वतंत्र होना चाहिए. जो भी इलेक्शन के बाद पावर में आए, उसे गैर–सांप्रदायिक होना चाहिए और अभी जो चल रहा है, उससे बेहतर शासन देना चाहिए.

मैं चाहता हूं कि देश में संविधान के अनुसार जनतंत्र आए. देश में जनता का राज हो, पक्ष या पार्टी का नहीं. क्योंकि संविधान में पक्ष और पार्टी का जिक्र है ही नहीं. जहां तक मैं जानता हूं, मोदी जी ने गोधरा और उसके बाद हुए दंगों का तीव्र निषेध अब तक नहीं किया है. इसलिए मैं वह सांप्रदायिक नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट उन्हें कैसे दे सकता हूं.

मैं शुरू से ही सांप्रदायिकता के विरोध में हूं, क्योंकि सांप्रदायिकता से देश के टूटने का खतरा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

स्लीपर घोटाले को समझने के लिए पहले रेलवे के कुछ नियमों को समझना ज़रूरी है. रेलवे बोर्ड का नियम था कि क्रंकीट स्लीपर की खरीद खुली निविदा से ही होगी. इस नियम के कारण इस काम से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. इसका हल निकालने के लिए एक खास लॉबी ने ममता बनर्जी के सामने एक प्रस्ताव रखवाया कि क्रंकीट स्लीपर की खरीद खुली निविदा की बजाय सीमित टेंडर के मार्फत हो.

जम्मू-कश्मीर

स्लीपर घोटाला

नीतीश को क्यों बचा रही है सीबीआई

स्लीपर घोटाला एक बार फिर चर्चा में है. वजह है, सीबीआई के परस्पर विरोधी एवं भ्रामक बयान. आरोप यह भी है कि वह इस मामले में नीतीश कुमार के बचाव का प्रयास कर रही है और उसके पीछे कांग्रेस है.

सरोज सिंह

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई क्या वाकई दबाव में है? हज़ारों करोड़ रुपये के स्लीपर घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई जिस तरह से भ्रम पैदा कर रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि स्लीपर घोटाले की जांच में अभी कई पेंच फंसे हुए हैं. लोकतांत्रिक समता दल के अध्यक्ष पी के सिन्हा एवं उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने घोटाले की जांच से संबंधित जो दस्तावेज़ सार्वजनिक किए हैं, उन्हें देखकर यही महसूस होता है कि सीबीआई अलग-अलग मौक़ों पर अलग-अलग बात करके कुछ न कुछ छिपाना चाह रही है. हालांकि उक्त नेताओं का दावा है कि वे किसी भी क़ीमत पर सच सामने लाकर रहेंगे. उनका आरोप है कि कांग्रेस से नीतीश कुमार की दोस्ती की बुनियाद में यही स्लीपर घोटाला है और कांग्रेस इस मामले में सीबीआई के माध्यम से नीतीश कुमार की मदद भी कर रही है.

इन आरोपों से अलग, अगर दस्तावेज़ों पर बात करें, तो ताजा दस्तावेज़ में सीबीआई ने याचिकाकर्ता मिथिलेश सिंह को सूचित किया है कि क्रंकीट स्लीपर की खरीद से संबंधित किसी मामले की जांच उसने नहीं की है. देखने वाली बात तो यह है कि सूचना का अधिकार क़ानून के तहत 12 अगस्त, 2008 को मिथिलेश सिंह को जो सूचना दी गई थी, उसमें रेल मंत्रालय ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई तीसरी पार्टी है और उसने इस संबंध में कोई भी सूचना देने से मना किया है, इसलिए इस मंत्रालय द्वारा सूचना नहीं दी जा सकती है. ग़ौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने सूचना मांगी थी कि 14वीं लोकसभा की रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के सातवें प्रतिवेदन में स्लीपर खरीद से संबंधित अनियमितताओं एवं घोटाले के कारण रेल विभाग को हुई भारी क्षति की जांच सीबीआई को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है. ऐसे में जानकारी दी जाए कि जांच की ताजा स्थिति क्या है. सूचना देने

में आनाकानी के बाद याचिकाकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आयोग के हस्तक्षेप के बावजूद, सूचक की जान पर ख़तरे का हवाला देते हुए सीबीआई ने जानकारी मुहैया नहीं कराई. इसके बाद मिथिलेश सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 12 दिसंबर, 2011 को याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान सहायक सॉलीसिटर जनरल एस चाढोस ने न्यायालय को सूचित किया कि सीबीआई ने इस मामले में जांच करके प्रतिवेदन सौंप दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है. लेकिन नए दस्तावेज़ में सीबीआई जांच की बात नहीं कही गई है. आख़िर सीबीआई के हवाले से अलग-अलग मौक़ों पर अलग-अलग बात क्यों कही जा रही है.

स्लीपर घोटाले को समझने के लिए पहले रेलवे के कुछ नियमों को समझना ज़रूरी है. रेलवे बोर्ड का नियम था कि क्रंकीट स्लीपर की खरीद खुली निविदा से ही होगी. इस नियम के कारण इस काम से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. इसका हल निकालने के लिए एक खास लॉबी ने ममता बनर्जी के सामने एक प्रस्ताव रखवाया कि क्रंकीट स्लीपर की खरीद खुली निविदा की बजाय सीमित टेंडर के मार्फत हो. इसके अलावा, यह

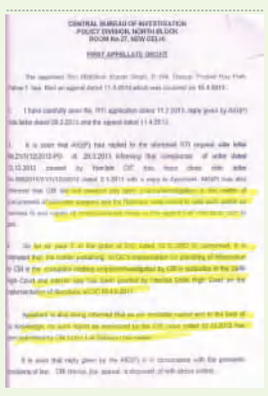

भी आज़ादी हो कि किसी भी जोन से कहीं के लिए भी स्लीपर खरीदा जा सके. ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव में छिपी घोटाले की बदबू को पहले ही महसूस कर लिया, इसलिए उन्होंने इसे सिरे से खारिज ही कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने यह आदेश भी निर्गत कर दिया कि निविदा तीन की बजाय दो साल पर होगी, लेकिन ममता बनर्जी के हटने के बाद नीतीश कुमार के कार्यकाल, यानी 19 मार्च, 1998 से 5 अगस्त 1999 और 20 मार्च, 2001 से 22 मई, 2004 के दौरान सारे नियम बदल डाले गए.

संसद में रेलवे की स्थायी समिति ने जांच के दौरान कुछ तथ्य उजागर किए. स्थायी समिति ने पाया कि रेल मंत्री के आदेश के कारण रेलवे को एक मोटे अनुमान के अनुसार, दो अरब रुपये का नुक़सान हुआ. नियमों को ताख पर रखकर गया के दया इंजीनियरिंग वर्क्स को स्लीपर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. 17 अगस्त, 2004 को स्थायी समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में निर्णय लिया कि जिन लोगों ने रेलवे को घाटा पहुंचाया है, उनकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो. 17 फरवरी, 2005 को स्थायी समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि क्रंकीट स्लीपर घोटाले की जांच सीबीआई ने ले ली है. इस बात की जानकारी लोकसभा एवं राज्यसभा को भी दे दी गई. अब बात आई कि आख़िर सीबीआई की जांच किस तेजी से चल रही है और कब पूरी होगी. लोक चेतना मंच के संयोजक मिथिलेश सिंह ने यह जानने के लिए एक आरटीआई डाली. उसके जवाब में रेल मंत्रालय ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने सूचना देने से रेल मंत्रालय को मना कर दिया है. मिथिलेश सिंह ने महसूस किया कि चूंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं, इसलिए कहीं न कहीं से मामले को लटकाने का दबाव बन रहा है. इसी के चलते उन्होंने अपने अधिवक्ता दीनू कुमार के मार्फत एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर कर दी. याचिका में आग्रह किया गया था कि मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन क्षेत्राधिकार की बात कहकर अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया. इसके बाद यह मामला दिल्ली की अदालत में गया.

आख़िर क्या बात है, जो इतने साल बीत जाने के बावजूद इस घोटाले का सच सामने नहीं आ पा रहा है. राजद विधायक सम्राट चौधरी कहते हैं कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जांच पूरी करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए. जो दोषी नहीं होंगे, वे बाइज्जत बरी हो जाएंगे और जो दोषी होंगे, वे सजा पाएंगे. मामले को लटकाने से क्या फ़ायदा? अगर किसी को शक है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो सरकार को स्थिति साफ़ कर देनी चाहिए. याचिकाकर्ता मिथिलेश सिंह कहते हैं कि सीबीआई दबाव में भ्रम पैदा कर रही है और वह नीतीश कुमार को बचाना चाहती है, लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है और एक न एक दिन न्याय होकर रहेगा. पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा का आरोप है कि कांग्रेस से जदयू की दोस्ती के पीछे और कुछ नहीं, सिर्फ़ स्लीपर घोटाले की जांच है, नरेंद्र मोदी तो केवल एक बहाना हैं. सिन्हा का दावा है कि जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा. ■

सच सामने आना ज़रूरी

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सच तो सामने आना ही चाहिए. सीबीआई के रवैये से लग रहा है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, वरना वह अपने ही स्टैंड से वापस क्यों हटती. कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस सीबीआई का डर दिखाकर नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि स्लीपर घोटाले का सच जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा. लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार घोटाले की सरकार है. दिल्ली में सरकार में रहते वह जो कर रहे थे, वही अब बिहार में हो रहा है. आख़िर क्या वजह है कि शक की सुई उठने के बावजूद स्लीपर खरीद में हुई अनियमितताओं की सही तरीके से जांच नहीं हो रही है. सीबीआई दबाव में है, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि की राय है कि स्लीपर घोटाले की जांच की समय सीमा तय कर दी जाए और अगर सीबीआई जांच में आनाकानी कर रही है, तो किसी दूसरी एजेंसी से जांच करा ली जाए, लेकिन देश और जनता को ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में रखना ठीक नहीं है. तथ्यों को देखने से लगता है कि सीबीआई नीतीश कुमार को बचा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जंस्कार में बौद्ध-मुस्लिम विवाद

नफ़रत की खाई पाटना दूभर

ज़ंस्कार के हालात बताते हैं कि बौद्धों के मन में मुसलमानों के प्रति बैर भाव काफी बढ़ गया है. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार वहां अमन-चैन कायम करने के लिए शीघ्र ही ठोस और सख्त क़दम उठाए.

मोहम्मद हारून

जम्मू-कश्मीर में हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में समुद्री स्तर से 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ज़ंस्कार की 700 लोगों की आबादी इन दिनों ख़ौफ़ के माहौल में सांस ले रही है. यहां मुसलमान स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. दरअसल, उन्हें अपनी जान एवं माल का ख़तरा सता रहा है और यह ख़तरा उन्हें दुनिया के प्राचीन एवं शांति का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के हितैषियों से है. ज़ंस्कार के पिछड़े मुसलमानों पर ख़तरे के बादल पिछले एक साल से मंडरा रहे हैं. इसीलिए कश्मीरी मुसलमान ज़ंस्कार के मुसलमानों की किसी प्रकार से मदद नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि वे मीडिया द्वारा उनकी मदद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. श्रीनगर के उर्दू दैनिक कश्मीर उज़मा ने अपने 9 जुलाई के अंक में यहां की एक बड़ी धार्मिक जमात जमीअते अहल-ए-हदीस का बयान प्रकाशित किया. पदम ज़ंस्कार में मुसलमानों पर बौद्ध अनुयायियों के अत्याचार और उन्हें विभिन्न प्रकार से परेशान करने पर जमीअते अहल-ए-हदीस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये लोग मुसलमानों पर अत्याचार करके एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं, जिससे पूरे राज्य में नकारात्मक संदेश जाए. इस्लाम किसी भी अत्याचार के विरुद्ध है, लेकिन ज़ंस्कार में बौद्ध धर्म के समर्थकों ने जो रास्ता अपनाया है, वह बिल्कुल अनैतिक और अमानवीय है. अगर इससे शीघ्र ही न निबटा गया, तो इसके घातक नतीजों के लिए प्रशासन ज़िम्मेदार होगा. इससे पहले 7 जुलाई को एक अन्य मुस्लिम संगठन कारवां-ए-इस्लामी ने ज़ंस्कार में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध न्यायालय जाने की घोषणा की थी.

ग़ौरतलब है कि लद्दाख़ से कारगिल क्षेत्र से दूर ज़ंस्कार, जहां 15,000 बौद्धों के मुक़ाबले केवल 700 मुसलमान हैं, में मुसलमानों पर अत्याचार का सिलसिला पिछले साल सितंबर में उस समय शुरू हुआ, जब निचली जाति से संबंध रखने वाले बौद्धों के 6 परिवारों के 22 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया. इस पर कुछ स्थानीय बौद्ध भड़क गए और उन्होंने पिछड़े मुसलमानों पर हमला बोल दिया. मीडिया में छपी ख़बरों के अनुसार, बौद्धों ने कई मुसलमानों के घरों में न केवल आग लगा दी, बल्कि लूटपाट भी की. दर्जनों मुसलमान इस हमले में घायल हुए. दरअसल, बौद्धों का आरोप है कि मुसलमान बौद्धों को धर्म परिवर्तन के लिए न केवल उकसाते हैं, बल्कि विवश भी करते हैं, लेकिन ज़ंस्कार के मुसलमानों ने इसका खंडन किया है. उनका कहना है कि इस्लाम अपनाने वाले उक्त बौद्धों का संबंध निचली जाति से था, चूंकि उन्हें समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाने का निर्णय लिया. यह खंडन मुस्लिम एसोसिएशन ज़ंस्कार ने 23 सितंबर, 2012 को राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नासिर असलम वानी के नाम लिखे अपने पत्र में किया है. एसोसिएशन ने कहा कि निचली जाति से संबंध रखने वाले छह परिवारों ने ज़ंस्कार की जामा मस्जिद में आकर वहां मुसलमानों से कहा कि वे इस्लाम इसलिए अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समाज में तुच्छ समझा जाता है.

धर्म परिवर्तन की इस घटना पर न केवल ज़ंस्कार के कुछ बौद्धों ने मुसलमानों पर हमले किए, बल्कि इस घटना को लेकर राज्य से बाहर भी मुसलमानों के विरुद्ध दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई. 12 दिसंबर, 2012 को भाजपा सांसद तरुण विजय ने राज्यसभा में मुसलमानों पर आरोप लगाया कि वह ज़ंस्कार में बौद्ध धर्म के समर्थकों को ज़बरदस्ती इस्लाम अपनाने पर विवश कर रहे हैं, जिससे वहां हालात बिगड़ गए हैं. तरुण विजय ने यह भी कहा कि ज़ंस्कार में पुलिस बौद्धों को सुरक्षा देने में असफल रही है, जबकि सच्चाई यह है कि वहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने खुलेआम बौद्धों का साथ दिया. ऐसे में, हालात इतने ख़राब हो गए कि मुसलमानों ने पलायन की भी कोशिश की, लेकिन अंतिम समय में प्रशासन के एक अधिकारी ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन देकर ज़ंस्कार छोड़ने से रोका. बहरहाल, एक साल बीत जाने के बावजूद ज़ंस्कार के मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. यही नहीं, ज़ंस्कार में कुछ बौद्धों ने पिछड़े मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार भी कर रखा है. करगिल में सबसे बड़े धार्मिक संस्थान इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रबंधक आग़ा शेख़ मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी ने कहा कि फिलहाल बौद्धों की ओर से हमले बंद ज़रूर हो गए हैं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार के चलते मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. बौद्धों ने अस्पतालों में मुसलमानों के इलाज और दुकानों से उनकी खरीदारी पर भी रोक लगा दी है. घाटी में अधिकतर राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं-दल म्यांमार में मुसलमानों के विरुद्ध बौद्धों की बर्बरता और अत्याचार की हालिया घटना के बाद ज़ंस्कार मामले को लेकर चिंतित हैं. दुख्तरान-ए-मिल्लत की अध्यक्ष सैयदा आसिया अंदराबी ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर है, यानी एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य. यह म्यांमार नहीं है, जहां बौद्धों ने मुसलमानों पर अत्याचार किया. दरअसल, ज़ंस्कार के मुसलमान इसलिए निशाने पर हैं, क्योंकि वहां के स्थानीय बौद्ध जानते हैं कि इस क्षेत्र तक शासन की पहुंच मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है. म्यांमार की घटना के बाद ज़ंस्कार के मुसलमानों के लिए ख़तरा और बढ़ गया है. आसिया का आरोप है कि ज़ंस्कार में मुसलमानों के साथ पिछले एक साल से जो कुछ भी हो रहा है, उसे सरकार का संरक्षण हासिल है. उन्होंने पूछा कि मुसलमानों पर जानलेवा हमला करने और पूरी बस्ती जलाने वालों के ख़िलाफ़ एक भी मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया और किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दरअसल, सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि बौद्धों को नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस प्रकार अपना वोट बैंक खो देंगे. अगर सरकार चाहती, तो बौद्ध ज़ंस्कार में मुसलमानों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते.

मुस्लिम संगठन पैरवान-ए-विलायत के अध्यक्ष सिब्ते मोहम्मद शब्बी क़मी ने कहा कि म्यांमार में मुसलमानों पर बौद्धों के अत्याचार पर विश्व भर की मुस्लिम बिरादरी की ख़ामोशी ने ज़ंस्कार के बौद्धों का हौसला बढ़ाया है. जम्मू-कश्मीर एक ऐसा राज्य है, जो सांप्रदायिक सौहार्द्र को लेकर स्वयं में एक उदाहरण है. यहां ऐसी घटनाएं होना चिंता का विषय है. दरअसल, बिहार के बोध गया में हुए हालिया धमाकों को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश भी हालात को बिगाड़ने का काम कर सकती है. बोध गया के धमाकों की गूंज का कोई प्रभाव ज़ंस्कार में देखने को मिला हो या नहीं, लेकिन यह बात तो तय है कि इस घटना ने मुसलमानों और बौद्धों के बीच नफ़रत की खाई अधिक गहरी कर दी है. ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि ज़ंस्कार में सांप्रदायिक सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं, क्योंकि इस समय एक छोटी सी चिंगारी भी आग के शोलों में बदल सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वह रिपोर्ट को आगे बढ़ाए और कार्रवाई करे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन भला हो अलजज़ीरा चैनल का, कि यह रिपोर्ट उसके हाथ लग गई और उसने इस रिपोर्ट को प्रसारित करने के साथ ही अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया.

ऐबटाबाद रिपोर्ट

अमेरिकी और पाक सरकार की नई मुसीबत

ऐबटाबाद आयोग की रिपोर्ट को अलजज़ीरा चैनल ने टीवी एवं वेबसाइट पर जारी कर दिया है. सार्वजनिक होने से यह रिपोर्ट अमेरिकी और पाक सरकार के गले की अब फांस बन गई है. ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों सरकारें अपनी जनता और विश्व बिरादरी को क्या जवाब देती हैं.

वसीम अहमद

कुछ ही दिनों पहले एडवर्ड स्नोडेन ने इंटरनेट डाटा की अमेरिकी जासूसी का ख़ुलासा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था. ताजा मामले में ऐबटाबाद आयोग की रिपोर्ट को अलजज़ीरा चैनल ने टीवी एवं वेबसाइट पर जारी कर दिया है. रिपोर्ट के सार्वजनिक होने की वजह से पाकिस्तान सरकार के लिए नया सिर दर्द पैदा हो गया है. गौरतलब है कि उर्दू के महाकवि मोहम्मद इक़बाल के सुपुत्र एवं पाक उच्चतम न्यायालय के जज जावेद इक़बाल की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार की गई है. ऐबटाबाद पाकिस्तान में रावलपिंडी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ख़ूबसूरत शहर है. 2 मई, 2011 से पहले इस शहर को कम ही लोग जानते थे, लेकिन दो मई, 2011 की रात में अमेरिकी सैनिकों द्वारा ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने से यह शहर रातोंरात दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया. बड़ी बात यह है कि आयोग की रिपोर्ट में पाकिस्तानी सरकार की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है, क्योंकि तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी, प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी और सेना प्रमुख अश्फ़ाक़ परवेज़ कयानी तीनों का दावा था कि उन्हें ऐबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी, जबकि आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान ऐबटाबाद पर हमला करने वाले अमेरिकी हेलिकॉप्टरों के पायलट पाकिस्तानी रडारों के ठिकानों और रेंज से परिचित थे. हेलिकॉप्टरों को ऐबटाबाद से ज़मीनी सम्पर्क मिल रहा था. आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना बड़ा सैनिक ऑपरेशन पाकिस्तान की नाक के नीचे हो गया और वहां के प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी.

दरअसल, ऐबटाबाद ऑपरेशन को लेकर पाक सरकार का रवैया पहले से स्पष्ट नहीं था, इसलिए जनता में अनिश्चितताएं देखने को मिलीं. आख़िरकार घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक आयोग के गठन का निर्णय लिया गया, लेकिन समस्या यह थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? पाकिस्तान में कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मामला अमेरिकी ऑपरेशन, पाकिस्तानी नेताओं की भूमिका और अलक़ायदा के सरग़ना की मौत की तफ्तीश से जुड़ा था. अगर रिपोर्ट में सैनिक ऑपरेशन को ग़लत ठहराया जाता, तो अमेरिका के नाराज़, अगर पाकिस्तानी सेना के रवैये की आलोचना की जाती, तो पाक सरकार नाराज़ और अगर अलक़ायदा के ख़िलाफ़ कोई बात होती, तो ऐसे में पख़्तूनख़्वाह की जनता नाराज़ हो जाती. मतलब साफ है कि सच्चाई किसी भी रूप में सामने आती, तो एक वर्ग को नाराज़ होना ही था. दरअसल, इन दिनों पाकिस्तानी में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उनमें किसी एक की भी नाराज़गी बड़े ख़तरे की घंटी साबित हो सकती थी. हालांकि ऐसे समय में, जब कोई भी इस आयोग की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, तो जावेद इक़बाल ने हौसला दिखाते हुए न केवल आयोग की अध्यक्षता संभाली, बल्कि ख़ुद को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया. आयोग के सदस्यों में अब्बास ख़ान, अशरफ़ जहांगीर क़ाज़ी और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद जैसे लोग शामिल थे. उन्होंने पूरे मामले की छानबीन करके 336 पृष्ठों पर आधारित एक रिपोर्ट 4 जनवरी, 2013 को सरकार के समक्ष पेश कर दी.

रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वह रिपोर्ट को आगे बढ़ाए और कार्रवाई करे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. भला हो अलजज़ीरा चैनल का, कि यह रिपोर्ट उसके हाथ लग गई और उसने इस रिपोर्ट को प्रसारित करने के साथ ही अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया. रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद यह पता चला कि आयोग ने इस रिपोर्ट में न केवल अमेरिकी ऑपरेशन की तीखी आलोचना की है, बल्कि ऑपरेशन को लेकर अब पाक सरकार की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है. निश्चय ही यही कारण था कि इस रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश की गई. रिपोर्ट में ओसामा बिन लादेन की हत्या को ग़लत क़दम बताया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सैनिक लादेन को जीवित पकड़ सकते थे, लेकिन उसे मारना अमेरिका की प्राथमिकता थी, इसलिए अमेरिकी सैनिकों ने लादेन को मारने को तरजीह दी. रिपोर्ट में तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ़ ज़रदारी, प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी और सेना प्रमुख कयानी के उस दावे को, कि उन्हें इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था, पर भी उंगली उठाई गई है और कहा गया है कि इस गुनाह में कहीं न कहीं पाकिस्तानी सरकार भी शामिल है.

इस रिपोर्ट में एक अजीबोग़रीब बात कही गई है, जो यह बताती है कि अमेरिका कहीं भी मानवीय संवेदना की बुनियाद पर कुछ करता है, तो उसके पीछे उसका राजनीतिक स्वार्थ छिपा होता है, क्योंकि 2010 में जब पाकिस्तान में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, तो उस समय अमेरिका ने बाढ़ पीड़ितों की ख़ूब मदद की थी. उनकी देखभाल के लिए जगह-जगह कैम्प लगाए गए थे और आसमान से निगरानी भी की गई थी. उस समय ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ मानवीय संवेदना की बुनियाद पर हो रहा है, लेकिन ऐबटाबाद आयोग की रिपोर्ट में ख़ुलासा किया गया है कि यह सब जासूसी के उद्देश्य से किया गया था. दरअसल, आसमानी निगरानी के नाम पर पूरे ऐबटाबाद के रास्ते पर नज़र रखी जा रही थी, बल्कि पेड़-पौधों के कारण जिन रास्तों की पहचान में परेशानी होती थी, उन पेड़ों को राहत कार्य में बाधा के नाम पर काट दिया गया था और फिर उनके नक्शे को सुरक्षित कर लिया जाता था. इस प्रकार देखा जाए, तो 2010 में ही इस ऑपरेशन का रेखाचित्र तैयार हो गया था, जिसको 2011 में ऐबटाबाद में अंजाम दिया गया.

जस्टिस जावेद इक़बाल की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हलचल पैदा कर दी और ऐसे में लोगों के दिमाग में यह सवाल उठने लगा कि आख़िर देश के एक महत्वपूर्ण नेता ने राष्ट्र से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और अमेरिकी षड़यंत्रों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों की. हालांकि इस रिपोर्ट में भी कुछ ख़ामियां हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक था. मसलन रिपोर्ट में केवल इतना ही कहा गया है कि महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग ने राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा गिलानी या सेना प्रमुख के साथ मीटिंग की इच्छा की थी या नहीं. आयोग का कहना है कि इस बात की संभावना कम है कि अमेरीकियों ने इस मिशन के हवाले से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझेदारी न की हो. इस तर्क पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ऑपरेशन से पूर्व, यहां तक कि इस दौरान किसी भी समय पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का सम्पर्क न साधा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती थी और अमेरिकी सेना को नुक़सान उठाना भी पड़ सकता था.

आयोग का कहना है कि 2 मई की घटना में सशस्त्र सैनिक के साथ-साथ पाक वायुसेना की नाकामी को स्वीकार करने की बजाए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन केवल इस बात पर ज़ोर देते रहे कि यह एक ऐसे देश की ओर से धोखा है, जो पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त देश के ख़िलाफ़ साझेदार है.

आयोग ने यह सवाल उठाया है कि ऐबटाबाद में हेलिकॉप्टर के आने के बाद 90 मिनटों के बीच में एक हेलिकॉप्टर के टकराने से उसकी तबाही और धमाका हुआ, ऐसे में यह बात बहुत आश्चर्यजनक है कि किसी एक ने भी यह मामला मिलिट्री कमांडर तक नहीं पहुंचाया. हालांकि यह सब जानते हैं कि पाकिस्तानी हेलिकॉप्टर कभी-कभार ही रात के समय उड़ान भरते हैं, तो फिर वायुसेना प्रमुख को रात के समय ऐबटाबाद पर उड़ रहे हेलिकॉप्टरों के बारे में सीधे सूचना क्यों नहीं दी गई?

> **रिपोर्ट के अनुसार, पाक वायु सेना के कुछ लोगों में यह शंका थी कि अन्य कारणों से पाक वायुसेना ने जान-बूझकर अमेरिकी हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की. शायद इसलिए कि अमेरिका ने पाकिस्तानी नेतृत्व को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई हो.**

रिपोर्ट के अनुसार, पाक वायु सेना के कुछ लोगों में यह शंका भी थी कि अन्य कारणों से पाक वायुसेना ने जान-बूझकर अमेरिकी हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की. शायद इसलिए कि अमेरिका ने पाकिस्तानी नेतृत्व को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई हो.

आमतौर पर पाकिस्तानी अख़बारों में यह बात कही जा रही थी कि अमेरिका की ओर से यह चेतावनी दी गई है कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान किसी तरह रुकावट न बने, लेकिन आयोग की रिपोर्ट से इस बात का ख़ुलासा हो रहा है कि यह सब महज़ अफ़वाह थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात का कोई पुख़्ता सबूत पेश नहीं किया जा सका है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी हो कि इस कार्रवाई के दौरान या इससे पूर्व किसी प्रकार का ख़तरा न हो.

रिपोर्ट में ओसामा बिन लादेन की पत्नी अमन सादिया के बयान भी शामिल हैं. अमन सादिया को ऑपरेशन के समय उनके पांव में गोली मारी गई थी. रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि ऐबटाबाद ऑपरेशन पूरा करने के बाद अमेरिकी सेल कमांडोज़ ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से सोने और जवाहरात से भरा डिब्बा और ओसामा की वसीयत भी अपने साथ ले गए.

आयोग की रिपोर्ट में पाकिस्तानी नेताओं के उस बयान को संदिग्ध रखा गया है कि इस ऑपरेशन के सिलसिले में उन्हें ख़बर नहीं दी गई. अब अगर उनकी बातों को सही मान लिया जाए, तो फिर सवाल यह भी पैदा होता है कि

पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी क्या कर रही थी? क्या यह संभव है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड व्यक्ति ऐबटाबाद में एक मकान के अंदर अपने परिवार के साथ कई सालों से छिपा हो और सरकार को इसकी भनक तक न हो. अगर यह सच था, तो यह पाकिस्तानी इंटेलीजेंस और ख़ुफ़िया विभागों की नाकामी का बेहतरीन सबूत है और इस प्रकार के अमल की जिम्मेदारी किसी संस्था या व्यक्ति को स्वीकार करनी ही चाहिए.

इन दिनों यह सवाल भी उठने लगा है कि आख़िर इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट अलजज़ीरा के हाथ कैसे लगी. पाकिस्तान के सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी सफ़ाई में लगे हुए हैं. प्रसारण मंत्री परवेज़ रशीद सफ़ाई देते हुए कहते हैं कि ऐबटाबाद आयोग रिपोर्ट प्रधानमंत्री निवास से लीक नहीं हुई. ऐबटाबाद आयोग की असल रिपोर्ट सरकार के पास सुरक्षित है. केन्द्रीय मंत्री का कहना है कि कमेटी क़ानून मंत्री, विदेशी मंत्री और रक्षा मंत्री पर आधारित है. किसी भी संबंधित व्यक्ति की पहुंच रिपोर्ट तक नहीं हो सकती. पाकिस्तानी मंत्रियों के इन बयानों से तो लगता यही है कि विकीलीक्स की तरह ही कोई है, जो पाकिस्तान की ख़ुफ़िया फ़ाइलों तक घुसपैठ कर रहा है और इसी ने ऐबटाबाद की इस महत्वपूर्ण घटना को अलजज़ीरा के हवाले किया है. और अगर ऐसा है, तो बड़े शर्म की बात यह है कि कोई आकर इस देश के अन्दर ऑपरेशन करता है और प्रशासन को पता तक नहीं चलता.

जस्टिस जावेद इक़बाल के आयोग की रिपोर्ट से जहां एक ओर पाकिस्तानी तंत्र सवालों के घेरे में आ गई है, वहीं अमेरिका के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो गई है कि वह जहां भी मानवीय संवेदना की बुनियाद पर कुछ करता है, तो उसके पीछे उसका राजनीतिक स्वार्थ छिपा होता है. इस प्रकार ऐबटाबाद आयोग रिपोर्ट अमेरिका और पाकिस्तानी दोनों के लिए मुसीबत बन गई है. ■

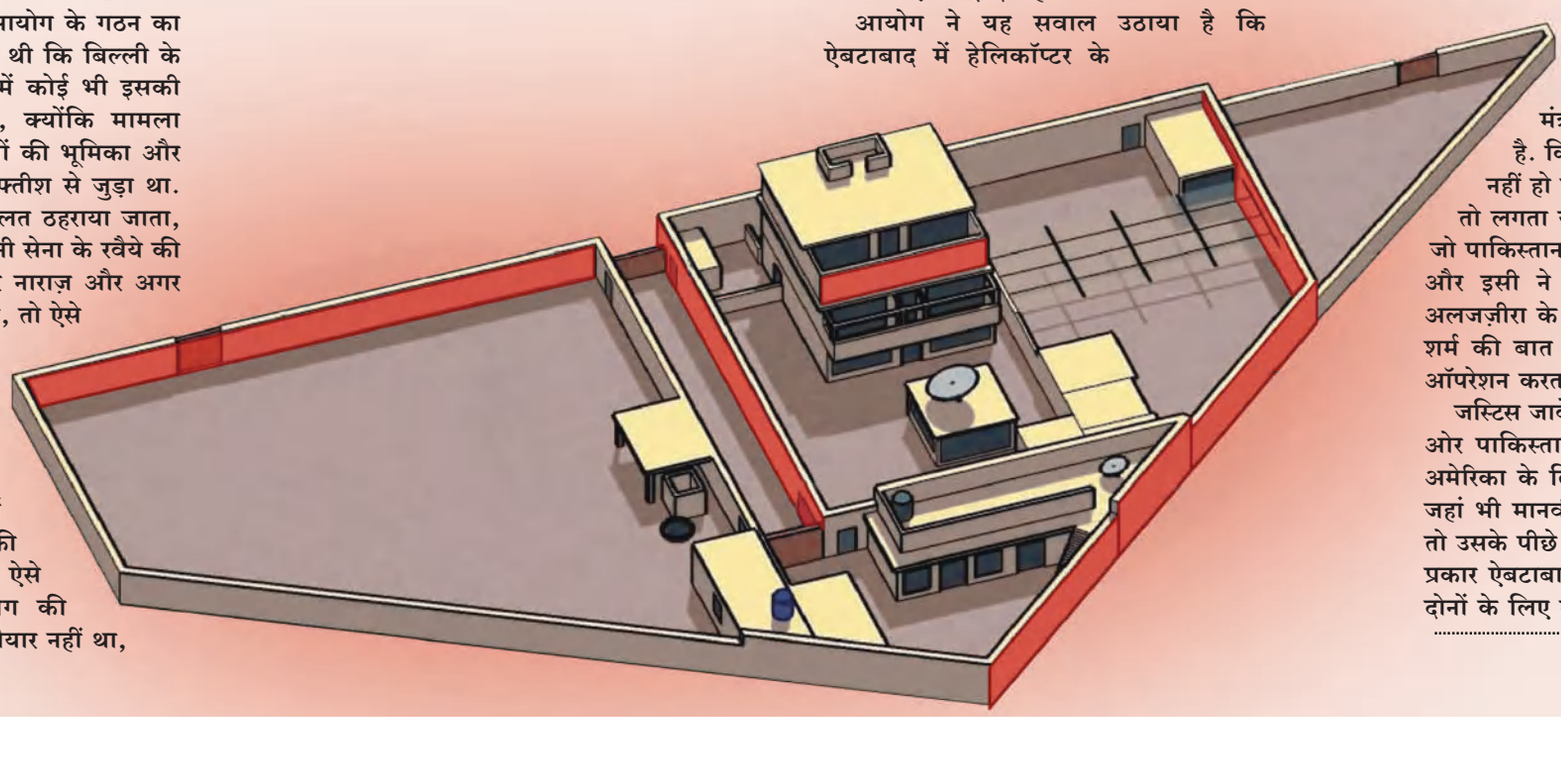

feedback@chauthiduniya.com

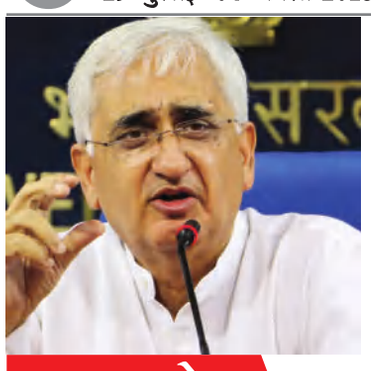

मुसलमानों को लुभाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जगह–जगह अल्पसंख्यक सम्मेलन भी करा रही है, जिसकी शुरुआत 15 जून को वाराणसी से हो चुकी है. यह सिलसिला लखनऊ में 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की 126वीं जयंती के मौक़े पर ख़त्म होगा, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है. इन सम्मेलनों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं पर राज्य सरकार किस तरह पानी फेर रही है.

उत्तर प्रदेश

मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस की कसरत

उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस जहां केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं के सहारे अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं सपा उस पर मुसलमानों की उपेक्षा करने और अब उन्हें बरगलाने की कोशिश का आरोप लगा रही है.

अजय कुमार

सूबे में 18.49 प्रतिशत मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए हाथ–पैर मार रही कांग्रेस के सामने सपा रोड़ा बनकर खड़ी है. पहले तीन बार मुलायम सिंह और फिर 2012 में मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले अखिलेश यादव का हाथ मुसलमानों ने मजबूती के साथ पकड़ रखा है. कांग्रेस मुसलमानों के सपा प्रेम से हतप्रभ है, क्योंकि न तो केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं काम आ रही हैं और न ही मुसलमानों को सपा से दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सपा नेता (अब कांग्रेसी) बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल जैसे नेताओं द्वारा मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे शब्द–बाण निशाने पर बैठ रहे हैं. दरअसल, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सपा–भाजपा को एक ही थाली के चट्टे–बट्टे बताकर मुसलमानों के दिल से मुलायम सिंह के प्रति उनका प्रेम निकाल फेंका जाए. इसीलिए मुलायम सिंह के, आडवाणी कभी झूठ नहीं बोलते, जैसे बयानों को कांग्रेसी खूब हवा देते रहते हैं. वरुण गांधी के अदालत से बरी होने और सपा सरकार द्वारा उसके ख़िलाफ़ उच्च अदालत में जाने में देरी को भी अब मुद्दा बनाया जा रहा है. जेल में बंद बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई के मामले में सपा सरकार ने जिस तरह ढुलमुल रवैया अपनाया है, उसे लेकर भी कांग्रेस सपा और राज्य सरकार पर निशाना साध रही है. सपा की सरकार बनने पर मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण के वादे की याद भी दिलाई जा रही है. मकसद है, मुसलमानों के मन में सपा के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा करना.

दरअसल, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बिना कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की जंग जीतना आसान नहीं होगा. इस बात का आभास उसे विधानसभा चुनाव में हो भी चुका है. लोकसभा चुनाव 2009 में जब कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोट पड़े थे, तो उसे 22 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को मुस्लिम मतों की मदद से बड़ी कामयाबी मिली, नतीजतन उसका न केवल मत प्रतिशत बढ़ा, बल्कि सीटों में भी इजाफा हुआ. कांग्रेस सूबे में सपा एवं बसपा के समकक्ष आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन वह अपनी यह कामयाबी संभाल नहीं सकी. उसने सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के सहारे मुसलमानों को छोड़ दिया. खुर्शीद भले ही यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री बने हों, लेकिन आम मुसलमान उन्हें कभी अपना नहीं मान सके, क्योंकि खुर्शीद की बयानबाजी अक्सर मुसीबत बन जाती है. ग़ौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को अलग से साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण संबंधी बयान उनके लिए सिरदर्द बन गया. ऐसे में यह आम राय उभर कर सामने आई कि मुस्लिम मतों के सपा के पक्ष में एकजुट हो जाने से कांग्रेस का मिशन 2012 परवान नहीं चढ़ सका.

इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं के सहारे मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कम कर दी. अब वह अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अनाप–शनाप एवं आधी–अधूरी, लेकिन लुभावनी योजनाएं बनाकर मुसलमानों पर डोरे डाल रही है. कांग्रेस यह बात भी शिद्दत से महसूस करती है कि विधानसभा चुनाव में मुसलमानों द्वारा सपा के पक्ष में थोक के भाव मतदान करने से उसकी हालत पतली हुई है. वहीं कांग्रेस नेता इस बात को भी अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं कि सपा ने मुसलमानों के लिए कांग्रेस के मुकाबले कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके बात बहादुर नेताओं ने अपने पक्ष में फिजा बना दी. कुछ कांग्रेसी दबी जुबान से यह भी कहते हैं कि 2009 से लेकर 2012 तक केंद्र की कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे लगता कि वह मुसलमानों के प्रति चिंतित है. कांग्रेस के नेता मुसलमानों को आरक्षण, सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र आयोग में फंसाए रहे, तो दिल्ली के बाटला हाउस कांड पर दिग्विजय सिंह की सियासत ने कांग्रेस को पूरी तरह धो डाला. कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से दिग्गी राजा की विदाई के पीछे उनके बेतुके बयान ही थे. बहरहाल, इन दिनों कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत सपा को कठघरे में खड़ा करने के लिए लगा रखी है और अपने कद्दावर मुस्लिम नेताओं, जैसे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रहमान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सांसद जफर अली नकवी, रशीद मसूद को मैदान में एक्शन प्लान के तहत उतार दिया है.

मुसलमानों को लुभाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जगह–जगह अल्पसंख्यक सम्मेलन भी करा रही है, जिसकी शुरुआत 15 जून को वाराणसी से हो चुकी है. यह सिलसिला लखनऊ में 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की 126वीं जयंती के मौक़े पर ख़त्म होगा, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है. इन सम्मेलनों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं पर राज्य सरकार किस तरह पानी फेर रही है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं बनाई ज़रूर हैं, लेकिन उनका लाभ उत्तर प्रदेश में उन्हें नहीं मिल रहा है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश की सपा सरकार के सामने मुस्लिम हितों से जुड़ी कुछ ऐसी मांगें भी रख सकती है, जिन्हें पूरा करने के लिए उसे लंबी शासकीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. मसलन, वह अखिलेश सरकार से कहेगी कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में दो मुस्लिम सिपाहियों के अलावा, आबादी के अनुरूप मुस्लिम वर्ग के थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए जाएं. यह मांग भी उठाई जाएगी कि राज्य सरकार उर्दू को अनिवार्य भाषा का दर्जा दे और बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में 24 घंटे मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाए.

कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विभाग के चेयरमैन मारूफ खां कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बुनकरों के उत्थान के लिए 4000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया, जिसकी बंदरबांट हो गई. सवा साल की सपाई हुकूमत में 27 दंगे हुए और अधिकांश इलाकों में मुसलमानों को ही

अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम

केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तय किए हैं, जिसे नाम दिया गया है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम. इसके तहत एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयीन शिक्षा उपलब्धता में सुधार, उर्दू शिक्षा के लिए अधिक संसाधन जुटाना, मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को छात्रवृति, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधो–संरचना उन्नत करना, ग़रीबों के लिए स्वरोज़गार एवं मज़दूरी रोज़–गार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल को बढ़ावा, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण की व्यवस्था, राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए ज़रूरी क़दम उठाना, ग्रामीण आवास योजना में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों की स्थिति सुधारना, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अलग से न्यायालय स्थापित करना और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था आदि कार्य अंजाम दिए जाएंगे.

हम मुस्लिम हितैषी, बाकी सब दुश्मन

राजनीतिक दल अपना वोटबैंक बचाने के लिए साम–दाम–दंड–भेद आदि सभी नुस्खे आजमाते हैं. मतदाताओं को लुभाने के लिए बेतुके बयान भी दिए जाते हैं. विरोधियों पर दोषारोपण और आरोप–प्रत्यारोप का दौर चलता है. कई बार वोटबैंक की राजनीति दो सरकारों के बीच टकराव भी पैदा कर देती है. इसी के चलते आम जनता के हितों से जुड़ी योजनाएं औधे मुंह गिर जाती हैं. अब अल्पसंख्यकों से जुड़ी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को ही लीजिए, जिनका उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के चलते बुरा हश्र हो रहा है. सपा नहीं चाहती कि कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द होने का श्रेय ले जाए, इसलिए अखिलेश सरकार उसके सभी कामों में चालाकी के साथ रोड़े अटका कर अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस, सपा एवं बसपा को बराबर का गुनहगार मानते हैं. वह कहते हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों ही मुसलमानों की तरक्की पसंद नहीं करती हैं. मुसलमानों को भाजपा का हौव्वा दिखाकर उनके वोट हासिल किए जाते हैं. क्या सरकारों को जाति एवं मजहब के आधार पर काम करना चाहिए? पहले कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी का निर्माण, फिर हमारी बेटी–उसका कल का नारा, लेकिन उसकी जगह केवल अल्पसंख्यक बेटी को सहायता! बेटी तो एक समान है, वह हिंदू हो या मुसलमान. फिर यह विभेद क्यों? सरकारें वोटों के लालच में आतंकवादी घटनाओं के आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है और उनके मुकदमे वापस लिए जाते हैं, लेकिन भला हो अदालत का, जिसने ऐसा करने से रोक दिया. पाठक कहते हैं कि कांग्रेस कई समस्याओं की जड़ है. दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहना दुर्भाग्यपूर्ण है. पाठक कहते हैं कि भाजपा दूध का दूध–पानी का पानी करने के लिए विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रही है, ताकि मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों की हकीकत सबको मालूम हो सके. बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या कहते हैं कि हमारे राज में दंगे नहीं हुए, जबकि सपा सरकार दंगों की राजनीति में खूब नाम कमा रही है. साल–सवा साल में हुए दर्जनों दंगे इस बात के प्रमाण हैं. सपा ने सत्ता में आने पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन अब चुप्पी साधे हुए है. सपा कहती थी कि अगर उसकी सरकार बनी, तो वह केंद्र पर रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए दबाव डालेगी और जो सिफारिशें राज्य सरकार के जरिए लागू हो सकती हैं, उन्हें प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन वह इसमें भी नाकाम रही.

–संजय सक्सेना

वादे हम पूरे कर रहे हैं : अखिलेश

सपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी पार्टी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के जो 16 वादे किए थे, उन्हें पूरा किया जा रहा है. पहला, रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालना है. हम लगातार केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं और संसद में भी यह मुद्दा उठा रहे हैं. केंद्र सरकार जो भी सिफारिशें लागू करेगी, उसे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाएगा. दूसरा वादा, सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में मुसलमानों को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण देना है. यह तभी संभव है, जब केंद्र सच्चर कमेटी की संस्तुतियां लागू करे. तीसरा वादा था, मुस्लिम बाहुल्य ज़िलों में सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का. इस बाबत प्रदेश के 13 ज़िलों में काम हो रहा है, अन्य ज़िलों में शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा. इसी तरह जेल में बंद बेकसूर मुस्लिम नौज़वानों की रिहाई, दोषी अधिकारियों को दंडित करने, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में प्राइमरी, मिडिल एवं हाईस्कूल स्तर पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की स्थापना का काम किया जा रहा है. मदरसों में तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है. पीएसी एवं अन्य राजकीय सुरक्षा बलों में मुसलमानों की भर्ती का विशेष प्रावधान किया गया है. कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे रोकने और उनकी चाहरदीवारी के लिए बजट में विशेष व्यवस्था की गई है. कक्षा दस उत्तीर्ण मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा अथवा विवाह के लिए तीस हज़ार रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है. यही नहीं, 2013–14 के बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 26 अरब 86 करोड़ 77 लाख 71 हज़ार रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग, आईएएस/पीसीएस कोचिंग संस्थान की स्थापना, ग़रीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान, मदरसों में मिनी आईटीआई, अरबी–फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान आदि योजनाएं शामिल हैं.

–दर्शन शर्मा

उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उन्हें जान–माल, दोनों का नुक़सान हुआ. कारोबार बंद रहने से बच्चे भूखे मरने लगे. यही वजह है कि सपा राज में मुस्लिम समाज अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है. मारूफ कहते हैं कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए गठित कमीशन एवं कमेटियों का सूबे में वजूद न होना चिंता का विषय है. मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी एवं उर्दू अकादमी के गठन में देरी को भी मुद्दा बनाया जाएगा. मारूफ कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की तरक्की पसंद पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी उनकी भावनाएं भड़काने का काम करती है. मुलायम सिंह सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात बार–बार केंद्र से कहते हैं, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई पता होती, तो वह ऐसा न बोलते. सच्चर कमेटी ने अल्पसंख्यकों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए 76 सिफारिशें सरकार से की थीं, जिनमें से 69 सिफारिशों को केंद्र सरकार ने न सिर्फ़ मंजूरी दी, बल्कि उनमें से 66 सिफारिशों पर काम भी शुरू कर दिया है. मात्र सात सिफारिशें इसलिए नहीं मानी जा सकीं, क्योंकि उनमें संवैधानिक संकट आड़े आ रहा था.

कांग्रेस नेता सिराज मेहंदी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश में क़रीब 1100 करोड़ रुपये भेजे थे, लेकिन अब तक 70 फ़ीसद रकम ही खर्च हो सकी है. कई योजनाएं अल्पसंख्यकों तक पहुंच ही नहीं सकी हैं. केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों की योजनाएं ज़िलों तक न पहुंचने से निराश है. इसलिए जल्दी ही अल्पसंख्यक मंत्रालय स्वयंसेवी एवं ग़ैर–सरकारी लोगों की एक कमेटी बनाने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के ज़िलों के लोग भी शमिल होंगे. यह कमेटी सभी 75 ज़िलों में बनाई जाएगी, जो अपने यहां भेजी जाने वाली छात्रवृत्ति, स्किल डेवलपमेंट एवं आंगनबाड़ी कार्यक्रमों पर नज़र रखेगी. इतना ही नहीं, केंद्र की पहल पर उसकी विभिन्न योजनाओं की 15 प्रतिशत धनराशि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के विकास में खर्च की जा रही है.

कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम ने समाजवादी पार्टी को चौकन्ना कर दिया है. आजम खां अब भाजपा से अधिक कांग्रेस पर बरसते हैं. सपा प्रवक्ता एवं मंत्री राजेंद्र चौधरी भी हर समय कांग्रेस से दो–दो हाथ करने में लगे रहते हैं. चौधरी को लगता है कि लोकसभा चुनाव का मौसम आया, तो बसपा, कांग्रेस एवं भाजपा जातीयता और सांप्रदायिकता की राजनीति को हवा देने में लग गई हैं. खुद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर बताई. रंगनाथ मिश्र आयोग भी उसने ही गठित किया था, लेकिन उसकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गईं. उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जब संसद में इस बारे में सवाल उठाए, तो प्रधानमंत्री तक जवाब टाल गए. मुसलमानों की घोर उपेक्षा करने वाले और बाबरी मस्जिद ध्वंस में भाजपा के सहयोगी रहे कांग्रेस नेता अब उन्हें बरगलाने के काम में लग गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सतनाम सिंह छाबड़ा कहते हैं कि हर किसी को सिरदर्द की समस्या कभी न कभी होती ही है, जिसमें कुछ तो सामान्य होती है, तो कुछ किसी भयंकर बीमारी को आमंत्रण दे रही होती है. ऐसे में सावधानी से इलाज कराने में ही समझदारी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, आज पूरी दुनिया में क़रीब 40 प्रतिशत आबादी गंभीर सिरदर्द से ग्रस्त है. सिरदर्द में सबसे कॉमन माइग्रेन होता है, जिसे सामान्य भाषा में अर्द्धकपारी का दर्द भी कहा जाता है.

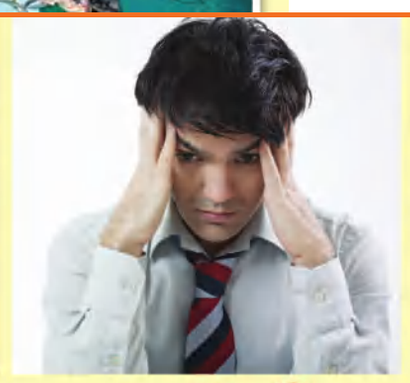

हल्के में न लें, नियमित सिरदर्द

कहीं माइग्रेन तो नहीं...

बहुत से लोगों में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या टेंशन से होने वाला सिरदर्द पाया जाता है, जिसमें उपचार की ज़रूरत नहीं होती, यद्यपि इसकी दवाइयां उपलब्ध हैं, जो सिरदर्द कम कर सकती हैं. बच्चों को भी माइग्रेन होता है. माइग्रेन साधारणतया सिर एवं गर्दन में हल्के दर्द के साथ शुरू होता है और बढ़ते–बढ़ते सिर के एक बड़े हिस्से में पहुंच जाता है. सामान्यतया यह कुछ घंटों में दूर हो जाता है.

नियमित सिरदर्द होना किसी ख़तरे से कम नहीं है, क्योंकि यह माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारी को जन्म दे सकता है. इसलिए जब भी कभी ऐसा हो, तो डॉक्टरी जांच के बाद उचित इलाज कराना बहुत ज़रूरी है. क्यों और कैसे होती है यह बीमारी तथा इसके उपचार क्या हैं, पढ़िए इस आलेख में.

अर्चना तिवारी

पूजा को आएदिन सिरदर्द होता था. सूरज की किरणों के साथ उसका सिरदर्द तेज होता जाता और शाम ढलते ही उसे थोड़ा आराम मिल जाता. इस समस्या से वह कुछ महीने से जूझ रही थी. एक दिन उसने अपनी सिरदर्द की समस्या अपनी दोस्त काजल को बताई, तो उसने उसे डॉक्टरी सलाह लेने की बात कही. डॉक्टरी जांच से यह बात सामने आई कि पूजा को माइग्रेन जैसी समस्या है. इस बीमारी का नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया कि समाज में माइग्रेन को लेकर कई भ्रांतियां हैं, इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तुम उपचार कराओ, यह समस्या पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो सकती है. पूजा ने ऐसा ही किया और अब वह क़रीब छह महीने बाद पूरी तरह माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पा गई.

सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सतनाम सिंह छाबड़ा कहते हैं कि हर किसी को सिरदर्द की समस्या कभी न कभी होती ही है, जिसमें कुछ तो सामान्य होती है, तो कुछ किसी भयंकर बीमारी को आमंत्रण दे रही होती है. ऐसे में सावधानी से इलाज कराने में ही समझदारी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, आज पूरी दुनिया में क़रीब 40 प्रतिशत आबादी गंभीर सिरदर्द से ग्रस्त है. सिरदर्द में सबसे कॉमन माइग्रेन होता है, जिसे सामान्य भाषा में अर्द्धकपारी का दर्द भी कहा जाता है. इसमें सिर के आधे हिस्से में बहुत ही तेज दर्द होता है. पुरुषों की तुलना में माइग्रेन की शिकार महिलाएं अधिक होती हैं. कुछ हद तक यह तनाव के कारण भी होता है. अध्ययन बताते हैं कि चार में से एक महिला को माइग्रेन की समस्या होती ही है, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं पेनकिलर लेकर इस रोग को कल के सहारे छोड़ देती हैं.

कारण: सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं. माइग्रेन के प्रमुख कारणों में तनाव, लगातार कई दिनों तक नींद पूरी न होना, हार्मोनल चेंजेस, शारीरिक थकान, चमचमाती रोशनी, तेज धूप, कब्ज, नशीली दवाओं का सेवन, मौसम में बदलाव, कॉफी–टॉफी– चॉकलेट का अत्यधिक सेवन, किसी प्रकार की गंध, सिगरेट का धुआं आदि हैं. इसके अलावा बाज़ार में मिल रहे डिब्बाबंद पदार्थ जैसे पनीर, चीज, नट्स में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जो माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं.

किन्हें है माइग्रेन का ख़तरा

वैसे तो देखा यही गया है कि बीस से चालीस साल के लोगों में माइग्रेन की शिकायत ज़्यादा होती है. माना जाता है कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों को सुकून के दो पल भी नहीं मिलते. इसलिए तनाव और थकान होना लाजिमी है. ऐसे में माइग्रेन भी लोगों पर हावी हो जाता है. कुछ हद तक मोटी तोंद और कमर वालों को भी यह समस्या होती है. इसके अलावा, प्रतियोगिता के इस दौर में हम आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते है, जिससे काफी तनाव रहता है. शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से गुजरने वालों को भी माइग्रेन की समस्या परेशान करती है.

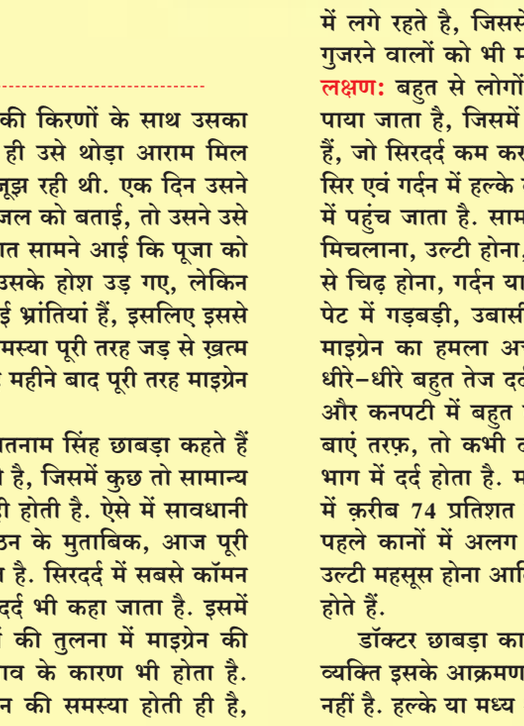

लक्षण: बहुत से लोगों में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या टेंशन से होने वाला सिरदर्द पाया जाता है, जिसमें उपचार की ज़रूरत नहीं होती, यद्यपि इसकी दवाइयां उपलब्ध हैं, जो सिरदर्द कम कर सकती हैं. बच्चों को भी माइग्रेन होता है. माइग्रेन साधारणतया सिर एवं गर्दन में हल्के दर्द के साथ शुरू होता है और बढ़ते–बढ़ते सिर के एक बड़े हिस्से में पहुंच जाता है. सामान्यतया यह कुछ घंटों में दूर हो जाता है. इसके लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी होना, रोशनी देखकर घबराहट होना, शोर या किसी प्रकार की खुशबू से चिढ़ होना, गर्दन या कंधे में दर्द या उन्हें मोड़ने में दर्द होना, दृष्टि संबंधी समस्याएं, पेट में गड़बड़ी, उबासी लेने में दबाव, मुंह सूखना, कंपकंपी उठना आदि प्रमुख हैं. माइग्रेन का हमला अचानक होता है. कई बार यह शुरू में हल्का होता है, लेकिन धीरे–धीरे बहुत तेज दर्द में बदल जाता है. अधिकतर यह सिरदर्द के साथ शुरू होता है और कनपटी में बहुत तीव्रता से टीस के साथ उठता है. कभी–कभी यह दर्द सिर के बाएं तरफ़, तो कभी दाएं तरफ़ होता है. क़रीब 90 प्रतिशत मरीजों को सिर के बाएं भाग में दर्द होता है. माइग्रेन का दर्द चार से 72 घंटे तक रह सकता है. इसके मरीजों में क़रीब 74 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. कुछ लोगों में माइग्रेन का दर्द शुरू होने से पहले कानों में अलग तरह की आवाज़ सुनाई देना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, उल्टी महसूस होना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं. माइग्रेन के ज़्यादातर रोगी वंशानुगत होते हैं.

डॉक्टर छाबड़ा का कहना है कि इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है. संभव है कि व्यक्ति इसके आक्रमण को पहचान कर राहत पाने की कोशिश करे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. हल्के या मध्य श्रेणी के सिरदर्द में पैरासिटामोल आदि का इस्तेमाल करके राहत पा सकते हैं. उपचार की शुरुआत में डॉक्टर जीवनशैली में बदलाव, पर्याप्त नींद लेने, व्यायाम, माइग्रेन के लक्षण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश और अन्य आरामदायक तकनीकों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. माइग्रेन से राहत पाने के लिए दवाइयों का सेवन करने की सलाह तब दी जाती है, जब यदि इसके आक्रमण के लक्षणों को नकारा न जा सके और महीने में दो से अधिक बार माइग्रेन का दर्द उत्पन्न होता रहे. माइग्रेन के आक्रमण के लिए माहवारी भी एक महत्वपूर्ण कारण है.

एलोपैथिक उपचार: माइग्रेन में पेनकिलर के साथ कुछ अन्य दवाइयां प्रयोग की जाती हैं. डॉक्टरी सलाह पर जीवनशैली अपनाने वालों की माइग्रेन की समस्या ख़त्म हो जाती है. भीषण दर्द होने पर दो प्रकार की दवाएं काफी प्रभावकारी होती हैं, जिन्हें हमेशा साथ रखना चाहिए. पहली, कैफीन रहित गोलियां जैसे नैप्रा–डी, नैक्सडॉम और मेफ्टलफोर्ट. दूसरी ट्रिप्टान दवाएं, जैसे सुमिनेट टैबलेट, नैसाल स्प्रे या इंजेक्शन. ट्रिप्टान दवाएं तब दी जाती हैं, जबकि माइग्रेन पर आम पेनकिलर्स का कोई असर नहीं होता. शोध से पता चला है कि भीषण दर्द में ट्रिप्टान दवाएं अधिक कारगर होती हैं, जिनका सेवन डॉक्टर की सलाह एवं मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए.

होम्योपैथिक उपचार: होम्योपैथिक में माइग्रेन का अचूक इलाज है. जाने–माने होम्योपैथिक फिजीशियन ऐंड कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज अग्रवाल का कहना है कि अगर डॉक्टरी सलाह पर नियमित रूप से इलाज किया जाए, तो माइग्रेन जड़ से ख़त्म हो सकता है. यह कुछ हद तक आनुवंशिकी होता है और कुछ तनाव के कारण. महिलाएं घर और दफ्तर की दोहरी ज़िम्मेदारियां निभाती हैं, ऐसे में तनाव उन्हें जल्दी घेर लेता है और वे धीरे–धीरे माइग्रेन की चपेट में आ जाती हैं. होम्योपैथिक में ब्रायोनिया, बैलाडोना एवं ग्लोनाइन आदि दवाओं का असर काफी अच्छा देखा गया. इसके सेवन से यह रोग छह महीने में लगभग पूरी तरह ठीक हो जाता है. लेकिन दवाइयों की मात्रा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए.

घरेलू उपचार: अगर सिरदर्द और गर्दन दर्द होने पर किसी खुशबू वाले तेल से मालिश की जाए, तो दर्द में कुछ हद तक आराम मिल सकता है. अगर सिर में तेज दर्द है, तो एक तौलिए को गर्म पानी और दूसरे को ठंडे पानी में निचोड़ कर एक के बाद एक करके सिर पर रखने से दर्द में आराम मिलता है. डॉ. नीरज अग्रवाल का कहना है कि माइग्रेन या तो आनुवांशिकी होता है या फिर वातावरण परिदृश्य के कारण. जब तेज धूप सिर पर सीधे पड़ती है, तो माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती है. जब तेज हवाएं सीधे सिर पर लगती हैं, तो भी इसकी आशंका ज़्यादा होती है. ऐसे प्रदेश, जहां तेज गर्मी और तेज ठंड होती है, वहां इसकी समस्या ज़्यादा होती है. वह कहते हैं कि आप जिस माहौल में रहेंगे, उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही. तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को माइग्रेन की समस्या ज़्यादा होती है. आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में न तो आराम है और न ही चैन. ऐसे में माइग्रेन जैसी समस्याएं अपना असर तेजी से दिखाती हैं. हमेशा परेशान रहना, मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों में जीना माइग्रेन को आमंत्रण देता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सावधानियां

- माइग्रेन कुछ हद तक आनुवांशिकी होता है, अत: इसकी पहचान कर इलाज समय रहते ही शुरू कर दें.
- कुछ मामलों में माइग्रेन की समस्या किसी खास खुशबू से होती है, ऐसे में उससे खुद को बचाकर रखें.
- नींद पूरी लें.
- तनाव से बचने की कोशिश करें.
- तेज धूप, ठंडी हवा से बचकर रहें.
- जीवनशैली सामान्य बनाने की कोशिश करें.
- डिब्बाबंद सामान, जैसे पनीर, चीज, चॉकलेट के सेवन से परहेज करें.
- तनाव से बचने के लिए योग एवं व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है.
- नियमित सिरदर्द की तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं, अन्यथा यह किसी भयंकर बीमारी को आमंत्रित कर सकता है, क्योंकि सिर संबंधी बीमारियों में शुरुआती दौर में सिरदर्द का लक्षण ही सामने आता है.

माइग्रेन के प्रकार

- सामान्य माइग्रेन: यह माइग्रेन फोनोफोबिया और फोटोफोबिया के साथ होता है.
- क्लासिक माइग्रेन: इसमें विभिन्न वस्तुएं चमकीली दिखाई पड़ती हैं. टेढ़े–मेढ़े स्वरूप में चटख, रंगीन, चमचमाती रोशनियां दिखाई पड़ती हैं या दृष्टि क्षेत्र में एक छिद्र दिखाई पड़ता है, जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं.
- जटिल माइग्रेन: यह मस्तिष्क के ठीक से काम न करने के कारण होता है.

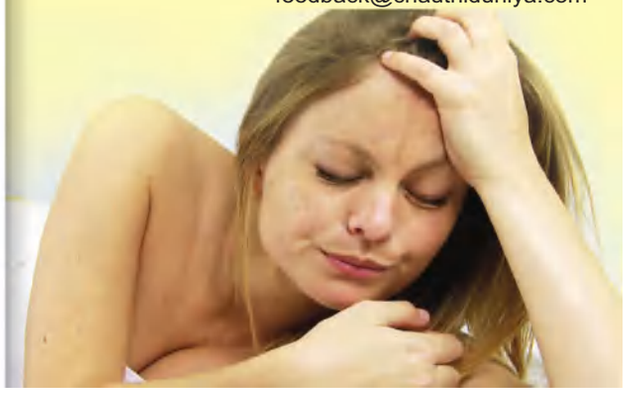

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

यह देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ है या नहीं? क्या हमने अपना संयम खो दिया है? क्या कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में होने के कारण वह भ्रष्टाचार को जारी रखेगी, फिर चाहे उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) कठघरे में खड़ा करे, या सुप्रीम कोर्ट?

सोच बदलें राजनीतिक दल

जरूरत है कि संसद का एक दिन निर्धारित हो और उस दिन सिर्फ संविधान में कही गई मूल बातों पर बहस हो और उस बहस का कोई निष्कर्ष निकले.

संसद का मानसून सत्र 5 अगस्त से शुरू होगा. दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस संसद सत्र के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस मानसून सत्र में सरकार लंबित विधेयकों को पारित कराना चाहेगी. विभिन्न मुद्दों को लेकर पिछले कुछ सत्रों में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते आ रहे प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए. यह खराब रणनीति मानी जाएगी. सभी विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए और उन्हें आवश्यक संशोधनों या बिना संशोधनों के पारित किया जाना चाहिए. यही लोकतंत्र है. सिर्फ बहुमत नहीं है, इसलिए बिल में बाधा डालना और उसे लटकाए रखना अच्छी बात नहीं है. खासकर तब, जब कई राज्यों में चुनाव है. इससे लोगों में यही संदेश जाएगा कि उनका नेतृत्व गलत हाथों में है. खाद्य सुरक्षा विधेयक भी अब संसद के समक्ष आएगा, जिस पर अध्यादेश आने के बाद पहले ही काफी हो–हल्ला हो चुका है.

इससे पहले कि यह कानून का रूप ले, न सिर्फ भाजपा, बल्कि अन्य दलों को भी खाद्य सुरक्षा अध्यादेश में आवश्यक बदलाव के लिए सकारात्मक सुझाव देना चाहिए. इस विधेयक का पारित होना लगभग तय है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसे विधेयक का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती, जो गरीबों को रियायती दर पर भोजन देने जा रहा हो. नि:संदेह सरकारी खजाने पर इससे बड़ा बोझ पड़ेगा और वित्तीय निहितार्थ भी देखने को मिलेंगे. लिहाजा, तर्कसंगत और उचित विधेयक पारित होना चाहिए. आखिरकार इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अंत में राज्यों की ही है और ऐसे कई राज्य हैं, जहां कांग्रेस नीत सरकार नहीं है. यही वजह है कि विधेयक को पारित किए जाने से पूर्व इस पर समुचित विचार–विमर्श होना चाहिए.

एक अन्य पहलू भाजपा के चुनावी अभियान का है. अभियान समिति के अध्यक्ष अपनी जुबां पर नियंत्रण खो चुके हैं. वह कुछ भी अनाप–शनाप बोलते हैं. एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में जिस तरह उन्होंने गुजरात दंगों और हिंदुत्व पर अपना रुख रखा, वह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है. उनसे सवाल किया गया था कि क्या उन्हें गुजरात दंगों में मारे गए लोगों का दुख है. इस पर उनका जवाब था कि कुत्ते का पिल्ला भी यदि कार के नीचे आ जाए, दुख तो तब भी होता है. इंसानी जिंदगी से जानवर की तुलना करना कतई अविवेकपूर्ण है. यह बिल्कुल गलत राजनीति है. सवाल यहां 2002 के गुजरात दंगों में मौत के मुंह में समा चुकीं एक हजार से अधिक जिंदगियों का है. इस तरह के अनुचित बयानों के बाद उनकी ओर से कैसी भी सफाई दी जाए, बेमानी ही लगती है. मैं नहीं जानता कि यह किसी रणनीति के तहत किया गया है, लेकिन उन्हें एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है. अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाने की बात करना ठीक है. अयोध्या जाकर कोई भी राजनेता यही कहेगा, लेकिन यह कहीं से भी देश हित में नहीं है.

अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं. वह यह है कि क्या संविधान में की गई परिकल्पना के अनुसार, यह देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ है या नहीं? क्या हमने अपना संयम खो दिया है? क्या कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में होने के कारण वह भ्रष्टाचार को जारी रखेगी, फिर चाहे उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) कठघरे में खड़ा करे, या सुप्रीम कोर्ट? क्या भाजपा सोचती है कि धर्मनिरपेक्षता की देश में मौत हो चुकी है और उसे मुस्लिम भावनाओं को रौंदने का ठेका मिल गया है?

2002 में की गई गलतियों को सुधारने की बजाय वह मंदिर के बारे में बात कर भावनाओं को हवा देने में लगी है. पार्टी के अभियान समिति के अध्यक्ष आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. इसलिए मैं मानता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए इस संसद को पूरा एक दिन संविधान की मूल बातों के निहितार्थ को समझने के लिए आरक्षित करना चाहिए. मैं मानता हूं कि राजनीतिक संवाद को सम्यक स्तर पर लाया जाना चाहिए. एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने के चलन को समाप्त करना चाहिए. निश्चित ही हमें बहस करनी चाहिए. अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन बहस करते हैं, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर बहस करते हैं. पर, यह बहस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बिंदुओं पर होनी चाहिए. व्यक्तिगत छींटाकशी इसका हिस्सा नहीं होने चाहिए. मुझे याद है, जब अंतिम बार रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाया गया था, भाजपा इसे मुद्दा बनाने से बच रही थी. अंदरखाने पार्टी के सदस्यों में तय हो गया था कि वे परिवार के सदस्यों को निशाना नहीं बनाएंगे. इसका सीधा मतलब है कि उन्हें इस बात का डर है कि इसका असर उनकी अपनी पार्टी पर भी पड़ेगा. जब उनमें इतना डर है, तो उन्हें भ्रष्टाचार पर बातें नहीं करनी चाहिए, संसद में हंगामे से बाज आना चाहिए और सदन के बहिष्कार से बचना चाहिए. यदि आप कोई मुद्दा सिर्फ इस डर से नहीं उठा सकते कि दूसरा भी आपको घेरेगा, तो आप प्रमुख विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते. मैं सोचता हूं, यह मानसून सत्र अच्छा अवसर होगा. बीते मानसून सत्र में बमुश्किल सोलह बैठकें हो पाई थीं. इस सत्र में अधिक से अधिक काम होना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

वक्तव्य

मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा एक व्यक्ति विशेष के बारे में कि मैं उन्हें सांप्रदायिक समझता हूं कि नहीं, तो मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया कि मेरे पास कोई सुबूत नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि वे सांप्रदायिक हैं या नहीं हैं. वे एक ऐसे दल में हैं, जिस दल की मान्यता है कि वह इस समुदाय के पक्ष में है और बाकी समुदायों के खिलाफ है और खासकर कि एक समुदाय के बहुत खिलाफ है, यह तो सर्वविदित है. अब रहा सवाल मेरे कथन का, जिसकी मैं देख रहा हूं काफी चर्चा हो रही है, उससे यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि मैंने किसी को भी सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं हूं. भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी पार्टियों को उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा और जो पार्टियां उसके मुताबिक नहीं चलेंगी, उनको बहुमत नहीं मिल सकता. मैं एक व्यक्ति विशेष को लेकर आगे नहीं बढ़ा हूं, यह दल का मामला है, जिसने उन्हें अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है. इसलिए उस दल का जो मत है, उसी को तो प्रतिबिंबित करेंगे. मैं किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं. मैं तो आम अभियान चला रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ.

आत्म–शुद्धि और संगठन सफलता की कसौटियां हैं

ठाकुर दास बंग

आज सस्ते कच्चे माल और महंगे पक्के माल से ग्रामीणों का कैसा शोषण हो रहा है! एक किलो रुई की क़ीमत 10 रुपये है. इससे बनने वाली मिल की चार धोतियों या कपड़ों की क़ीमत 100–125 रुपये होती है, यानी 10 रुपये गांव के किसान–मज़दूर को और 100 से अधिक रुपये शहर के संगठित मज़दूर, व्यवस्थापक वर्ग और टाटा–बिड़ला जैसे पूंजीपति को. गेहूं का दाम दो रुपये किलो है और उससे बने पारले बिस्कुट का दाम 22 रुपये. कितना भयंकर मुनाफा है यह! शहर के कारखाने का मालिक बिस्कुट या कपड़े का लागत–खर्च निकालते समय ऊंची दर पर अपनी मज़दूरी और वेतन तो लगाता ही है, साथ ही साथ प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित डिब्बे में सफर, पंचतारा होटलों–महानगरों में रहने और टेलीविजन आदि विलास के खर्चे भी पक्के माल के लागत–खर्च में जोड़े जाते हैं. इसके अलावा, कई वस्तुओं में बेतहाशा मुनाफा लिया जाता है. कई दवाएं लागत–खर्च पर हज़ार–दो हज़ार प्रतिशत मुनाफा जोड़कर बाज़ार में बेची जाती हैं. इसलिए इस बहिष्कार–आंदोलन से न केवल शोषण रुकेगा, बल्कि साथ–साथ गांवों में काम की मात्रा बढ़ने से पूर्ण रोज़गार की दिशा में गांव ठोस क़दम भी उठाएंगे. इस प्रकार शोषणयुक्त गलत अर्थव्यवस्था से न केवल असहयोग होगा, बल्कि साथ–साथ गांवों में इन चीजों के उत्पादन से वैकल्पिक रचना का निर्माण भी होगा. अत: गलत रचना का ध्वंस और वैकल्पिक रचना का निर्माण, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू साथ–साथ चलेंगे. गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम और सत्याग्रह, ये जो अमोघ अस्त्र जनता को दिए,

उनका उपयोग कर यह आंदोलन चलाया जाना चाहिए.

आंदोलन का स्वरूप निर्दलीय होगा और शांतिपूर्ण भी. इस न्यायसंगत मांग को मानने वाला कोई भी नागरिक, भले ही वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या न हो, एक नागरिक की हैसियत से इस आंदोलन में शामिल हो सकेगा. अपने–अपने दल की नीतियां बढ़ाने या गुटबाजी करने के लिए दलों के सदस्य इस आंदोलन में शामिल न हों. मंदिर में जाते समय हम अपने जूते, चप्पल और सैंडिल बाहर खोलकर मंदिर में प्रवेश करते हैं. ठीक वैसे ही अपने दल के विचारों को छोड़कर इस आंदोलन में नागरिक के नाते कोई भी शामिल हो. आज भी सारे राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या मतदाताओं की संख्या के अनुपात में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है. दूसरे शब्दों में, 90 प्रतिशत नागरिक निर्दलीय हैं. दलों के सदस्यों में भी ग्राम–स्तर के सदस्य आंदोलन शुरू होते ही इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी दलीय निष्ठा बहुत गहरी नहीं होती है. वास्तव में यह आंदोलन किसी के ख़िलाफ़ है भी नहीं. अत: 90 प्रतिशत निर्दलीय नागरिक अपनी शक्ति को पहचान कर इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में दाखिल हों. यह आंदोलन देश भर या देश के अधिक से अधिक हिस्सों में एक ही समय किया जाए, तो इसका असर जल्द हो सकता है, अन्यथा आंदोलन की स्थायी सफलता कठिन होगी. अत: देश भर में एक ही समय आंदोलन शुरू होना चाहिए.

यह आंदोलन संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होना चाहिए. इस बारे में अगर कोई ढिलाई बरती गई या लाठी, ईंट–पत्थर का प्रयोग जनता की ओर से हुआ, तो सरकार को दमन, यानी गोली–चालन का मौक़ा या निमित्त मिल सकता है. ऐसा हुआ, तो जनता की हार होगी. किसी प्रकार की तोड़–फोड़ या संपत्ति नष्ट करना इस आंदोलन में नहीं होना चाहिए. वैसा हुआ भी नहीं है. ग्रामीण समाज इस देश का मालिक है. वह अपनी ही संपत्ति नष्ट कैसे करेगा? इसलिए सत्याग्रहियों को शांतिपूर्णता की शपथ लेकर इस आंदोलन में उतरना होगा. रणनीति की दृष्टि से भी शांतिपूर्णता की शर्त अनिवार्य है. 70–80 प्रतिशत जनता जिस आंदोलन में हिस्सा लेती है, उसे दंगा–फसाद या अशांति करने की ज़रूरत ही क्या है? इसलिए हमारी संख्या को शक्ति मानकर और शांतिपूर्णता शक्ति की निशानी है, यह विचार करके बहादुरी से इस आंदोलन में हर एक को हिस्सा लेना चाहिए और कष्ट सहन करने चाहिए. इन कष्टों के कारण ग्रामीणों की तपस्या होगी, उनकी आत्म–शुद्धि होगी और उनका संगठन सुदृढ़ होगा. आत्म–शुद्धि और संगठन, ये दो सफलता की कसौटियां हैं. इसलिए निर्दलीयता और शांतिमयता की कसौटियों से आंदोलन को एक क्षण के लिए विचलित नहीं होना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

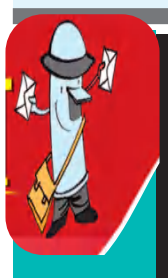

राहुल जी, प्लीज ओबामा को बख्श दें

चौथी दुनिया की आवरण कथा–राहुल ओबामा बनना चाहते हैं (15 जुलाई, 2013) पढ़ी, अच्छा लगा. इसमें राहुल गांधी द्वारा विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा की नकल करने जैसी बातों पर प्रकाश डाला गया है. लेखक ने राहुल के हाव–भाव और बोलने के तरीके पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है, जो उनकी एक खास शैली को दर्शाता है. राहुल द्वारा ओबामा की चाल–ढाल, हाव–भाव की नकल उन्हें ओबामा तो कभी नहीं बना सकती, लेकिन हंसी का पात्र ज़रूर बना सकती है. आख़िर राहुल ओबामा कैसे बन सकते हैं. राहुल अगर यह सोचते हैं कि ओबामा बनने के लिए सिर्फ़ उनके हाव–भाव की कॉपी ही काफी है, तो यह उनकी भूल है. राहुल की सरकार में रोज घोटाले हो रहे हैं. उनकी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है. कांग्रेस का देश पर लगभग 50 साल का शासन रहा है, लेकिन लूट की नीति आज भी बरकरार है. ऐसे में वह पाक–साफ अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर राहुल ऐसा करते या सोचते हैं, तो उनका यह करना या सोचना नेताओं के उन कथनों को सही ठहराता है कि राहुत अभी बच्चे हैं. मेरी राहुल को यही सलाह है कि अगर वह ओबामा ही बनना चाहते हैं, तो देश को ठोस नीतियां एवं साफ़–सुथरी सरकार दें और सरकारी विभागों को दुरुस्त करने का प्रयास करें. अगर यह सब नहीं कर सकते, तो प्लीज राहुल जी, जो आप हैं, वही रहें और ओबामा को भी ओबामा ही रहने दें.

–कैफील राजा, *दिल्ली.*

हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार

संविधान हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है. देवताओं की लिपि का एक अंग होने का गौरव रखने वाली हिंदी को क्या अपने ही उद्गम स्थान में वह सम्मान मिल पा रहा है, जिसकी वह हक़दार है. आज हिंदी माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि लेकर जो छात्र कॉलेज से निकल रहे हैं, क्या वर्तमान व्यवस्था उन्हें नियोजित कर पाने में समर्थ है? कतई नहीं. कॉरपोरेट और निजी क्षेत्र की बात तो छोड़ ही दीजिए, सरकारी रिक्तियों की भर्ती के लिए जो मापदंड तय हैं, वे हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों की तुलना में हीन साबित करते हैं. चाहे आप बैंकिंग, रेलवे, लोकसेवा आयोग या फिर एसएससी की ही परीक्षा क्यों न दे रहे हों. इन तमाम परीक्षाओं में उम्मीदवारों से अंग्रेजी में निपुण होने की अपेक्षा की जाती है, भले ही उनकी पढ़ाई का माध्यम हिंदी क्यों न रही हो? जिस छात्र ने अपनी पांचवीं कक्षा में एबीसी सीखी हो, उससे अंग्रेजी में महारथ हासिल करने की अपेक्षा क्या उचित है? कई भाषाओं की जानकारी रखना अच्छी बात है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति हीनभावना रखें. आज आधुनिकता की होड़ में जिस तरह से हिंदी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में वह दिन दूर नहीं, जब हिंदी की स्थिति वही हो जाएगी, जो आज संस्कृत की है. देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा नौवीं एवं दसवीं कक्षा में हिंदी की अनिवार्यता समाप्त करना हिंदी के प्रति हमारी उदासीनता को दर्शाता है. केवल हिंदी दिवस के मौक़े पर व्याख्यान भर देने से क्या हिंदी की महत्ता बरक़रार रखी जा सकती है? आज कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, पर अंग्रेजी में चूक होने पर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं. राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी पहचान है और पहचान खोकर तरक्की के ख़्वाब कभी नहीं संजोए जा सकते.

–विकास कुमार पाटनी, *झुमरी तिलैया, झारखंड.*

बयान पर बवाल

जिस तरह से राजनीति में इन दिनों बयानबाजी पर बवाल हो रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब राजनीति नहीं होती, बयानों पर दंगल होते हैं. दंगों पर मोदी के बयान से बवाल मच गया है. केवल मोदी की ही चर्चा हो रही है. जवाब में जहां एक ओर सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि धर्म का कोई राष्ट्र नहीं हो सकता, वहीं दूसरी ओर निर्मला सीतारमण मोदी को बचाने के लिए कह रही हैं कि उनके साक्षात्कार को लेकर बिना वजह विवाद खड़ा किया गया है. वैसे, संजय राउत भी राजनीति में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने भी मोदी को बचाने की कोशिश की और कहा, हम मोदी के रुख का स्वागत करते हैं.

–नरेश कुमार, *नोएडा, उत्तर प्रदेश.*

चौथी दुनिया सबसे अलग

अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं निर्भीकता के चलते चौथी दुनिया सबसे अलग है. यही कारण है कि आज बाज़ार में 83 फ़ीसद हिस्सेदारी और 1.51 करोड़ पाठकों के साथ वह पहले स्थान पर है. मुझे चौथी दुनिया से बढ़कर कोई दूसरा अख़बार पसंद ही नहीं है. मुझे चौथी दुनिया में मुख्य पृष्ठ, सियासी दुनिया, हमारी दुनिया एवं राशिफल विशेष रूप से पसंद हैं.

–संजय कुमार झा, *दरभंगा, बिहार.*

मुखौटा

संवाद जारी है
झोपड़ी का मानव से,
जब तू
जंगल से था आया,
तब मैंने
तुम्हें था अपनाया,
फिर क्यों
तुमने अपने बंगले के
मुखौटे पे
मुझे सजाकर
मेरा मजाक उड़ाया?

–घनश्याम बेलानी गुलाब, कटनी, *मध्य प्रदेश.*

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

मोदी की वजह से देश बदलेगा

देश चुनाव के करीब जैसे-जैसे पहुंच रहा है, राजनीतिक दलों में चुनाव की हलचल उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रही है. भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी सार्वजनिक रूप से करनी शुरू कर दी है. नरेंद्र मोदी लगभग भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करने की स्थिति में हैं और जान-बूझकर ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. नरेंद्र मोदी ने अपनी बिसात बिछा दी है, लेकिन उस बिसात पर उन्होंने एक नई रणनीति भी अख्तियार की है. वे खुद नहीं खेल रहे हैं, बल्कि अमित शाह के जरिये खेल खिला रहे हैं. अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेजने और उन्हें पहले संसदीय बोर्ड में रखने का फैसला नरेंद्र मोदी का था. अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े रोल में नहीं देखना चाहते थे. इस जगह किसी को होना चाहिए था, अरुण जेटली को होना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी का विश्वास न अरुण जेटली पर है और न सुषमा स्वराज पर. उनका विश्वास अमित शाह पर है. अमित शाह के जरिये उन्होंने उत्तर प्रदेश को सीधा संदेश भी दे दिया है. संदेश कि अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आते हैं, तो मुसलमानों के जान-माल की गारंटी न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस और न ही बहुजन समाज पार्टी दे सकती है. मैं यह बात विश्वास के साथ इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जगह किसी दूसरे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना देते, तो मुझे उनके इरादे के बारे में कभी शंका ही नहीं होती, लेकिन अभी इसलिए शंका हो रही है, क्योंकि अमित शाह का दिमाग, उनका तरीका, उनका सोचना और उनका इतिहास देश के सामने बहुत साफ है. सुप्रीम कोर्ट अमित शाह के खिलाफ सुनवाई की मंजूरी भी दे चुका है. शायद अमित शाह को लेकर कई सारी अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं.

अमित शाह के बहाने नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों को नहीं धमका रहे हैं, बल्कि उनके बहाने दलितों को भी धमका रहे हैं. अमित शाह एक दबंग किस्म के मंत्री रहे हैं और ऐसे मंत्री रहे हैं, जो कुछ घटनाएं घटवा कर कुछ समुदायों को सीधा संदेश देता है. ऐसे मंत्री जब राजनीतिक नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में जाएगा, तो यह सीधा संदेश उन लोगों के लिए भी है, जो कट्टर हिंदू हैं कि आप लोग खड़े हो जाएं. आप अगर खड़े हो जाएंगे, तो आपके सामने न मुसलमान आने की हिम्मत करेंगे और न ही दलित. अमित शाह के जरिये नरेंद्र मोदी का संदेश उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, लेकिन इससे बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के समय विश्व हिंदू परिषद ने देने काम किया था. दिल्ली में नरसिम्हा राव की सरकार थी और बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी, जिसे भाजपा के लोग कहते हैं कि ढांचा गिरा दिया गया था. यह संदेश उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों के कट्टर हिंदुओं के लिए भी था. अब अगर वे खड़े हो जाएंगे, तो नरसिम्हा राव के बाद जो भी प्रधानमंत्री होगा, वह भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि मस्जिद गिरा दी गई है और भगवान राम का भव्य मंदिर वहां बनाना है. विश्व हिंदू परिषद द्वारा सारे देश को दिए गए इस संदेश के बाद, खासकर उत्तर प्रदेश को दिए गए संदेश के बाद ही चुनाव हुए. उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह हार मिली. कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी. कल्याण सिंह ऐसे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करके कहा था कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा. सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करेगी, लेकिन कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत नहीं की. पर सवाल यह है कि वह संदेश उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने कैसे लिया. उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने अगले चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया. उत्तर प्रदेश के या देश के हिंदुओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दलों को बहुमत दिया और इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने. इसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री अवश्य बने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे कारण राम मंदिर नहीं था, या बाबरी मस्जिद का गिरना नहीं था. अटल बिहारी वाजपेई के प्रधानमंत्री बनने के पीछे सिर्फ एक कारण था कि तीसरे मोर्चे के नाम पर देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनें. उन्होंने देश के लोगों का मोह भंग किया. लोगों की इच्छा भाजपा को सत्ता में लाने की नहीं थी, लेकिन दोनों ने देश के बुनियादी विकास के लिए कुछ नहीं किया. हां, देवगौड़ा को जब कांग्रेस ने सत्ता से हटाया, तो इंद्र कुमार गुजराल को उन्होंने प्रधानमंत्री जरूर बनाया, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल को भी कांग्रेस ने सत्ता से अंततः हटा ही दिया.

देश को फिर ऐसा लगा कि देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल जैसे नेता या तथाकथित तीसरा मोर्चा देश में सरकार नहीं चला सकता. देश के एक बहुत बड़े वर्ग का कनसर्न नीति संबंधी फैसलों में नहीं, बल्कि सुचारू रूप से सरकार चलाने में है. इसीलिए लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया. यह बात बहुत लोग नहीं समझते हैं कि उनका प्रधानमंत्री बनना तीसरे मोर्चे की असफलता का प्रमाण है. उस समय अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन दलों को साथ लिया, उन दलों की सभी शर्तें उन्होंने मान लीं. शर्तें थीं - धारा 370 के बारे में बात नहीं होगी, राम मंदिर-बाबरी मस्जिद यथास्थिति बनी रहेगी और कोई बातचीत उस पर नहीं होगी. समान आचारसंहिता लागू करने की मांग नहीं उठाई जाएगी और इन सभी विषयों पर कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा.

अटल जी ने इन बातों को माना और वह लगभग सात साल प्रधानमंत्री रहे. अटल जी ने इन विषयों पर बात तक नहीं की, जबकि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहते थे कि मंदिर भी बने और 370 भी खत्म हों. अटल जी से साफ कह दिया कि जब हमारे दोस्त-भाई दो तिहाई की संख्या में सांसद हो जाएंगे, तभी यह काम हो सकता है.

> मैं यह बात विश्वास के साथ इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जगह किसी दूसरे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना देते, तो मुझे उनके इरादे के बारे में कभी शंका ही नहीं होती, लेकिन अभी इसलिए शंका हो रही है, क्योंकि अमित शाह का दिमाग, उनका तरीका, उनका सोचना और उनका इतिहास देश के सामने बहुत साफ है. सुप्रीम कोर्ट अमित शाह के खिलाफ सुनवाई की मंजूरी भी दे चुका है. शायद अमित शाह को लेकर कई सारी अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं.

अब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और सारे देश को एक संदेश दे रहे हैं. यह संदेश बहुत खास है. अमित शाह उनके विश्वसनीय सिपहसालार हैं और यह मान लेना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो गृहमंत्री या उप-प्रधानमंत्री अमित शाह ही होंगे. अमित शाह ने जैसे गुजरात में पुलिस का इस्तेमाल कर मुसलमानों को डराया, धमकाया, ठीक वैसा ही काम गृहमंत्री या उप-प्रधानमंत्री बनने के बाद वह करेंगे. अमित शाह न केवल देश में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े अंतरंग सिपहसालार हैं, बल्कि वह नरेंद्र मोदी की नीतियों का जीता-जागता चेहरा हैं.

अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह अलग बात है. पर मुझे यह लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस दिशा में चल रहे हैं, वह कट्टर हिंदुत्व की दिशा है. अगर सारे हिंदू नरेंद्र मोदी की इस दिशा का समर्थन कर देते हैं, तो देश का भाग्य ही बदल जाएगा. फिर मुसलमान यहां दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहेंगे. और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो इस देश में वैसा ही लोकतंत्र चलेगा, जैसा हमारे संविधान में परिभाषित है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर संविधान बदलने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन यह संविधान जनता के पक्ष में नहीं, बल्कि कट्टर हिंदुओं के पक्ष में बदला जाएगा.

सवाल यह उठता है कि क्या देश का सामान्य हिंदू, जिसे हम मॉडरेट हिंदू कहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा. अब तक का इतिहास तो यही कहता है कि सामान्य हिंदू कहा जाने वाला नागरिक इतना समझदार है कि वह देश को पहले और धर्म को बाद में देखता है, क्योंकि सामान्य हिंदू नाम से जाने जाना वाला नागरिक जानता और मानता है कि वह धर्म से हिंदू नहीं, बल्कि धर्म से सनातनी है. और सनातन धर्म और हिंदू धर्म में फर्क है. फर्क बहुत साफ है कि हिंदू नाम से कोई धर्म है ही नहीं और सनातन नाम से धर्म है. सनातन धर्म के नारे अलग हैं और हिंदू धर्म के नारे अलग. हिंदू धर्म विश्व हिंदू परिषद ने चलाया है और विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए हुए धर्म को अभी भारत के नागरिकों ने स्वीकार ही नहीं किया है. इसीलिए 2014 में जो फैसले लिए जाएंगे, उनमें एक फैसला यह भी होगा कि इस देश का हिंदू इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहता है या सांप्रदायिकता की आग से बचाकर विकास और लोकतंत्र की राह पर पुनः खड़ा करना चाहता है. ■

editor@chauthiduniya.com

अकर्मण्य और धर्मनिरपेक्ष राजनेताओं का सच

मेघनाद देसाई

सेक्युलर और कम्यूनल की लड़ाई में राजनीति के मूल मुद्दे, यानी देश का विकास और जनता की ज़रूरतें काफी पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन इन सबसे भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल के नेताओं को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. उन्हें चिंता है, केवल येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने की.

पाकिस्तानी अधिकारियों में जांच के दौरान इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि ओसामा बिन लादेन ऐबटाबाद कैसे पहुंचा. महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में भी यह बात काफी हद तक फिट बैठती है. महाबोधि मंदिर में सारे सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम कर रहे थे, गार्ड्स वहां मौजूद थे और अन्य चीजें भी अपनी जगह पर दुरुस्त थीं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आख़िर उपद्रवी तत्व वहां पहुंचे कैसे?

ये चीजें देश के लिए ठीक नहीं हैं. यहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियम-क़ानून हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता. दिल्ली गैंगरेप की घटना से पहले लगता था कि यहां उत्पीड़न, दुष्कर्म और छेड़खानी के ख़िलाफ़ भी क़ानून है, लेकिन किस काम के ऐसे क़ानून कि किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई. हमारे पास दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां हैं, लेकिन रुपया दम तोड़ता नज़र आता है. सब कुछ वैसा ही हो रहा है, जैसा होना चाहिए, सिवाय काम के. हमारे नेताओं को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि सबसे प्रमुख समस्या मुद्दों की राजनीति है. हमेशा विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह दावे के साथ कहते हैं कि महाबोधि मंदिर की घटना के तार नरेंद्र मोदी और बिहार भाजपा कैडर में हुई बातचीत से जुड़े हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हिंदुत्व का षड्यंत्र है, लेकिन कौन जानता है? ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए, तो वह गलत नहीं हैं. ब्राह्मणों ने कई सारे बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिरों में परिवर्तित कर दिया. इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ब्राह्मणों के प्रोत्साहन के बाद ही तोड़ा था. बौद्धों और ब्राह्मणों से संबंधित इन साक्ष्यों को हिंदुओं के कैंप ने इतिहास से इसलिए मिटा दिया कि वे इस बात में विश्वास करते हैं कि हिंदुत्व इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. धर्मनिरपेक्ष तत्व यह मानते हैं कि खिलजी ने अपने समय में इस बात का ज़रूर ख्याल रखा होगा कि आने वाली सदियों में किसी तरह के धार्मिक निर्माण के विध्वंस को लेकर मुसलमानों पर दोषारोपण न किया जाए.

समकालीन ज़रूरतों के मुताबिक इतिहास को भूलने और उसे फिर से तोड़-मरोड़ कर पेश करने की परंपरा शुरू से ही रही है. अगर हम 1990 के मध्य का समय याद करें, तो पाएंगे कि उस समय लोग कहा करते थे कि अगर भाजपा सत्ता में आई, तो उसका शासन हिटलर की तरह होगा और भारत के लोग 1933 की यूरोपीय ज़िंदगी को कल्पना में जिएंगे. उस समय वाजपेयी बस एक मुखौटा भर थे, उन सबके पीछे वास्तविक चेहरा तो आडवाणी का था. हालांकि समय की नज़ाकत देखते हुए आडवाणी ने अपनी आत्मा ही बदल दी है. कांग्रेस नेताओं में आडवाणी के प्रति मोदी द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर संवेदना प्रकट करने की होड़ सी मची है. वाजपेयी तो एक संत की तरह हैं, जिनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं है और वह धर्मनिरपेक्ष छवि वाले नेता हैं. वाजपेयी के समय भाजपा की छवि भी काफी अच्छी थी. सबसे प्रमुख मुद्दा मोदी खुद हैं. एक ऐसा मुद्दा, जिसे नई सदी का नया ख़तरनाक फासीवादी कहा जा सकता है. खुद को बुद्धिजीवी, निर्दोष एवं धर्मनिरपेक्ष कहने वाली कांग्रेस सबको यह कहकर डरा रही है कि अगर मोदी सत्ता में आए, तो आप लोगों को 1930 के जर्मन बुद्धिजीवियों की तरह देश से निकाल बाहर किया जाएगा.

भारत एक जटिल लोकतांत्रिक देश है. आज़ादी के बाद आपातकाल के दौरान जो फासीवादी प्रयोग किया गया था, यह उसी माहौल में सुरक्षित रह सकता है. उस समय इंदिरा गांधी देश की भावनाओं को तोड़ने में पूरी तरह से असफल रही थीं. वह एक ऐसा दौर था, जब संजय गांधी ने ग़रीब मुसलमान परिवार वाले इलाकों पर होने वाले अत्याचारों का समर्थन किया था. उन्होंने ऐसे परिवारों को नसबंदी कराने के लिए बाध्य भी किया था. तुर्कमान गेट में मुसलमानों की झुग्गी-झोपड़ियों को उस समय जला दिया गया, जब आरएसएस ने जामा मस्जिद के इमाम के साथ मिलकर कांग्रेसी आततायियों को ललकारा.

> भारत एक जटिल लोकतांत्रिक देश है. आज़ादी के बाद आपातकाल के दौरान जो फासीवादी प्रयोग किया गया था, यह उसी माहौल में सुरक्षित रह सकता है. उस समय इंदिरा गांधी देश की भावनाओं को तोड़ने में पूरी तरह से असफल रही थीं. वह एक ऐसा दौर था, जब संजय गांधी ने ग़रीब मुसलमान परिवार वाले इलाकों पर होने वाले अत्याचारों का समर्थन किया था.

जब इतिहास लिखा गया, तो ऐसे किसी भी वाकये का जिक्र नहीं किया गया और इसीलिए इंदिरा गांधी एक महान नेता बनकर उभरीं. मोदी आख़िर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि इस मसले पर खुले तौर पर विचार-विमर्श हो, तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा. ऐसे में अपने इतिहास का परीक्षण भी बहुत ही ईमानदारी से हो जाता. धर्मनिरपेक्षवादी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अगर वे 2002 की बातों का जिक्र कर सिर्फ़ मतदाताओं को डराते रहे और मोदी के सत्ता में आने पर फिर से मुसलमानों की सामूहिक हत्या की बात करते रहे, तो वे ज़रूर जीत जाएंगे. उनका मानना है कि इन बातों के सामने लोग मुद्रास्फीति, अस्थिरता, घोटाले, रुपये का अवमूल्यन और खराब विदेशी निवेश जैसे मुद्दे भूल जाएंगे.

इतिहास फिर से लिखा जा सकता है, लेकिन दुःख की बात है कि भविष्य नहीं लिखा जा सकता. ऐसे लोग, जिनकी उम्र 30 साल है और जिनकी संख्या 300 मिलियन के लगभग है, वे अपने भविष्य को लेकर सवाल कर सकते हैं. क्या उस जगह पर अच्छी शिक्षा का सपना साकार हो सकता है, जहां शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं रखते. लोग जब अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे, तो क्या उन्हें नौकरी मिल सकती है? क्या रोजमर्रा की ज़रूरतों वाली चीजों के दाम स्थिर रहेंगे, क्या उच्च विकास दर की प्राप्ति होगी? आख़िर कौन सी पार्टी इन लक्ष्यों को पूरा करने का आश्वासन देगी, इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? यह कम से कम वैसे डरपोक व्यक्ति तो नहीं कर सकते, जो कपोल-कल्पनाओं में जीते हैं और जो हिटलर को लेकर चिंतित हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

छात्रवृत्ति न मिले, तो क्या करें?

चौथी दुनिया ब्यूरो

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि ऐसे छात्र, जिनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, उनकी पढ़ाई-लिखाई में कोई दिक्कत न आए. इसके लिए बाक़ायदा नियम-क़ानून भी बनाए गए हैं कि कौन इस छात्रवृत्ति का हक़दार होगा और कौन नहीं. इसके बावजूद, कई बार ऐसी ख़बरें भी आती हैं कि ज़रूरतमंदों और असली हक़दारों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती या बच्चों के अभिभावकों से हस्ताक्षर कराकर इस मद का पैसा अंततः हड़प लिया गया. ज़ाहिर है, इस काम में स्कूल प्रशासन से लेकर अधिकारियों तक की मिलीभगत होती है. दरअसल, इस समस्या के पीछे कई कारण हैं, मसलन आम आदमी का जागरूक न होना, उसे अपने अधिकारों की जानकारी न होना या अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह होना. वैसे, एक और वजह है और वह है भ्रष्ट पंचायती व्यवस्था. यदि पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, तो यह व्यवस्था अन्य किस्म के भ्रष्टाचार को भी बढ़ाती है. ग्रामसभा नामक संवैधानिक संस्था, जिस पर गांवों से जुड़े शासन-प्रशासन को नियंत्रित और देखरेख करने की ज़िम्मेदारी है, को भी पंगु बना दिया गया है. यदि ग्रामसभा में इन मुद्दों पर ईमानदारी से बहस की जाए, तो ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो वास्तव में इनके हक़दार हैं या जिन्हें इनकी ज़रूरत है. इस अंक में हम छात्रवृत्ति के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि का ग़बन होने से रोक सकते हैं. इस अंक में एक आवेदन का प्रारूप प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप छात्रवृत्ति की राशि के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(विद्यालय में छात्रवृत्ति का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया.....विद्यालय में छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:-

1. उपरोक्त विद्यालय की कक्षा.....में मेरा पुत्र/पुत्री .....पढ़ता/पढ़ती है. आपके रिकॉर्ड के मुताबिक़ क्या वह इस वर्ष छात्रवृत्ति पाने का हक़दार है? यदि हां, तो उसे कितनी राशि मिलनी चाहिए?
2. क्या आपके विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक़ उसे इस वर्ष की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है? यदि हां, तो संबंधित दस्तावेज़ों/रजिस्टरों के उस भाग की प्रमाणित प्रति दें, जहां उसे छात्रवृत्ति दिए जाने का विवरण दर्ज है.
3. यदि उसे छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, तो उसका क्या कारण है? संबंधित दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति दें.
4. उपरोक्त विद्यालय में कुल कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? प्रत्येक छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं कक्षा का विवरण दें.
5. वर्ष.....में कुल कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई? प्राप्ति रजिस्टर, जिस पर छात्र-छात्राओं या उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर हों, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.
6. छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए क्या नियम एवं क़ानून हैं? इस संबंध में समस्त शासनादेशों/निर्देशों एवं क़ानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
7. सरकार ने विभिन्न कक्षाओं के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की है?
8. अगर किसी छात्र की छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, तो उसका क्या कारण है? ऐसे सभी छात्रों की सूची दें, जिन्हें अब तक छात्रवृत्ति नहीं दी गई है. इस सूची में निम्नलिखित विवरण अवश्य शामिल हों:-
   क. छात्र का नाम
   ख. पिता का नाम
   ग. छात्रवृत्ति न दिए जाने का कारण
10. छात्रवृत्ति का भुगतान समय से न होने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के नाम एवं पद बताएं. अपना काम विभाग के नियम-क़ानूनों के अनुसार न करने वाले उक्त अधिकारियों केख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नं.....

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आप मौज-मस्ती करना चाहेंगे और आर्थिक स्थिति उसमें आपकी मदद करेगी. आप अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे. खर्च भी बढ़ेंगे और सप्ताह के अंत में आप महसूस करेंगे कि अत्यधिक खर्च हुआ. वाणी पर नियंत्रण रखें. धैर्य रखने से आपके अनसुलझे कार्य भी सुलझेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
प्रगति के अच्छे संकेत हैं. धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा नुक़सान हो सकता है. परिवार में प्रेम का माहौल बना रहेगा. अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं और अगर किसी बात की कमी है, तो उसे ठीक कराएं. पुराने लंबित कार्य पूर्ण होने वाले हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह आप कड़ी मेहनत करेंगे और मिलने वाले पुरस्कार को अधिकार के साथ हासिल करेंगे। कोई ऐश्वर्य की वस्तु, जो घर के उपयोग की हो, उसकी खरीद होगी. किसी नई जगह की यात्रा और जोखिम वाले बाज़ार से यथासंभव बचें. दांपत्य जीवन में दूरी न आने पाए. आप एकांत में सोचकर आगे की रणनीति बनाएंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आत्मविश्वास में काफी बढ़ोत्तरी होगी और आप आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेंगे. आय के स्रोतों में भी बढ़ोत्तरी होगी. किसी भी क्षण अपने अंदर गरूर न लाएं और ज़मीनी हकीकतों से वाकिफ रहें. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति के प्रबल योग हैं. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
नौकरीपेशा एवं व्यापारियों के लिए कुल मिलाकर अच्छा समय है. कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक रूप से चिंतित रहेंगे. कुछ व्यर्थ के कार्यों में पैसों का व्यय हो सकता है. पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा. मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी. लेन-देन में सावधानी बरतें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह आप थोड़ा सुकून महसूस करेंगे. आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. संपत्ति के क्रय-विक्रय में सावधानी रखें. किसी निर्णय पर पहुंचने से पहलें किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार-विमर्श ज़रूर करें. पारिवारिक माहौल मिला-जुला असर देगा. नौकरीपेशा एवं व्यापारियों के लिए अच्छा समय है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
शत्रुओं से सावधान रहें, अन्यथा झूठे इल्जाम में फंसने का डर रहेगा. अपने किसी भी क्रय-विक्रय पर अत्यधिक सावधानी रखें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान देंगे. आप अपने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें. स्त्री पक्ष से थोड़ी परेशानी रहेगी. वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
विरोधी नुक़सान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. इस सप्ताह कुछ असंतोष की स्थिति रहेगी. कभी-कभी मन विचलित हो सकता है, इसलिए मन को एकाग्र रखें, आप फ़ायदे में रहेंगे. किसी राजनीतिक व्यक्ति के संपर्क से यात्रा की योजना बनेगी और आप लाभ की स्थिति में रहेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
ऐसे दोस्तों से सावधान रहें, जिसके मन में आपके लिए अच्छी भावना नहीं है. आपका मन इस सप्ताह असुरक्षित रहेगा. इकट्ठा किए हुए पैसों का निवेश सतर्क होकर करें. ज़मीन-जायदाद से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग थोड़ा तनाव महसूस करेंगे. स्वास्थ्य हल्के उतार-चढ़ाव के साथ अच्छा रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. इस सप्ताह आपकी सोची हुई चीजें पूरी होंगी. पदोन्नति की ख़बर मिल सकती है. आप भ्रमण से धन इकट्ठा करेंगे. व्यवसायी कुछ उलझन में रहेंगे. क़ानूनी मामलों में सतर्क रहें. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. दांपत्य जीवन और संतान सुख प्राप्त होगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह उत्तेजना में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है. कर्ज के लेन-देन पर ज़्यादा ध्यान रखें और कोई नया कर्ज न लें. किसी नई संपत्ति की खरीद का मौक़ा मिल सकता है. मित्रों एवं बंधुओं से समन्वय आपके आर्थिक लाभ के लिए अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों को लाभ के योग हैं. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
वाहन ध्यान से चलाएं, अन्यथा शरीर को नुक़सान हो सकता है. आप खुद से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखेंगे. खुद को उलझाने वाली चीजों से बचाकर रखें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक एवं व्यक्तिगत तनाव रहेगा. जोखिम वाले बाज़ार में ज्यादा निवेश न करें.

ज़रा हट के

मृत व्यक्ति मेयर बना

क्या कभी आपने किसी मृत व्यक्ति को वोट दिया है, या चुनाव के बाद जीत या हार की घोषणा में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम की घोषणा होते सुना है, जो कुछ साल पहले ही मर गया हो. सुना होगा आपने. चलिए हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं. यह बात है मेक्सिको की, जहां एक अजीबोगरीब घटना हुई है. यहां के दक्षिणी शहर ओक्सासा के पास स्थित एक गांव में कुछ दिनों पहले हुए चुनाव में निर्वाचित होने वाला मेयर तीन साल से मृत घोषित था. जब लेनिन कारबालिदो सैन आग्सिटिन अमातेगो को गांव का मेयर निर्वाचित किया गया, तो उसका निर्वाचन विवादों में घिर गया, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र से खुलासा यह हुआ कि वह 2010 में ही मधुमेह से मर गया है. ■

मृतक को मिली सजा!

जीवित व्यक्ति को सजा पाते हुए आप रोज देखते-सुनते होंगे, लेकिन आज हम आपको मरे हुए व्यक्ति की सजा के बारे में बताएंगे. रूस की एक अदालत द्वारा कर चोरी के लिए एक वकील को मरने के बाद सजा सुनाने का मामला सामने आया है. यह सजा वकील सरजेई मैगनित्सकी को दी गई, जिनकी मृत्यु जेल में 2009 में ही हो गई थी. मैगनित्सकी इन्वेस्टमेंट फंड के वकील थे. उनके खिलाफ मुकदमा मरने के बाद भी चलता रहा. उन पर दो करोड़ 30 लाख डॉलर की कर चोरी का आरोप था. ■

अंधा बन ले रहा था पेंशन

अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से सही-सलामत हो, इसके बावजूद वह विकलांगों को मिलने वाले पेंशन का लाभ उठा रहा हो, तो है न यह हैरान करने वाली बात. जी हां, इटली में एक व्यक्ति चकमा देकर इसी तरह से विभाग से विकलांग पेंशन योजना का फायदा उठा रहा था. उस व्यक्ति ने अंधे होने का ढोंग करके पिछले तीन साल से हर महीने लगभग 40 हजार रुपये का पेंशन लिया. इस कारनामे का भांडाफोड़ तब हुआ, जब उसे पढ़ते हुए देखा गया. सूत्रों के अनुसार, पेरूगिया शहर में रहने वाले इस व्यक्ति ने बताया था कि उसे एक ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से वह लगभग अंधा हो गया है. उसने बताया कि अपने रोजमर्रा के काम करने और अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए उसे आर्थिक मदद की जरूरत है. इसके बाद उसे 2010 से 500 यूरो यानी लगभग 40 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन मिलना शुरू हो गया था, लेकिन पुलिस ने जब इस व्यक्ति को साइकिल चलाते, तेजी से चलते और पढ़ते देखा, तो हकीकत कुछ और ही सामने आई. अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वह सलाखों के पीछे है. उस व्यक्ति के पास से पेंशन के 16 हजार 500 यूरो बरामद हुए हैं. उस पर सरकार की तरफ से धोखाधड़ी का केस चलाया जाएगा. ■

जानवरों के लिए शवदाह गृह

अब तक इंसानों के लिए ही शवदाह गृह की बात सुनी गई थी, लेकिन अब आपको जानवरों के लिए भी शवदाह गृह देखने को मिलेंगे. अब आप अपने पालतू जानवरों का दाह संस्कार भी सम्मानजनक तरीके से कर सकते हैं. यह शवदाह गृह बेंगलुरु में खुलने जा रहा है. यहां के पशु-प्रेमी भी अपने पालतू जानवरों को सम्मानजनक ढंग से अंतिम विदाई दे सकेंगे. बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी शहर के सोमनहल्ली क्षेत्र में जानवरों का शवदाह गृह बनाने की योजना बना रही है. सूत्रों के अनुसार, छोटे और बड़े जानवरों को जलाने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी. इस शवदाह गृह में एक दिन में लगभग 25 जानवरों को जलाया जा सकेगा. ■

बकरियों के साथ कैफे में सैर-सपाटे

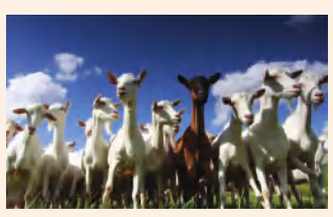

जापान में अब एक ऐसा कैफे खोला गया है, जहां लोग पालतू बकरियों के साथ खेल तो सकते ही हैं, उन्हें टोक्यो के कंक्रीट जंगल में सैर पर भी लेकर जा सकते हैं. कैफे की मालकीन रीना कावागूची ने यह सब जानवरों के प्रति लोगों में प्यार जगाने और ऐसे लोग, जिन्हें जानवरों से प्यार था, को कैफे की तरफ आकर्षित करने के लिए किया. रीना ने तीन साल पहले अपने कैफे में दो बकरियां पालीं. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने कैफे में बकरियां पालीं, तो उस समय जापान में बिल्लियों या कुत्ते वाले कैफे की भरमार थी, लेकिन किसी भी कैफे में बकरियां नहीं थीं, जबकि बकरियां इंसानों से ज्यादा फ्रेंडली होती हैं. इसी को देखते हुए उन्होंने कुछ हटकर करना चाहा और बकरियों वाली कैफे की शुरुआत कर दीं. ■

जमीन से आती हैं अजीबोगरीब आवाजें!

जब आपको अचानक अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे, तो आपका हैरान होना स्वाभाविक है. हो सकता है कि ऐसे में आप डर जाएं और इधर-उधर भागने लगें. इस समय कुछ ऐसा ही हाल ठाणे जिले के निवासियों का है. इस जिले के जव्हार इलाके में भू-गर्भ से अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं. गौरतलब है कि पिछले साल भी जव्हार तालुका के निवासियों ने ऐसी ही आवाजें सुनने का दावा किया था. कुछ दिनों पहले इन आवाजों के बारे में पता चलने के बाद नेवी की टीम ने इस इलाके का मुआयना भी किया था. सबसे बड़ी बात यह है कि ये आवाजें हर साल बारिश के मौसम में ही सुनाई देती हैं. जव्हार भूकंप का इलाका माना जाता है. जब से ये अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, तब से इस इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं. ■

सोमालिया

> सवाल यह है कि आख़िर प्राकृतिक संपदा से संपन्न इस देश के लोग निर्धनता के शिकार क्यों हैं? समझा जाता है कि यहां भुखमरी की वजह गृहयुद्ध और सूखे का क़हर है, लेकिन सच्चाई कुछ और नज़र आती है. इसे समझने के लिए हमें पश्चिमी देशों की औपनिवेशिक योजनाओं पर नज़र डालनी होगी. पश्चिमी शक्तियां हमेशा से इस्लामी दुनिया पर हावी होने, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर क़ब्ज़ा करने एवं आपस में लड़ाओ और राज करो की नीति पर काम करती रही हैं.

बदहाली की असल वजह

नेतृत्व का अभाव और बाहरी हस्तक्षेप

सोमालिया में प्राकृतिक संपदा एवं संसाधन बहुत हैं, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव और बाहरी हस्तक्षेप के चलते देश ग़रीबी के दलदल में फंसता चला गया. नतीजा यह हुआ कि आज वह दुनिया के सबसे निर्धनतम देशों में गिना जाता है.

वसीम अहमद

अफ्रीक़ा महाद्वीप का ऐतिहासिक राष्ट्र सोमालिया दुनिया में इसलिए भी जाना जाता है, क्योंकि पैग़ंबर मोहम्मद साहब का संदेश मक्का के बाद सर्वप्रथम जिस राष्ट्र में गया था, वह सोमालिया ही था. यह उस समय हब्शा कहलाता था. जब अरब में अत्याचार बढ़ा, तब मोहम्मद साहब के कुछ अनुयाइयों ने यहीं जाकर शरण ली थी और यहां के ईसाई राजा अस्महा बिन अबहर ने इन प्रथम मुस्लिम शरणार्थियों को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त दी थी. मोहम्मद साहब के अनुयाइयों ने जिस स्थान को अपनी शरणस्थली बनाया था, वह आज सोमालिया के शहर ज़ीला का हिस्सा है. सोमालिया की वर्तमान राजधानी मोगादेशू अफ्रीक़ा में इस्लाम का एक केंद्र थी, लेकिन अफसोस! जिस धरती ने मक्का के बाद सर्वप्रथम मोहम्मद साहब के अनुयाइयों को शरण दी, आज वहीं 99 प्रतिशत मुस्लिम आबादी भूख, प्यास और भयंकर सूखे की चपेट में है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, सोमालिया दुनिया के निर्धनतम देशों में से एक है, जबकि प्रकृति ने इसे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से मालामाल कर रखा है. यहां तेल, यूरेनियम, गैस एवं सोने की खानें बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, परंतु इसके बावजूद गत दो दशकों में 20 लाख लोग अनाज की कमी से तड़प-तड़प कर मर चुके हैं, जिनमें बच्चों की संख्या 30 हज़ार बताई जाती है.

सवाल यह है कि आख़िर प्राकृतिक संपदा से संपन्न इस देश के लोग निर्धनता के शिकार क्यों हैं? समझा जाता है कि यहां भुखमरी की वजह गृहयुद्ध और सूखे का क़हर है, लेकिन सच्चाई कुछ और नज़र आती है. इसे समझने के लिए हमें पश्चिमी देशों की औपनिवेशिक योजनाओं पर नज़र डालनी होगी. पश्चिमी शक्तियां हमेशा से इस्लामी दुनिया पर हावी होने, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर क़ब्ज़ा करने एवं आपस में लड़ाओ और राज करो की नीति पर काम करती रही हैं. 1980 के बाद इस्लामी दुनिया में तेज़ी से बदलता परिदृश्य और पश्चिमी ताक़तों का हस्तक्षेप इस बात को पुख्ता करता है. यूरोप ने प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न खाड़ी देशों में अपना प्रभाव इस तरह बढ़ाया कि तेल की अंतरराष्ट्रीय क़ीमतें तय करने का अधिकार पश्चिमी देशों के पास चला गया और तेल बाज़ार पर उनका क़ब्ज़ा हो गया. अगर किसी ने विरोध किया, तो उसका अंजाम होगा सत्ता से उसकी बेदखली या मौत. कुछ ऐसे भी इस्लामी देश थे, जहां प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन वे अपनी लोकेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे. जैसे अफगानिस्तान में तेल या सोने के भंडार तो नहीं थे, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण था. इसीलिए पहले रूस और फिर अमेरिका ने यहां के क़बायली तंत्र एवं उनकी पारंपरिक संस्कृति में सेंध लगाई. यह तय है कि पश्चिमी देशों ने इस देश को बेहद क्षति पहुंचाई.

दरअसल, पश्चिमी शक्तियां यह बात समझ रही थीं कि सोमालिया में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने से उन्हें दोहरा फ़ायदा होगा. एक ओर उन्हें यहां के 99 प्रतिशत मुसलमानों को उनके पारंपरिक रहन-सहन और इस्लामी पहचान से दूर करने का मौक़ा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों पर क़ाबिज़ होने का बहाना भी मिल जाएगा. इसलिए सोमालिया की सीमा से सटे ईसाई देश इथोपिया की मदद से ब्रिटेन, इटली एवं फ्रांस ने यहां का रुख़ किया और यहां की संपदा पर क़ब्ज़ा करने के लिए सबसे पहले कृषि व्यवस्था में परिवर्तन किया. दरअसल, खेती और पशुपालन सोमालिया के लोगों का मूल पेशा था. वे खेतों में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे. यही कारण था कि अगर कभी बारिश नहीं भी होती थी, तो उनके खेतों में इतना अनाज पैदा हो जाता था कि उनका गुज़र-बसर हो सके. इन तीनों देशों ने सबसे पहले उनके इसी मूल संसाधन पर घात लगाई और ऐसी कृषि व्यवस्था तय की कि ज़मीनें एक विशेष केमिकल की आदी हो गईं और फिर धीरे-धीरे उनमें विशेष प्रकार के अनाज पैदा करने की क्षमता ही शेष रह गई. यूनिसेफ के सर्वे के अनुसार, 68 प्रतिशत ज़मीन बंजर होने की प्रबल आशंका है. जब ज़मीन से हर प्रकार का अनाज पैदा होने की क्षमता ख़त्म हो गई, तो पश्चिमी देशों ने यहां खेतों में पैदा होने वाला अनाज कम दामों पर ख़रीद कर वैश्विक मंडियों में महंगे दामों में बेचने की ठेकेदारी भी ले ली. दूसरी ओर यहां बरसों तक बारिश नहीं हुई. नतीजतन, भीषण सूखा पड़ा और पैदावार लगभग ख़त्म हो गई. कुछ हिस्सों में घरेलू आमदनी केवल इतनी रह गई थी कि पीने का पानी हासिल किया जा सके. इस प्रकार सोमालिया समेत अफ्रीका के कई देश धीरे-धीरे ग़रीबी के दलदल में फंसते चले गए.

ग़रीबी की मार थी ही, पश्चिम के ठेकेदार अपनी साम्राज्यवादी नीतियों पर सख्ती से अमल कर रहे थे. अंजाम यह हुआ कि पूरा सोमालिया गृहयुद्ध के दलदल में फंसता चला गया. जब 1991 में जनरल मोहम्मद सादबरी को इथोपिया की मदद से अपदस्थ कर दिया गया, तो केंद्रीय सरकार की ग़ैर-मौजूदगी में विरोधी तत्वों को अराजकता का मौक़ा मिल गया और गृहयुद्ध में तेज़ी आ गई. लगभग पांच लाख लोग मारे गए और तीन लाख 20 हज़ार लोग बेघर हो गए. सूखे की वजह से पूरे देश में पानी और खाद्य सामग्री की कमी हो गई थी, इसलिए अमेरिका मानवीय हमदर्दी की बुनियाद पर भूखों को भोजन उपलब्ध करा रहा था, वहीं दूसरी ओर वह इस जुगत में था कि केंद्रीय सरकार गठित न हो. दरअसल, अगर केंद्रीय सरकार गठित हो जाती, तो सोमालिया में इथोपिया के हस्तक्षेप पर रोक लग सकती थी, क्योंकि इथोपिया की समुद्री आवश्यकता सोमालिया के बंदरगाह से पूरी होती है. अगर केंद्रीय सरकार होती, तो वह अपने बंदरगाह को सशर्त रूप में ही प्रयोग करने की अनुमति देती. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सोमालिया के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र इथोपिया के क़ब्ज़े में है, जिनकी वापसी की मांग शुरू हो जाती, इसलिए इथोपिया चाहता था कि सोमालिया में गृहयुद्ध का माहौल बना रहे, ताकि वह अपने अधिकारों को पुन: वापस पाने की स्थिति में न आ सके.

सोमालिया में इस्लामी पार्टियां अमेरिकी गतिविधियों का विरोध कर रही थीं. हालांकि उनके पास हथियारों की कमी थी, लेकिन लंबे गृहयुद्ध ने उन्हें लड़ना सिखा दिया था. इसके अलावा, उनकी एक बड़ी संख्या ओसामा बिन लादेन के साथ अफगानी जिहाद में शामिल होकर बाहरी सेना का सामना करने का हुनर सीख चुकी थी. इसीलिए उन्होंने अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन का बचाव किया. इन सबके बावजूद, उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं था, जो पश्चिमी ताक़तों के विरुद्ध उन्हें एक मंच पर एकत्र करता. आख़िरकार, एक इस्लामी संगठन के गठन पर विचार किया गया. इसमें वे लोग शामिल थे, जो अमेरिका के विरुद्ध अफगानिस्तान में जिहाद कर चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके लिए हथियारों की व्यवस्था कैसे हो और फंड कौन एकत्र करे? कहा जाता है कि ऐसे में, सोमालियाई लुटेरों एवं तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कबायलियों ने फंड एकत्र करने की ज़िम्मेदारी उठाई और 2004 में हरकतुल जिहाद अलमुजाहिदीन के नाम से एक संगठन गठित किया गया. इस संगठन ने इथोपियाई सेना का कड़ा विरोध किया और सोमालिया के कई क्षेत्रों, यहां तक कि मोगादेशू के उत्तरी भाग पर क़ब्ज़ा करके वहां इस्लामी हुकूमत स्थापित कर दी.

इस्लामी उदारवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ऐसा माना जाता रहा कि अब सोमालिया में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन इस चुनाव से अलशबाब के लड़ाके संतुष्ट नहीं हैं. वे अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का विचार है कि अलशबाब की तहरीक अब दम तोड़ चुकी है और वह बुझते चिराग़ की लौ की तरह है. देश में सरकार तो बन चुकी है, लेकिन इस समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सोमालिया में गृहयुद्ध की शुरुआत ग़रीबी की वजह से हुई थी, जो अब भी बरकरार है. अगर ग़रीबी उन्मूलन को लेकर उचित प्रयास न किए गए, तो सोमालिया एक बार फिर गृहयुद्ध के दलदल में फंस जाएगा. सोमालिया के लोग खेती एवं पशुपालन के साथ-साथ मांस एवं दुग्ध उत्पादों में भी अच्छा अनुभव रखते हैं. इसलिए वहां निवेश के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं. मछली, मक्का एवं ज्वार के मामले में सोमालिया आत्मनिर्भर है, सिर्फ़ थोड़ी दक्षता की कमी है. अगर भारत जैसा देश सोमालिया में निवेश करे, तो न केवल उसे आर्थिक फ़ायदा होगा, बल्कि सोमालिया की ग़रीबी भी दूर हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूटान चुनाव

भूटान-चीन : बढ़तीं नजदीकियां

नई सरकार कितनी भरोसेमंद

पीडीपी ने भूटान नरेश की क़रीबी समझी जाने वाली पार्टी डीपीटी को हरा दिया है. पूरे चुनाव के दौरान भारत के साथ संबंधों का मुद्दा छाया रहा, जो आने वाले दिनों में भारत-भूटान संबंधों को निर्णायक दौर में पहुंचा सकता है, क्योंकि भूटानी अवाम को भारत की अनदेखी पसंद नहीं.

राजीव रंजन

भूटान में विपक्षी दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने सत्तारूढ़ पार्टी द्रुक फुएनसम त्शोंगपा (डीपीटी) को हरा दिया है. डीपीटी भूटान नरेश की क़रीबी समझी जाने वाली पार्टी है. ऐसे में उसकी हार देश के लिए दूरगामी परिणाम वाली साबित होगी. दूसरी ओर, एक बात भारत के संदर्भ में गौर करने लायक है कि ऐसा पहली बार है कि किसी देश के चुनाव में भारत के साथ संबंधों और उनमें सुधार का मुद्दा छाया रहा. इसने भूटान की राजनीति में यह तय कर दिया कि भूटानी अवाम को भारत की अनदेखी पसंद नहीं है. ग़ौरतलब है कि भारत ने हाल में भूटान को दी जाने वाली तेल एवं गैस सब्सिडी में कमी की थी, जो कि भूटान की सत्तारूढ़ पार्टी की हार का प्रमुख कारण बनी. भारत के इस क़दम के बाद भूटान में यह अनुमान लगाया जाने लगा कि भारत ने यह क़दम चीन से भूटान की बढ़ती नज़दीकियों के मद्देनज़र उठाया है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चुनाव से ऐन पहले सब्सिडी हटाकर भारत ने सही नहीं किया. लोगों का मानना है कि कहीं भारत के भूटान से संबंध नेपाल की तरह न हो जाएं, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकता. हाल में भूटान ने चीन के साथ जो गर्मजोशी दिखाई थी, उसे देखते हुए भारत के सब्सिडी हटाने जैसे क़दम को भूटान को सतर्क करने के एक प्रयास के रूप में ही देखना चाहिए.

भारत का आश्वासन

भारत द्वारा भूटान को किरोसिन तेल एवं रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी कम करने की घटना को स्थानीय मीडिया या भूटानियों ने चाहे जिस रूप में लिया हो, लेकिन यह सत्य है कि भारत की खुद की आर्थिक चिंता ने उसे भूटान के प्रति ज़्यादा उदार होने से रोका, अन्यथा भारतीय प्रधानमंत्री भूटान के चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद पीडीपी अध्यक्ष शेरिंग तोगबे को बधाई देने के साथ ही भारत की ओर से दी जाने वाली मदद हमेशा की तरह जारी रखने का आश्वासन क्यों देते. भारत ने यह भी कहा है कि वह भूटान को किसी कठिनाई में फंसने नहीं देगा और नई सरकार के साथ रियायत के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी. हालांकि हर देश की अपनी विदेश नीति होती है और अगर भारत अपनी विदेश नीति के तहत चीन से भूटान की क़रीबियां नहीं चाहता, तो भूटान को भी चाहिए कि वह भारत और चीन से अपने रिश्तों को इस प्रकार से लेकर चले कि उसके हित प्रभावित न हों.

भारत की अनदेखी संभव नहीं

पीडीपी की जीत का प्रमुख कारण भारत के साथ रिश्तों और उनमें सुधार का मुद्दा रहा है, जिसे वह अपने चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा दोहराती रही. दूसरी ओर डीपीटी की हार की वजह भी भारत के साथ रिश्तों को लेकर उदासीनता और चीन से बढ़ती नजदीकियां हैं. ऐसे में पीडीपी यह बात भलीभांति समझ गई है कि भारत के साथ संबंध खराब करना या चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाना जनमत के साथ धोखा होगा. भूटान का क़रीब 60 फ़ीसद निर्यात भारत के बाज़ारों

में पहुंचता है और उसके कुल आयात का 75 फ़ीसद अकेले भारत से जाता है. ऐसे में भूटान पुरानी गलतियां कभी नहीं दोहराएगा. तेल एवं गैस सब्सिडी को फिर से हासिल करना भी भूटान का प्रमुख उद्देश्य होगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति यह सब्सिडी रोक देने के कारण खराब हो गई है और अगर यह सब्सिडी हासिल करने में कुछ दिन और भूटान सरकार ने देरी कर दी, तो उसके आर्थिक हित बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे. आर्थिक मंदी, विदेशी कर्ज, बढ़ती ग़रीबी एवं बेरोजगारी भी भूटान की प्रमुख समस्याएं हैं, जिन्हें नई सरकार जल्द से जल्द नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगी, जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. पीडीपी ने कहा है कि उसकी सरकार भारत से आर्थिक राहत पैकेज के लिए भी अनुरोध करेगी. ऐसे में भूटान कभी नहीं चाहेगा कि उसके संबंध भारत जैसे देश से खराब हों. खास तौर पर ऐसे भारत से, जो पिछले कई दशकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर उसका भाग्य विधाता रहा हो.

क्या करे भारत

भारत को भी अपने इरादों से जुड़ी आशंकाएं दूर करने के लिए भूटान में पनप रहे लोकतांत्रिक फैलाव को समझना चाहिए. इस समय ज़रूरत इस बात की भी है कि भारत भूटान को यह राजनीतिक संदेश भेजे कि वह चीन द्वारा उसे अपनी ओर आकर्षित करने से खुद को असुरक्षित नहीं समझता, बल्कि वह तो सिर्फ़ भूटान को अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता है. विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि भारत द्वारा चुनाव से ऐन पहले सब्सिडी ख़त्म करने से भूटान में नेपाल की तरह भारत विरोधी भावनाएं लगातार मजबूत होती जाएंगी. अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई है, तो भारत-भूटान संबंध की मिठास ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकती. ऐसे में भारत को चाहिए कि वह अपनी विदेश नीति में सतर्कता, गंभीरता एवं दूरदर्शिता अपनाए. भारत को न केवल भूटानियों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि ऊर्जा, मदद एवं रक्षा मामलों में उसकी भारत पर निर्भरता कम करने का प्रयास भी करना चाहिए. भूटान पवन एवं सौर या अन्य वैकल्पिक ऊर्जा पैदा कर सकता है. भारत उसके वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन में निवेश करके महत्वपूर्ण ढंग से मदद कर सकता है. भारत के इस क़दम से भूटान आत्मनिर्भर हो सकता है, जिससे भारत की ज़िम्मेदारी भी कम होगी और जब भूटान आत्मनिर्भर होगा, तो उसका झुकाव भी चीन की तरफ़ कम होगा.

पीडीपी के सामने चुनौती

पीडीपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूटान का आर्थिक पुनरुत्थान है. भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण भूटान में खाद्य पदार्थों, ईंधन, निर्माण-सामग्रियों, सौंदर्य-प्रसाधनों एवं खाद्य तेल की क़ीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. भारी विदेशी कर्ज भी उसकी एक बड़ी परेशानी है. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 में भूटान पर विदेशी कर्ज लगभग एक अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर था. आर्थिक मंदी, बढ़ती ग़रीबी एवं बेरोज़गारी भी नई सरकार के लिए एक चुनौती होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्यों हारी डीपीटी

- भारत द्वारा तेल एवं रसोई गैस सब्सिडी हटा लेना.
- भारत के साथ संबंधों में उदासीनता भूटानी अवाम को पसंद नहीं.
- चीन से भूटान की नजदीकियां बढ़ना.
- डीपीटी का भ्रष्टाचार, ज़मीन घोटाले, औद्योगिक लाइसेंस मिलने में अनियमितताएं.
- आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी एवं विदेशी कर्ज.
- आधुनिकीकरण पर जोर नहीं.
- पीडीपी का जनता के क़रीब होना और विकास की व्यवहारिक नीतियां.

साई

आस्था

दरअसल

> एक बार श्रीमती तर्खड शिरडी आईं. दोपहर का भोजन प्राय: तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थीं कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा. श्रीमती तर्खड तुरंत उठीं और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया. कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया.

बाबा का अमृत समान उपदेश

नि:स्वार्थ सेवा करो

बाबा ने कहा था कि जो लोग भेद-भाव भूल कर मेरी सेवा नि:स्वार्थ करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं. आइए जानते हैं कि बाबा ने ये बातें कब और किस परिस्थिति में कहीं थीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक बार श्रीमती तर्खड ने तीन वस्तुएं, यानी भरित (भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही), काचर्या (बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए) और पेड़ा (मिठाई) बाबा के लिए भेजीं. बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया, इसे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा. बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे. एक बार वह शिरडी जा रहे थे. श्रीमती तर्खड ने श्रीमती पुरंदरे को दो बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वह एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें. शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गईं. बाबा उसी समय भोजन के लिए बैठे ही थे. उन्हें भुर्ता बहुत स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा-थोड़ा सभी को वितरित भी किया. इसके पश्चात राधाकृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचर्या मांग रहे हैं. वह असमंजस में पड़ गईं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बैगन की तो अभी ऋतु नहीं है. अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो. जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थीं और फिर उन्हें ही काचर्या बनाने का कार्य सौंपा गया. अब हर आदमी को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ.

दिसंबर, 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे. प्रस्थान करने से पूर्व वह श्रीमती तर्खड से मिलने आए. श्रीमती तर्खड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थीं. उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था. फिर भी अति प्रेम के कारण उन्होंने वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया. उन्हें पूरा विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे. शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए. बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब गोविंद पुन: संध्या समय बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे, तो फिर बाबा शांत न रह सके और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं. बाबा ने पुन: प्रश्न किया और गोविंद ने फिर वही उत्तर दोहरा दिया. अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें मां (श्रीमती तर्खड) ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब गोविंद को स्मृति हो आई. वह बहुत लज्जित हुए और बाबा से क्षमायाचना करने लगे. दौड़कर गए और उन्होंने फिर पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया. बाबा ने तुरंत पेड़ा खा लिया. इस प्रकार श्रीमती तर्खड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और कहा कि भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं, यह भगवद् वचन भी सत्य साबित हुआ.

एक बार श्रीमती तर्खड शिरडी आईं. दोपहर का भोजन प्राय: तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थीं कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा. श्रीमती तर्खड तुरंत उठीं और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया. कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया. संध्या के समय जब श्रीमती तर्खड मस्जिद में जाकर बैठीं, तो बाबा ने उनसे कहा-मां, आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली. सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा. इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा. सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो. पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन

करो. इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो. बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूं, मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूं और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूं. बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं. भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था. इसी प्रकार अन्य प्राणी (बिल्लियां, सुअर, मक्खियां, गाय आदि) भी मेरे ही स्वरूप हैं. मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं. जो इन सब प्राणियों में मेरे दर्शन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है. इसलिए भेद-भाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो. यह अमृत समान उपदेश ग्रहण कर वह द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा.

जो बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते...

एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पाकर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए. उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया. वह तो बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर उनके कर-कमलों का चुंबन करना चाहते थे. इसी कारण उन्होंने तीन बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया. उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली. इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के लिए वह वहां आए. बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी.

अन्य भक्तों ने भी उस यूरोपियन व्यक्ति से बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वह सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए. कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक-ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक साइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और तेज गति से दौड़ने लगे. फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ-साथ घिसटते चले गए. उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो लोग बाबा के आदेशों की अव-हेलना करते हैं, उन्हें किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है और जो आज्ञा का पालन करते हैं, वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं.

शिक्षा

समस्त प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है. उपनिषदों एवं गीता का यही उपदेश है कि ईशावास्यमिदं सर्वम् यानी सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

चिदंबरम मंदिर

शिव का मंगलमय और अलौकिक रूप

चिदंबरम मंदिर भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है. यहां नटराज शिव की नृत्य मुद्रा मनमोहक है. भारत में बहुत कम ऐसे मंदिर हैं, जहां शिव और वैष्णव दोनों मंदिर एक ही स्थान पर प्रतिष्ठित हैं. चिदंबरम मंदिर में आकर आप इस अलौकिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं.

कैफी रज़ा

चिदंबरम मंदिर दक्षिण भारत के पुराने मंदिरों में से एक है, जो एक हिंदू मंदिर है. यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 245 किलोमीटर दूर चेन्नई-तंजावुर मार्ग पर स्थित है. इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने आनंद नृत्य की प्रस्तुति यहीं की थी, इसलिए इस जगह को आनंद तांडव के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. मंदिर के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह भारत के पांच पवित्र शिव मंदिरों में से एक है. मंदिर शहर के मध्य में स्थित है. इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. यह मंदिर भगवान शिव के एक अन्य रूप नटराज और गोविंदराज पेरुमल को समर्पित है, जो अति प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है. इस मंदिर के बारे में लोग यही कहते हैं कि देश में बहुत कम मंदिर ऐसे हैं, जहां शिव व वैष्णव दोनों देवता एक ही स्थान पर प्रतिष्ठित हैं. मंदिर में कुल नौ द्वार और चार पगोडे या गोपुरम हैं.

नटराज शिव का विशेष आकर्षण

नटराज शिव की मूर्ति मंदिर की एक अनूठी विशेषता है. नटराज आभूषणों से लदे हुए हैं, जिनकी छवि अनुपम है. यह मूर्ति भगवान शिव को भरतनाट्यम नृत्य के देवता के रूप में प्रस्तुत करती है. बताया जाता है कि यह उन कुछ मंदिरों में से एक है, जहां शिव को प्राचीन लिंगम के स्थान पर मानवरूपी मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है. मंदिर में पांच आंगन हैं. शिव के नटराज स्वरूप के नृत्य का स्वामी होने के कारण भरतनाट्यम के कलाकारों में भी इस जगह का कुछ खास महत्व है.

मंदिर की बनावट इस तरह है कि इसके हर पत्थर और खंभे पर भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं अंकित हैं. मंदिर के केंद्र और अम्बलम के सामने भगवान शिवकाम सुंदरी (पार्वती) के साथ स्थापित हैं. मंदिर की अन्य खासियतों में शुमार है चिदंबरम मंदिर का रहस्य. इस रहस्य को जानने के लिए आपको एक तय राशि यहां देनी पड़ती है. मंदिर की देख-रेख और पूजा-पाठ पारंपरिक पुजारी करते हैं. हालांकि सारा प्रबंधन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे और दान के रूप में दिए गए धन से ही होता है. मंदिर शिव क्षेत्रम के रूप में भी प्रसिद्ध है.

गोविंदराज मंदिर

चिदंबरम मंदिर

गोविंदराज और पंदरीगावाल्ली का मंदिर भी चिदंबरम मंदिर के इसी भवन में स्थित है, जो शिव के बिल्कुल निकट स्थापित हैं. मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब और नृत्य परिसर भी है. यहां हर साल नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से कलाकार हिस्सा लेते हैं.

पांच सभाओं वाला हॉल

पांच सभाओं वाला हॉल भी यहां देखने लायक है, जो देवी-देवताओं के संसार में विचरण करने के लिए बाध्य कर देता है. यहां भगवान नटराजन अपने सहचरी के साथ रहते थे. दक्षिणी मान्यता के अनुसार, भगवान देवी काली के साथ यहीं नृत्य किया करते थे. मंदिर के चारों ओर जल सरोवर भक्तों को शीतलता का एहसास कराता है.

भगवान नटराजन का रथ

आपको यहां आने पर उस रथ का दर्शन भी हो जाएगा, जिस पर भगवान नटराजन साल में दो बार चढ़ा करते थे. उसी रथ को भक्तों द्वारा त्योहारों के दिन खिंचा जाता है. उस समय रथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है.

आनंद तांडव मुद्रा

भगवान शिव की आनंद तांडव मुद्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. यह नृत्य मुद्रा हमें यह बताती है कि किसी नर्तक या नर्तकी को कैसे भरतनाट्यम नृत्य करना चाहिए.

कुछ किंवदंतियां

ऐसा दावा किया गया है कि मूल रूप से यह मंदिर भगवान श्री गोविंद राजास्वामी का निवास था और भगवान शिव अपनी सहचरी के साथ उनसे संपर्क करने आए थे, जिससे कि वह युगल जोड़े के मध्य नृत्य प्रतिस्पर्धा के निर्णायक बन जाएं. भगवान गोविंद राजास्वामी इस बात पर सहमत हो गए और और शिव और पार्वती दोनों के मध्य बराबरी पर नृत्य प्रतिस्पर्धा चलती रही. दरअसल, इसी दौरान भगवान शिव विजयी होने की युक्ति जानने के लिए श्री गोविंद राजास्वामी के पास गए और उन्होंने संकेत दिया कि वह अपने एक पैर से उठाई हुई मुद्रा में नृत्य कर सकते हैं. महिलाओं के लिए, नाट्यशास्त्र के अनुसार, यह मुद्रा वर्जित थी, इसीलिए जब अंततः भगवान शिव इस मुद्रा में आ गए, तो पार्वती ने पराजय स्वीकार कर ली और इसीलिए इस स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति नृत्य मुद्रा में है.

ठहरने का उत्तम प्रबंध

ठहरने के लिए यहां होटलों और धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है. खाने-पीने के लिए रेस्टोरेंट भी बहुत हैं, जहां दक्षिण भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां खाना-पीना भी किफायती है.

कैसे पहुंचें?

चेन्नई-तंजावुर मार्ग पर चेन्नई से 245 किमी दूर है चिदंबरम. रेलवे स्टेशन भी चिदंबरम नाम से ही है. अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहें, तो किसी भी वाहन से चेन्नई से 4 से 5 घंटे में चिदंबरम पहुंच सकते हैं. चेन्नई नजदीकी एयरपोर्ट है. यहां से बस या ट्रेन के जरिये चिदंबरम पहुंचा जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दरअसल

गलती का एहसास

दिलीप कुमार

भारत ऋषि-मुनियों का देश है. यहां एक से बढ़ कर एक संत पैदा हुए. सभी संत यही कहते थे कि यदि अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया, तो सब कुछ प्राप्त कर लिया. अहंकार पर विजय से संबंधित एक छोटी सी कहानी याद आई .

देवराज ऋषि के आश्रम में कई शिष्य उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे. इन शिष्यों में इंद्र बहुत होनहार शिष्य थे, इसलिए देवराज ऋषि उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इंद्र को इस बात का अहंकार होने लगा. इसीलिए दूसरे शिष्यों को हीन समझकर उनके साथ इंद्र बुरा व्यवहार करने लगे. ऋषि देवराज को इस बात का एहसास हुआ. गुरु के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन ऋषि देवराज को लगा कि इस शिष्य की सोच को बदलना जरूरी है और संसार को एक उदाहरण पेश करना है.

एक दिन वह इंद्र को सागर किनारे ले गए. इंद्र को प्यास लगी, तो ऋषि देवराज ने उन्हें सागर का जल पीने को कहा. मुंह से लगाते ही शिष्य ने पानी मुंह से बाहर फेंक दिया. उसने गुरुजी से कहा कि यह पानी न केवल खारा और कसैला है, बल्कि विष है इस पानी में. अब गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए. नदी का निर्मल जल तेजी से कल कल बह रहा था. अब गुरुजी ने शिष्य को नदी का पानी पीने के लिए कहा. इंद्र ने नदी का जल पिया. जल पीते ही उसने शांति का अनुभव किया. दरअसल, जल मुंह में डालते ही इंद्र को अत्यंत तृप्ति हुई. शिष्य ने कहा कि इतना ठंडा, स्वच्छ और शीतल जल हमें तो आज तक नहीं मिला!

अब ऋषि ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि इंसान अगर खारा, अहंकारी, कटु भाषी और कसैला होता है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते, बल्कि उससे सभी दूर भागते हैं, लेकिन यदि इंसान शीतल, सरल और मिलनसार होता है, तो सभी उससे मिलने को आतुर रहते हैं. गुरु ने समझाया कि रावण इतना बड़ा पंडित था, लेकिन चूंकि अहंकारी भी था, इसीलिए उसका पतन हुआ. अहंकार को कभी भी पास फटकने नहीं देना चाहिए. इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया. आश्रम लौटने के बाद इंद्र पूरी तरह से बदल चुके थे.■

feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

> फिल्म समीक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हिंदी में अब तक सिर्फ़ दो लोगों, ब्रजेश्वर मदान और विनोद अनुपम को ही मिल पाया है, जबकि हिंदी में इस वक्त फिल्म समीक्षा लिखने वाले सैकड़ों लोग होंगे.

कविता

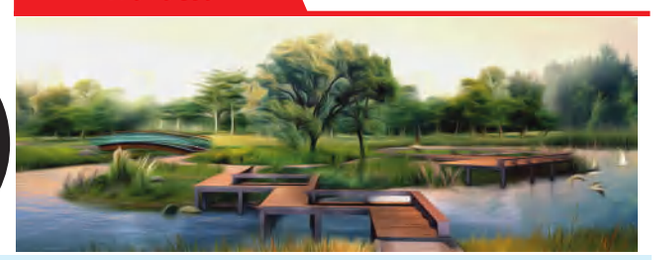

फिल्मी पोस्टरों से बनता इतिहास

फिल्मी पोस्टरों में पहले शीर्षक ज़्यादातर रोमन में लिखे जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में बनी फिल्मों के पोस्टरों में हिंदी का प्रयोग बताता है कि बॉलीवुड में अब हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है. यह एक अच्छा संकेत है.

अनंत विजय

हिंदी सिनेमा के सौ साल पूरे होने के शोरगुल के बीच सिनेमा के पोस्टरों पर बेहद कम बात हुई. कुछ ही लोगों ने पोस्टरों के इतिहास पर लिखा एवं परखा. हिंदी सिनेमा का यह बेहद अहम पक्ष है, जिस पर बेहद गंभीरता से बात होनी चाहिए थी, लेकिन हिंदी के विद्वानों के लिए सिनेमा पर लिखना ही अस्पृश्यता के बराबर है, इसलिए पोस्टरों पर लिखने में वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं. मेरठ से छपने वाले लोकप्रिय उपन्यासों की तरह सिनेमा भी उन्हें सस्ती एवं चलताऊ विधा लगती है. खासकर, मार्क्स बाबा के अनुयायियों को तो सिनेमा से एक खास एलर्जी है. यह बेहद चिंता की बात है कि हिंदी में सिनेमा पर गंभीर काम हुआ ही नहीं. यह बात फिल्म समीक्षा से लेकर फिल्म लेखन तक लागू होती है. फिल्म समीक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हिंदी में अब तक सिर्फ़ दो लोगों, ब्रजेश्वर मदान और विनोद अनुपम को ही मिल पाया है, जबकि हिंदी में इस वक्त फिल्म समीक्षा लिखने वाले सैकड़ों लोग होंगे. इस बारे में हिंदी समाज को गंभीरता से सोचना होगा. इसके अलावा, फिल्म की तकनीक पर भी हिंदी में चुनिंदा किताबें ही मौजूद हैं. खैर, यह एक अवांतर प्रसंग है, जिस पर कभी निश्चिंतता से चर्चा होगी.

हम इस लेख में बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पोस्टरों की. 3 मई, 1913 को जब पहली हिंदी फिल्म–हरिश्चंद रिलीज हुई, तो उसके प्रचार–प्रसार के लिए कोई पोस्टर नहीं बना था. केवल अख़बारों में उसके विज्ञापन छपे थे और सिनेमा हॉल के बाहर पर्चा बंटा था, जिसमें फिल्म के बारे में जानकारी दी गई थी. सिनेमा हॉल के बाहर बांटे गए उस पर्चे में भी चित्र का उपयोग नहीं हुआ था. माना जाता है कि हिंदी फिल्मों का पहला पोस्टर 1920 में बाबू राव पेंटर ने अपनी पहली फिल्म–वत्सला हरण के लिए बनाया था. बाद में हिंदी फिल्मों के हाथ से बने पोस्टर खूब चलन में आए, लेकिन उन पोस्टरों के शीर्षक भी ज़्यादातर रोमन में ही लिखे जाते रहे. मशहूर पेंटर एम एफ हुसैन ने भी फिल्मी पोस्टरों पर हाथ आजमाए थे. साठ के दशक तक तो हिंदी फिल्मों के पोस्टरों पर अनिवार्य रूप से शीर्षक रोमन के साथ–साथ उर्दू में भी लिखा जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरेफिल्मी पोस्टरों से उर्दू गायब होती चली गई. इसकी वजह वह नहीं है, जो देवनागरी या हिंदी के स्थापित होने की है. कुछ लोग इसे सांप्रदायिकता से भी जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, जो कि निहायत बेवकूफाना तर्क और सोच है. उर्दू गायब होने की वजह इतर है और उसकी चर्चा यहां अवांतर होगी. फिल्मों के ज़्यादातर पोस्टर रोमन में बनाए जाते थे.

दरअसल, रोमन में पोस्टर की डिजाइनिंग देवनागरी

लिपि से अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है. हिंदी में मात्राओं की वजह से डिजाइन बनाने में दिक्कतें आती हैं. कालांतर में फिल्मों की मार्केटिंग करने वालों को भी यह बात समझ में आई और इस दिक्कत को चैलेंज के रूप में लेकर उस पर काबू पाने के लिए नई तकनीक विकसित की गई. सिनेमा को जनता तक पहुंचाने का पहला और सबसे आसान माध्यम पोस्टर ही रहा है. कंप्यूटर क्रांति और प्रिंटिंग में नई तकनीक आने के पहले तो पोस्टर हाथ से बनाए जाते थे, फिर उसे छपवा लिया जाता था. पोस्टरों के बाद फिल्म के बैनरों का दौर आया, जिनमें फिल्मों के कुछ रोचक सीन्स छापे जाने लगे, लेकिन तब भी रोमन का साम्राज्य कायम रहा. पहले यह माना जाता था कि देश के अंग्रेजी दां लोगों के पास ही पैसा खर्च करने की क्षमता है, लिहाजा उनकी पसंद को ध्यान में रखकर हिंदी फिल्मों के पोस्टर एवं बैनर भी रोमन में बनाए जाते थे.

श्रीदेवी एवं जितेंद्र की हिम्मतवाला जैसी खालिस हिंदी दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म के पोस्टर भी रोमन में लिखे गए थे. सुपर हिट फिल्म शोले का भी पहला पोस्टर रोमन में ही लिखकर आया था. रोमन में लिखे उस पोस्टर की कैलीग्राफी अब भी दर्शकों के दिमाग में ताजा है. राजश्री प्रोडक्शन जैसी फिल्म निर्माण कंपनियों, जिनके पोस्टर से लेकर कास्टिंग तक पहले हिंदी में हुआ करती थी, ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए रोमन एवं अंग्रेजी का दामन थाम लिया था, लेकिन हाल के दिनों में बॉलीवुड में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है. हिंदी फिल्मों में खालिस हिंदी पट्टी से आने वाले विशाल भारद्वाज एवं अनुराग कश्यप जैसे निर्देशकों की जो नई खेप आई है, उसने हिंदी को बेहद मजबूती से बॉलीवुड में स्थापित किया है. उनकी फिल्मों के पोस्टर भी ज़्यादातर हिंदी में ही बनते हैं. यही नहीं, संवादों में भी एक देसीपन होता है. आर्थिक उदारवाद की बयार के बाद हिंदीभाषी लोगों की क्रय क्षमता या कहें कि खर्च करने की क्षमता में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है. विनोद अनुपम के तर्कों में दम है. हिंदी पट्टी के लोगों की क्रय क्षमता में बढ़ोत्तरी के बाद हमारे देश में बाज़ार का व्याकरण पूरी तरह से बदल गया. हिंदी के लोगों ने समाज की हर चीज को प्रभावित करना शुरू कर दिया. हिंदी पट्टी के लोग विचार, समाज एवं संसाधन, तीनों को प्रभावित करने लगे. इस बढ़ते प्रभाव को बाज़ार ने फौरन भांप लिया. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लगा कि विशाल हिंदीभाषी जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए उनकी भाषा में उन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया जाए और उसी भाषा में ही बाज़ार उनसे संवाद करे, लिहाजा हिंदी को तवज्जो दी गई.

बाज़ार को भांपते हुए संजय लीला भंसाली एवं पंकज कपूर जैसे पुराने लोगों ने भी हिंदी की ताकत पहचानी और उसमें काम करने की शुरुआत की. पंकज कपूर ने जब मटरू की बिजली का मंडोला बनाई, तो उसके पोस्टर की बहुत तारीफ़ हुई थी. देवनागरी लिपि में बेहतरीन ढंग से लिखे गए अक्षरों ने दर्शकों के साथ–साथ फिल्म समीक्षकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया. अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म राउडी राठौर के पोस्टर भी देवनागरी लिपि में लिखे गए थे. फिल्म राउडी राठौर के पोस्टर तो हिंदी में तैयार किए ही गए, साथ ही साथ फिल्म के प्रमोशन के लिए पोस्टरों पर हिंदी की बेहद चलताऊ लाइनें–नया साल, नया माल, फौलाद की औलाद आदि लिखी गईं. पोस्टरों में हिंदी के बढ़ते चलन से एक बात साफ़ हो गई है कि बॉलीवुड में भी हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है. कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन ने भी कान फिल्म महोत्सव में अपना भाषण हिंदी में देकर हिंदीभाषियों का दिल जीत लिया था. इसके लिए बिग बी की जमकर तारीफ़ भी हुई थी. अब वक्त आ गया है कि हिंदी के साहित्यकार भी फिल्मों को गंभीरता से लें और फिल्म लेखन को एक गंभीर विधा के रूप में विकसित करें. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कविता

अशयार

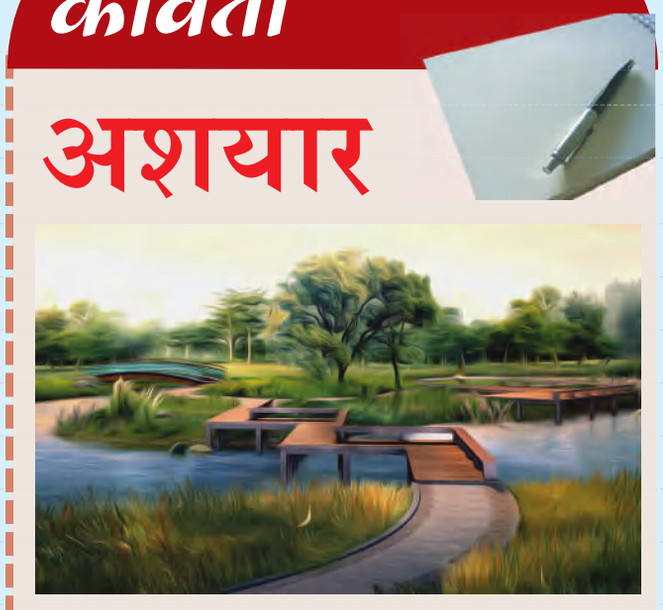

अक्षय जैन

प्लानिंग कमीशन करेगा, कमाल इस बरस भी,
खोलेगा प्रसूति गृह, किन्नरों की बस्ती में!

कयामत के आने का अब इंतजार क्या करना,
जब जिंदगी गुजार दी, बिना किसी मकसद के!

दरवाजा खुला रखना, इंक़लाब आया है,
रिजर्वेशन तो नहीं मिला, तत्काल में आया है!

पहले से बताकर आज तक नहीं आया,
तूफान को नहीं आता, एसएमएस करना!

वह बोलता नहीं है और सुनता भी नहीं है,
जरूर वजीर ए आजम के खानदान का होगा!

(लेखक दाल–रोटी के संपादक हैं)

नरभक्षी

इस बसर से खेतों का बसर भला,
कृषक का ध्यान रखे बनकर लल्ला,
चलती फिरती लाशें हैं ये,
नरभक्षी बन काटते हैं गला!

जिस वन से आया ये वन मानुष,
उसी वन को है इससे शिकवा गिला,
घर में ओछा हुआ चौपाया,
खूंखार जानवरों को बहुत खला
घनश्याम बेलानी

–घनश्याम बेलानी

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
जुलाई की एक रात	दुष्यंत
प्रकाशक	**मूल्य**
पेंगुइन बुक्स	125 रुपये

दुष्यंत ने बेहद सुंदरता से अपने वर्तमान का यथार्थ और समय का सच्चा इतिहास लिखा है. पुस्तक आधुनिक जीवन के तनावों और अंतर्विरोधों के वैचारिक टकराव को खंगालती है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

विस्थापन की मनोव्यथाएं

इस पूरी किताब में जिस तरह से एक के बाद एक घटना सामने आती है, वह सचमुच उपन्यास को बांधने में सक्षम है. एक बूढ़े व्यक्ति का जिस तरह से वर्णन किया गया है, वह सचमुच अकल्पनीय है. ऐसा लगता है कि लेखक खुद एक यायावर हैं और उन्होंने अपने ही पात्र को जीवन देने की कोशिश की है. यह एक ऐसे यायावर की कहानी है, जो सौम्य है, तरोताजा है और इसीलिए हमेशा नाश्ते के लिए तैयार रहता है.

निर्मलेंदु

इस उपन्यास का मुख्य हिस्सा अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, जहां यूगांडा या रवांडा जैसी एक जगह है. इसके दो मुख्य किरदार अंग्रेज हैं. उपन्यास का विषय है, विस्थापन अर्थात् किसी और की भूमि पर एक अच्छी जगह की इच्छा रखना. और दरअसल, इसी से जुड़ी हुई हैं मनोव्यथाएं. इसकी कहानी न केवल कसी हुई है, बल्कि हैरतअंगेज रूप से बुनी हुई है. हालांकि इसकी औपचारिक और सटीक भाषा हमेशा हिंसा और गुस्से के साथ सहज भी लगती है. लेखक हैं प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता वी एस नायपॉल. कहानी कुछ इस तरह से है. वाशिंगटन में एक भारतीय नौकर एक अमेरिकी नागरिक बन जाता है. उसे एक दिन महसूस होता है कि वह अब अपने वतन का हिस्सा नहीं रहा. कत्ल के इल्जाम में लंदन की एक जेल में रह रहा यह बेचैन वेस्ट इंडियन कभी नहीं जान पाता कि वह सचमुच कहां है. हमने पहले ही बताया है कि उपन्यास के दोनों किरदार अंग्रेज हैं. दरअसल, दोनों बिंदास और दीन–ओ–दुनिया से बिल्कुल बेख़बर. एक समय वह था, जब इन दोनों को अफ्रीका में मुक्ति का आभास हुआ था. हालांकि बाद के दिनों में उनकी बेचैनी और बढ़ती ही चली गई. उन्हें लगा कि अफ्रीका उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है और इसीलिए उन्हें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी.

यह एक यायावर की कहानी है. वह यायावर जब घाट पर उतरा, तो वह ठेठ अंग्रेज ही लग रहा था. शायद इसलिए भी वह अंग्रेज लग रहा था, क्योंकि जहाज पर यायावर के सिवा और कोई अंग्रेज था ही नहीं. आप उसे घुमक्कड़ भी नहीं कह सकते. मझोले कद का एक दुबला, पतला इंसान था वह. चलते समय वह अपने नन्हे–नन्हे क़दम लचकदार तरीके से ज़मीन पर रखता. उसके तमाम पहनावे तार–तार हो रहे थे. उसके स्कार्फ की गांठ भी एकदम कसी और चिपचिपी हो चली थी. जी हां, वह एक यायावर ही था. दरअसल, बहुत पास आने पर एहसास हुआ कि वह एक डरे–सहमे, थके–हारे चेहरे और नम आंखों वाला एक बूढ़ा इंसान था.

लेखक अपनी पीठ दरवाजे की ओर किए बैठा था, इसलिए वह देख नहीं पाया कि यायावर कब अंदर आया. सामने एक जर्मन लड़की बैठी थी. अचानक वह बूढ़ा यायावर लेखक के सामने आ गया. एक कुर्सी पर बैठा, जिस पर से अभी–अभी कोई उठकर गया था. वह अपने बुढ़ाते पांव फैला कर बैठा था. उसकी भारी–भरकम जैकेट उसकी पतलून की फूली हुई जेबों पर झूल रही थी. अचानक उसने अपनी जेब से एक मैग्जीन निकाली. मैग्जीन को उसने चार तहों में मोड़–मोड़ कर अपनी जांघ के नीचे छिपा दिया और अपनी जेब से डायरी निकाल कर पढ़ने लगा. फिर वह हंसने लगा. थोड़ी देर बाद उसने अपनी निगाहें ऊपर कीं, शायद यह देखने की कोशिश कर रहा था यायावर कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है! फिर एक पेज पलट कर वह पढ़ने लगा. अब फिर से हंसने लगा और ज़्यादा जोर से पढ़ने लगा. अब वह जर्मन लड़की की ओर झुका और अपने कंधे उचका कर उससे बोला, क्या आप स्पैनिश पढ़ सकती हैं? जर्मन लड़की ठिठक कर बोली, नहीं. यायावर अपनी मैग्जीन वापस खोलने में जुट गया. यह एक ऐसा प्रसंग था, जिसके बारे में लेखक ने बहुत ही प्यार और शिद्दत से लिखा है.

समीक्ष्य कृति: इन ए फ्री स्टेट
लेखक: वी एस नायपॉल
प्रकाशक: पेंगुइन बुक्स
क़ीमत: 250 रुपये

दरअसल, इस पूरी किताब में जिस तरह से एक के बाद एक घटना सामने आती है, वह सचमुच उपन्यास को बांधने में सक्षम है. एक बूढ़े व्यक्ति का जिस तरह से वर्णन किया गया है, वह सचमुच अकल्पनीय है. ऐसा लगता है कि लेखक खुद एक यायावर हैं और उन्होंने अपने ही पात्र को जीवन देने की कोशिश की है. यह एक ऐसे यायावर की कहानी है, जो सौम्य है, तरोताजा है और इसीलिए हमेशा नाश्ते के लिए तैयार रहता है. हमेशा खाने–पीने में मस्त एक यायावर. खाना चबाने में भी वह खरगोश की भांति फुर्तीला था. उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अगले कौर के लिए वह बेचैन है. हर निवाले में निर्मल आनंद लेना तो कोई उस यायावर से सीखे.

लेखक ने जहां एक ओर यह बताने की कोशिश की कि ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर, बताओ किसे मारना है और साथ ही यह बताने की कोशिश भी की कि उपन्यास लिखने से पहले किस तरह से थ्रिल का सहारा लिया जाता है. एक जगह लेखक लिखते हैं कि एक टैक्सी आकर रुकती है और किस तरह से उस टैक्सी से एक दुबला–पतला गोरा लड़का बाहर आता है, एकदम बेफिक्र. शब्दों के बाजीगर हैं लेखक. शब्दों को कहां कितना ढीला छोड़ना है, और कहां कसना है और कहां कितना थ्रिल का पुट देना है, इसमें लेखक की अपनी दूरदृष्टि नज़र आती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कंपनी ने अपनी बाइक डिस्कवर का अपग्रेडेड मॉडल डिस्कवर 125टी उतारा है. इसकी क़ीमत 52,500 रुपये (एक्स शोरूम–दिल्ली) है. डिस्कवर 125टी में कंपनी ने 125 सीसी की क्षमता का 4 स्ट्रोक इंजन इस्तेमाल किया है, जो इसे 12.5 पीएस की पावर देता है.

कीजिए जी भर कर बात

पब्लिक सेक्टर की टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने नेशनल रोमिंग के लिए एक स्कीम पेश की है. इसके तहत ग्राहकों को पूरे देश में रोमिंग के दौरान मुफ्त इनकमिंग कॉल के साथ सस्ती दर कॉल और एसएमएस करने की सुविधा भी मिलेगी. बीएसएनएल ने रोमिंग के लिए दो स्पेशल टैरिफ वाउचर पेश किए हैं. अब ग्राहक हर दिन के लिए 5 रुपये या 30 दिन के लिए 69 रुपये देकर अनलिमिटेड फ्री इनकमिंग कॉल का लाभ उठा सकेंगे. आउटगोइंग कॉल 1.5 पैसा प्रति सेकेंड पर की जा सकेगी. इसके अलावा, कंपनी ने पोस्ट–पेड ग्राहकों के लिए भी दो रोमिंग शुल्क योजना (आरटीपी) पेश की है. ■

41 मेगापिक्सल कैमरे वाला मोबाइल

नोकिया ने 41 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन लूमिया 1020 पेश किया है. नोकिया ने इस करते हुए कहा है कि यह कैमरा किसी भी डिजिटल कैमरे से ली गई इमेज जितनी शार्प इमेज दे सकता है. विंडोज़ फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले नोकिया लूमिया 1020 में 6 लेंस एलिमेंट और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है. कंपनी का दावा है कि यह आम स्मार्टफोन के माइक्रोफोन से 6 गुना ज्यादा साउंड प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है. इसमें प्रोफेशनल क्वॉलिटी इमेज के लिए नया फोटो ऐप्लिकेशन भी है. इसमें क्लियर ब्लैक और सुपर–सेंसिटिव टच टेक्नोलॉजी के साथ 1280–768 रेज्यूल्यूशन वाली 4.5 ईंच की एमोलेड स्क्रीन भी है. यह कॉर्निंग गरिला ग्लास 3 से बनी है. इसके स्क्रीन को धूप में भी देखा जा सकता है. पिक्सल डेंसिटी 334 पीपीआई है, जो आईफोन 5 के 326 पीपीआई से थोड़ी ज़्यादा और सैमसंग गैलक्सी एस4 के 441 पीपीआई से काफी कम है. इसमें ज़िनॉन फ्लैश के साथ नोकिया प्योर व्यू वाला 41 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. यह ड्यूल–कोर 1.5 गी–गाहर्ट्ज क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन एस4 प्रोसेसर पर चलता है. इसमें 2 जीबी रैम है. स्टोरेज 32 जीबी है और मेमरी कार्ड का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता. हालांकि 7 जीबी का क्लाउड स्टोरेज फ्री है. इसकी बैटरी 2000एमएच की है. कंपनी के मुताबिक़, टॉक टाइम 2जी पर 19.1 घंटे और 3जी पर 13.3 घंटे तक है. 63 घंटे तक इस पर गाने सुने जा सकते हैं. इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है. इसका वजन 158 ग्राम है. ■

वेगा बुलियन

वेगा कंपनी के इस हेलमेट का वजन 2 हजार ग्राम है. इसके अंदर की पैडिंग काफी सॉफ्ट हैं, जो आपके सिर को आराम देगी. मल्टीपल फीचर वाले इस हेलमेट में दो शील्ड हैं. एक फेस शील्ड दूसरी सन शील्ड. कंपनी का दावा है कि

यह हेलमेट एंटी स्क्रैच है. यह सीएडी तकनीक से बना है, जो आपके सिर को वेंटिलेशन के ज़रिये गर्मी से राहत पहुंचाएगा. इस हेलमेट की क़ीमत 1985 रुपये है. ■

वॉयस कालिंग टैबलेट है लाजवाब

सेलकॉन मोबाइल ने मार्केट में बड़े ब्रांडों से टक्कर लेने के लिए नया एचडी टैबलेट लॉन्च किया है. सीटी 910+ एचडी नाम के इस नये टैबलेट में 7 ईंच की 5 प्वाइंट स्क्रीन दी गई है, जो 960–540 रेज्यूल्यूशन को सपोर्ट करती है. 1 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर प्रोसेसर से लैस सेलकॉन टैब में 512 एमबी रैम और 4 जीबी इंटरनल मेमोरी इनबिल्ड है, जिसमें से 1.7 जीबी टैब में प्रयोग की जा सकती है. अगर कैमरे की बात करें, तो सेलकॉन के नए टैब में 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा और वीजीए फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो मार्केट में मौजूद ड्यूल कैमरा टैबलेटों के मुक़ाबले क़ीमत में कम है. सेलकॉन सीटी910+ में एंड्रॉयड 4.1 जैली बीन ओएस दिया गया है. साथ में 3जी वॉयस कॉलिंग सपोर्ट भी मौजूद है. मुकाबले की बात करें, तो सेलकॉन टैब सीटी 910+ टैब 7,999 रुपये में लॉन्च किया है, जो महंगे वॉयस कॉलिंग टैबलेट को कड़ी टक्कर देंगे. ■

कोबो ओरा एचडी

कोबो ने पढ़ने की आदत को आसान और रोचक बनाते हुए अपना नया ई–रीडर गैजेट लॉन्च किया है. 6.8 ईंच स्क्रीन वाले इस गैजेट की एचडी और 1440–1080 रेज्यूल्यूशन क्वालिटी इसको बेहतर क्लियरिटी देती है. इसकी बेहतर तकनीक स्क्रीन को स्क्रैच फ्री बनाती है. कोबो के इस ई–रीडर की इंटरनल मेमोरी 4 जीबी की है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के ज़रिये 32 जीबी तक एक्सपैंड किया जा सकता है. ई–रीडर की मदद से यूजर ई–बुक के फॉन्ट्स को अपनी सुविधानुसार बदल भी सकते हैं और आप पढ़ते समय टेक्स्ट को हाइलाइट कर नोट कर सकते हैं. यही नहीं, इसे आप अपनी फेसबुक के ज़रिये शेयर भी कर सकते हैं. कंपनी का दावा है कि रोज़ औसतन 30 मिनट चलाने पर इसकी बैटरी दो महीने तक चलती है. ■

माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन धमाका

कैनवास–4 लॉन्च

घरेलू हैंडसेट कंपनी माइक्रोमैक्स की अब भारतीय बाज़ार में नंबर वन बनने पर नजरें टिकी हुई हैं. कंपनी ने हाल ही में अपना सबसे आधुनिक स्मार्टफोन कैनवास–4 लॉन्च किया है. इसकी क़ीमत 17,999 रुपये है. कम क़ीमत में बेहतरीन फीचर्स के ज़रिये कंपनी सैमसंग के गैलेक्सी को कड़ी टक्कर देगी. कंपनी के सह संस्थापक राहुल शर्मा ने बताया कि माइक्रोमैक्स हर महीने 22 लाख हैंडसेट बेच रही है. अब हमें देश की नंबर वन कंपनी बनना है. कैनवास सीरीज ने बाज़ार में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. कैनवास–4 की लॉन्चिंग से पहले ही 11,500 ऑर्डर आ चुके हैं. पिछले तीन महीने में हम 10 लाख कैनवास बेच चुके हैं. इस सीरीज में 10 फोन हैं, जिनकी क़ीमत 6,000 से 18,000 के बीच है. कंपनी की योजनाओं के बारे में बताते हुए सीईओ, दीपक मल्होत्रा ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में हमारा कारोबार 3,100 करोड़ रुपये था. चालू वित्त वर्ष में हम इसे ढाई गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सैमसंग की बाज़ार में हिस्सेदारी 37 फीसद है. ■

तोशिबा का नया टैबलेट

तोशिबा ने टैबलेट की दुनिया में नये आयाम छूते हुए एक नया गैजेट लॉन्च किया है, जो लैपटॉप और टैबलेट दोनों का काम करता है. इसकी स्क्रीन को अलग करके इसे की–बोर्ड के साथ जोड़ कर लैपटॉप की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. विंडो 8 प्रोसेसर के साथ चलनेवाला यह टैबलेट पूरी तरह से डिटेचेबल, फुल एचडी, 11.6 ईंच का टचस्क्रीन टैबलेट है. इसकी ख़ासियत यह है कि यह टेन फिंगर मल्टी टच के साथ मौजूद है और साथ ही इसकी स्क्रीन उंगलियों से पड़ने वाले निशानों को खुद से दूर रखेगी. इस टैबलेट के साथ की–बोर्ड भी जोड़ा जा सकता है, जो अत्याधुनिक तकनीक से बना है. ये इंटेल कोर आई 5 और आई 7 प्रोसेसर वी–प्रो टेक्नोलॉजी के साथ है, जो इसको कार्य करने में तेजी प्रदान करता है. एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह पांच घंटे दस मिनट तक आसानी से काम करता है. तोशिबा के इस टैबलेट में दो यूएसबी स्लॉट के साथ, एचडीएमआई और कार्ड रीडर के फीचर भी मौजूद हैं. यह वजन में मात्र 1.98 पाउंड और 19.9 मिमी चौड़ा है. ■

मात्र 15,999 में गेमिंग स्मार्टफोन

ज़ोलो प्ले स्मार्टफोन की प्री–बुकिंग शुरू हो गई है. कंपनी इस स्मार्टफोन की ब्रांडिंग गेमिंग फोन के रूप में कर रही है. कंपनी की वेबसाइट से यह फोन 15999 रुपये में प्री–बुक किया जा सकता है. इसमें एनवीडिया टेगरा 3 चिपसेट के साथ 1.5 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर प्रोसेसर लगा है. इसमें बैटरी सेविंग के लिए 5वां कोर भी है. 12 कोर एनवीडिया यूएलपी जीफोर्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है. इसमें इंटरनल मेमरी 4 जीबी की है और 32 जीबी तक मेमरी कार्ड लगाया जा सकता है. रैम 1 जीबी है. यह एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन पर चलता है. इसमें 1280–720 रेज्यूल्यूशन और 312 पीपीआई पिक्सल डेंसिटी वाला 4.7 ईंच का डिस्प्ले है. इसमें वन ग्लास सलूशन टेक्नोलॉजी के साथ आईपीएस डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है इसमें. यह 5 फिंगर को सपोर्ट करता है. इसमें ऑटो फोकस और फ्लैश के साथ पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल कैमरा और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है. फुल एचडी 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्ड और प्ले किया जा सकता है. इसमें 2000 एमएच की बैटरी है. कंपनी के मुताबिक़, स्टैंडबाई टाइम 2जी पर 227 घंटे और 3जी पर 413 घंटे है. टॉक टाइम 2जी पर 11.2 घंटे और 3जी पर 9 घंटे है. ■

स्टीलबर्ड का एसबी 29

स्टीलबर्ड कंपनी का एसबी 29 हेलमेट एक स्टाइलिश लुक के साथ सुरक्षा की नज़र से भी मज़बूत है. यह एक ओपन फेस हेलमेट है, जो बाइकर को वेंटिलेशन भी देता है, जो आमतौर पर साधारण हेलमेट नहीं दे पाते. इसकी स्लाइडर रूफ हवा के तेज़ बहाव को धकेलने में मदद करती है. इसका ड्यूल फिनिश डिजाइन इसको अन्य हेलमेट की तुलना में अलग और ज़्यादा कूल बनाता है. अपनी क़ीमत के मुताबिक़, यह हेलमेट एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इसकी क़ीमत है 1350 रुपये. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बजाज की बेमिसाल बाइक

बाइक बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी बजाज ऑटो ने भारतीय बाज़ार में टू व्हीलर का विस्तार करते हुए अपनी लोकप्रिय बाइक डिस्कवर का नया वर्जन लॉन्च कर दी है. कंपनी ने अपनी बाइक डिस्कवर का अपग्रेडेड मॉडल डिस्कवर 125टी उतारा है. इसकी क़ीमत 52,500 रुपये (एक्स शोरूम–दिल्ली) है. डिस्कवर 125टी में कंपनी ने 125 सीसी की क्षमता का 4 स्ट्रोक इंजन इस्तेमाल किया है, जो इसे 12.5 पीएस की पावर देता है. कंपनी ने नई डिस्कवर 125 टी में 5 स्पीड स्टैंडर्ड गियर बॉक्स का प्रयोग किया है, जो बजाज की पुरानी बाइक की तरह ही है. नई बजाज डिस्कवर 125टी में कंपनी ने डीटीएसआई तकनीक का प्रयोग किया है, जो बाइक का माइलेज शानदार बनाती है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 77 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी. बजाज डिस्कवर 125टी की अधिकतम स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. इस स्पोर्टी बाइक में एलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है. इस बाइक में 130 एमएम का ड्रम ब्रेक और सेल्फ स्टार्ट भी शामिल किया गया है. कंपनी की ओर से इस बाइक में ड्रम ब्रेक की जगह पर डिस्क ब्रेक लगाने की सुविधा भी है, लेकिन उससे बाइक की क़ीमत बढ़कर लगभग 55,500 रुपए हो जाएगी. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

धोनी को ट्वेंटी–20 मैचों का शानदार फिनिशर माना जाता है. अब उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि वह 50 ओवर के मैचों में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान डेथ ओवर में कितने योग्य हैं.

बेस्ट फिनिशर हैं धोनी

दुनिया बोले माही वे...

भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी की मैच फिनिशिंग स्किल के सभी कायल हो गए हैं. सभी इस बात से अब इत्तेफाक रखने लगे हैं कि जब तक धोनी क्रीज पर हैं,भारत को डरने की जरूरत ही नहीं है...

चौथी दुनिया ब्यूरो

माही, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज उस मुकाम पर हैं, जिसे हासिल करने में बड़ों–बड़ों के दांत खट्टे हो जाते हैं. उनके तरकश में आज एक से बढ़कर एक तीर हैं. दरअसल, वह यह बखूबी जानते हैं कि किस तीर से कब और कहां निशाना साधना है. और इसी काबिलियत की वजह से धोनी को न सिर्फ भारत का बेस्ट कैप्टन कहा जाता है, बल्कि वह दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर भी बन गए हैं. कभी एडम गिलक्रिस्ट की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले धोनी ने वनडे क्रिकेट में टीम की जरूरत के लिए माइकल बेवन बनने से भी परहेज नहीं किया. यही खूबी उन्हें एक असाधारण वनडे बल्लेबाज बनाती है. वह एक गेंद में गिलक्रिस्ट की तरह छक्के लगाकर मैच जिता सकते हैं, तो अगलीही गेंद पर बेवन की चपलता से बड़े आसानी से सिंगल्स भी चुरा सकते हैं.

धोनी ने टीम इंडिया को शिखर पर पहुंचा दिया है. आज टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में नंबर वन है, तो वहीं टेस्ट में दूसरे और टी–ट्वेंटी में तीसरे स्थान पर है. धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2007 में ट्वेंटी–20 विश्व कप, 2011 में वन डे वर्ल्ड कप और 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम की है. धोनी की मैच जिताऊ पारियों के कारण ही पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण कहते हैं कि भारत लकी है कि उसके पास धोनी जैसा कैप्टन है. धोनी बहुत ही शांत एवं धैर्यवान कप्तान हैं और वह भारतीय टीम को एकदम सही तरीके से संचालित कर रहे हैं.

देखा जाए, तो धोनी छक्का लगाकर मैच जिताने में माहिर हैं. उन्होंने कई बार विषम परिस्थितियों में भी छक्का मारकर मैच जिताए हैं. हाल ही में वेस्टइंडीज में त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल और विश्व कप 2011 में श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने फाइनल में छक्का मारकर टीम को विश्व विजेता बनाया था. वेस्टइंडीज में श्रीलंका के खिलाफ हुए फाइनल मैच में यह साबित हो गया कि वह भारत के सबसे बढ़िया फिनिशर हैं. अगर आज के क्रिकेट की बात की जाए, तो फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है, जो उनसे अच्छा मैच फिनिशर हो. इंग्लैंड के इयोन मोर्गन, लंका के मैथ्यूज, इंडीज के पोलार्ड, ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क, दक्षिण अफ्रीका के जे.पी डुमिनी, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी मैच खत्म करने में उनसे कहीं पीछे हैं. धोनी की यही काबिलियत है कि अगर भारत के 9 विकेट गिर चुके हैं और क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, तब भी उम्मीद रहती है कि भारत मैच जरूर जीत लेगा. हालांकि धोनी जब टीम इंडिया में आए थे, तो कई विशेषज्ञों का मानना था कि उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी खामियां हैं, लेकिन आज धोनी दुनिया में सबसे भरोसेमंद फिनिशर के तौर पर उभर चुके हैं. गौरतलब है कि मिस्टर भरोसेमंद का तमगा इससे पहले पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को दिया जाता था, जो तकनीकी रूप से विश्व के नंबर एक बल्लेबाज थे.

पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में झारखंड के इस क्रिकेटर से बेहतर फिनिशर नहीं देखा है. वेंगसरकर कहते हैं कि धोनी का मिजाज बहुत बढ़िया है, अब तक मैंने जितने भी फिनिशर देखे हैं, उनमें वह सर्वश्रेष्ठ है. वह खेल में किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है. धोनी के कायल लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी हैं. वे कहते हैं कि धोनी क्या चीज हैं, इसे समझ पाना असंभव है. उनके करीबी दोस्त मानते होंगे कि वह उन्हें जानते हैं, लेकिन मेरी समझ से वह उन्हें बिल्कुल नहीं जानते. असल में धोनी क्या हैं, यह किसी को नहीं पता.

धोनी को ट्वेंटी–20 मैचों का शानदार फिनिशर माना जाता है. अब उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि वह 50 ओवर के मैचों में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान डेथ ओवर में कितने योग्य हैं. विपरीत परिस्थितियों में धोनी के चेहरे पर शांति, जरूरत के मुताबिक, रणनीति में बदलाव तथा विपक्षी गेंदबाजों और कप्तानों को पढ़ने की क्षमता, उनकी सफलता के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं. उन्होंने 226 वन डे में आठ शतक, 48 अर्धशतकों से 7,300 रन बनाए हैं. दरअसल इस महान फिनिशर की क्षमता का पता इस बात से ही चल जाता है कि वह प्रत्येक चार पारियों में एक बार नाबाद रहते हैं, लेकिन धोनी के लिए यह ऊंचाई हासिल करना इतना आसान नहीं था.

धोनी ने 2004–05 में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का सदस्य बनकर अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन यह उनकी बहुत ही खराब शुरुआत रही थी. मैच में रांची का यह खिलाड़ी शून्य पर रन आउट हो गया था, लेकिन इसके बाद धोनी के करियर का ग्राफ चढ़ता ही चला गया और वह इस समय देश ही नहीं, विश्व के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं. धोनी का क्रिकेट में आना एक संयोग था, क्योंकि क्रिकेट धोनी की पहली पसंद नहीं था. कहा जाता है कि वह फुटबॉल और बैडमिंटन के शौकीन थे. एक बार धोनी के फुटबॉल कोच ने धोनी को एक क्रिकेट क्लब के लिए विकेट कीपिंग करने को कहा और उसके बाद फिर जो हुआ, उसके बारे में शायद धोनी ने कभी सोचा नहीं होगा. ऐसा भी नहीं है कि धोनी को सब कुछ आसानी से हासिल हो गया. उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है. धोनी सबसे पहले 1998–99 में बिहार अंडर–19 टीम में शामिल किए गए. 1998–1999 के दौरान कूच बिहार ट्रॉफी से धोनी के क्रिकेट को पहली बार पहचान मिली. इस टूर्नामेंट में धोनी ने 9 मैचों में 488 रन बनाए और विकेट कीपिंग करते हुए 7 स्टंपिंग भी कीं. इसी प्रदर्शन के बाद उन्हें साल 2000 में पहली बार रणजी में खेलने का मौका मिला. इस तरह 18 साल के धोनी ने बिहार की टीम से रणजी में खेलना शुरू किया. इस दौरान 2003–04 में कड़ी मेहनत के कारण धोनी को जिम्बाब्वे और केन्या दौरे के लिए भारत ए टीम में चुना गया. जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने विकेटकीपर के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 कैच और 4 स्टंपिंग की. इस दौरे पर बल्लेबाजी करते हुए धोनी ने 7 मैचों में 362 रन भी बनाए.

धोनी के कामयाब जिम्बाब्वे दौरे के बाद तत्कालीन टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें टीम में लेने की सलाह दी. 2004 में धोनी को पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली. हालांकि वह अपने पहले मैच में कोई खास कमाल नहीं कर पाए और शून्य पर आउट हो गए. इसके बावजूद कई औरमैचों में धोनी का बल्ला नहीं चला. 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रनों की एक ऐसी तूफानी पारी खेली कि सभी इस खिलाड़ी के मुरीद बन गए.

वर्ष 2005 में धोनी भारतीय टीम में नये–नये थे और उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए महज 145 गेंद में नाबाद 183 रन का स्कोर बनाया था, जो कि अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, जिसमें 10 छक्के और 15 चौके शामिल थे. इस पारी से भारत ने श्रीलंका द्वारा दिए गए 299 रन के लक्ष्य को चार ओवर रहते ही हासिल कर लिया था, जबकि उनकी टीम में उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चामिंडा वास और मुथैया मुरलीधरन शामिल थे.

इससे कुछ महीने पहले ही धोनी ने विशाखापत्तनम में पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंद में 148 रन की पारी खेलकर अपनी काबिलियत का नजारा पेश किया था, जिससे भारत ने नौ विकेट पर 356 रन का स्कोर खड़ा किया और मेहमान टीम हार गई थी. धोनी ने पाकिस्तान में 2006 में लाहौर और कराची में जोरदार अंदाज में फिनिशर की भूमिका अदा की, जिसमें नाबाद 70 से अधिक रन की पारी शामिल थी, जिससे भारत ने टेस्ट सीरीज में 0–1 की हार के बाद वन डे सीरीज में 4–1 से जीत दर्ज की.

उन्होंने बांग्लादेश में मई में 2007 और फिर जनवरी 2010 में क्रमश: नाबाद 91 और नाबाद 101 रन की पारी खेलकर यह काम फिर से किया. इन कुछ पारियों में धोनी को युवराज सिंह, विराट कोहली तथा अन्य खिलाड़ियों का साथ मिला और वेस्टइंडीज में लंका के खिलाफ उन्होंने अंतिम खिलाड़ी इशांत शर्मा के साथ यही किया. इन सबमें सबसे ज्यादा चर्चित और अहम पारी वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 2 अप्रैल, 2011 विश्व कप फाइनल की रही, जिसमें उन्होंने नाबाद 91 रन बनाए.

सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर की 97 रन की शानदार पारी और धोनी की उनके साथ 119 रन की साझेदारी तथा कप्तान की युवराज सिंह के साथ नाबाद 54 रन की भागीदारी से भारत ने 10 गेंद रहते श्रीलंका द्वारा दिए गए 275 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था. धोनी ने तेज गेंदबाज नुवान कुलाशेखरा की गेंद पर विजयी छक्का लगाकर पूरे देश को जश्न के माहौल में डुबो दिया.

भारत के पूर्व फिरकी गेंदबाज मनिंदर सिंह कहते हैं कि धोनी न केवल भाग्य के धनी हैं, बल्कि उनमें गुण भी बहुत हैं. वह क्रिकेट के अच्छे जानकार हैं. वह निर्भीक होकर बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और कप्तानी करते हैं. उनके कुछ फैसले बेहद चौंकाने वाले होते हैं. उनकी सोच है कि जब तक मैं सौ प्रतिशत दे रहा हूं, तब तक चाहे कोई भी मेरी कितनी ही आलोचना करे, मुझे कोई डर नहीं है. जब किसी खिलाड़ी का रवैया इस तरह का हो जाए, तो परिणाम भी सकारात्मक या फिर मन मुताबिक आने शुरू हो जाते हैं. साथ ही युवा खिलाड़ियों को जिस अंदाज में वह साथ लेकर चलते हैं या मैदान में उनका उपयोग करते हैं, वह भी काबिलेतारीफ है. युवा खिलाड़ियों को एक ऐसा कप्तान चाहिए, जो उन पर भरोसा कर सके, उन पर दबाव न आने दे और जब कप्तान निडर होगा, तो टीम भी वैसी ही होगी, जैसी इस समय भारतीय टीम दिख रही है.

पोर्ट ऑफ स्पेन वन–डे में धोनी की एक और मैच–जिताने वाली पारी के बाद एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई है कि क्या धोनी वास्तव में बेस्ट फिनिशर हैं. आंकड़े देखें, तो यह साबित होता है कि धोनी को क्यों बेस्ट फिनिशर कहा जाता है. सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की. सचिन के 463 वनडे मैचों में 18426 रन, 44.83 का औसत, 86.23 का स्ट्राइक रेट, 49 शतक और 96 अर्धशतक उनको भारत तो क्या, दुनिया की किसी भी सर्वकालीन महान वन डे टीम का हिस्सा बनाने के लिए काफी हैं, लेकिन इन आंकड़ों और रिकॉर्ड से बड़ी बात यह है कि तेंदुलकर के दौर में टीम इंडिया के वनडे मैचों के जीतने का अनुपात बढ़ा और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है. इतना ही नहीं, तेंदुलकर ने दुनिया के हर मैदान पर, हर विरोधी के खिलाफ करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक अपने आप को मैच विनर साबित किया.

सौरव गांगुली की गिनती भारत के सफलतम कप्तानों में होती है. आकंड़ों और शतक के लिहाज से गांगुली की दावेदारी वन डे क्रिकेट में सबसे बड़े मैच–विनर के तौर पर तेंदुलकर की तुलना में उन्नीस ही है. 311 मैचों में 11363 रन, 41.02 का औसत, 73.70 का स्ट्राइक रेट, 22 शतक और 72 अर्धशतक, दादा को भारतीय क्रिकेट का एक बेजोड़ मैच–विनर बनाते हैं, लेकिन बात सिर्फ एक खिलाड़ी की चुनने की आए, तो शायद दादा के समर्थक भी मानेंगे कि सचिन, युवराज और धोनी उनसे इस मामले में आगे हैं.

युवराज सिंह की गिनती भी भारत के बेस्ट मैच फिनिशरों में होती है. अगर 2011 के वर्ल्ड कप को देखें, तो युवराज सिंह का योगदान साबित करता है कि वन डे क्रिकेट में एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, एक उपयोगी गेंदबाज और एक लाजवाब फील्डर के तौर पर वे जबरदस्त मैच विनर हैं. युवराज के 282 मैचों में 8211 रन और 36.98 का औसत, 87.64 का स्ट्राइक रेट, 13 शतक और 50 अर्धशतक के आंकड़े भले ही तेंदुलकर और गांगुली की तुलना में थोड़े कमजोर दिखें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि युवराज ने सिर्फ अपने दम पर कई मैचों का रुख बदला है. आंकड़ों के लिहाज से करियर के इस दौर में धोनी का औसत स्ट्राइक रेट की कसौटी पर तेंदुलकर से भी बेहतर है. धोनी के 226 मैचों में 7358 रन, 51.45 का औसत, 88.17 का स्ट्राइक रेट, 8 शतक और 48 अर्धशतक, अपने आप में अद्भुत आंकड़े हैं. आज भारत के किसी भी फॉर्मेट (टेस्ट वनडे और ट्वेंटी–ट्वेंटी) में धोनी का रिकॉर्ड भारत के पूर्व कप्तानों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्राण का जन्म एक सरकारी ठेकेदार लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर 12 फरवरी, 1920 को दिल्ली में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई–लिखाई कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर जैसे शहरों में हुई. साल 1945 में प्राण की शादी शुक्ला से हुई, जिनसे उन्हें दो बेटे अरविंद और सुनील व एक बेटी पिंकी हुईं.

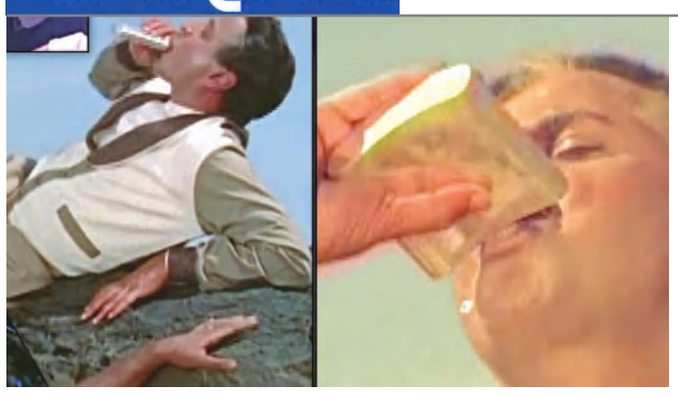

नहीं रहे डायलॉग डॉन प्राण

आत्मविश्वास से भरपूर एक कलाकार

93 साल की उम्र में पिछले दिनों महान फिल्म अभिनेता प्राण की मृत्यु हो गई. आइए, जानते हैं प्राण के नीजी और फिल्मी सफर के बारे में...

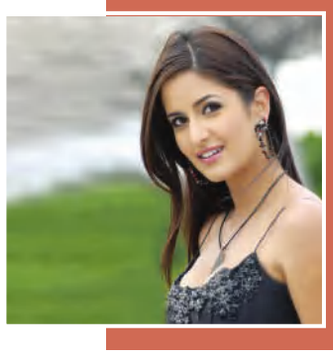

प्रियंका तिवारी

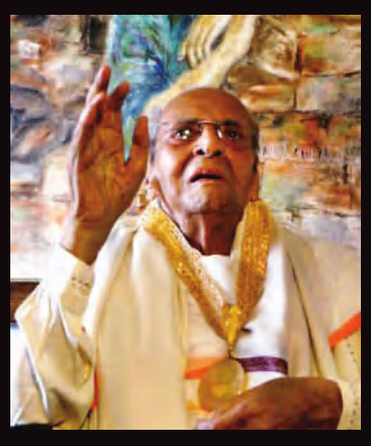

वयोवृद्ध अभिनेता प्राण अब हमारे बीच नहीं रहे. 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने. इस उदीयमान सितारे ने नफरत भरे किरदारों से भी लोगों के दिल पर अंत तक राज किया. प्राण के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले और आखिरी सुपर स्टार विलेन का निधन हो गया है. आज अगर प्राण होते और निधन किसी और का हुआ होता, तो वह गंभीर होकर कहते, तुमने ठीक ही सुना है बरखुरदार. और साथ ही यह डॉयलॉग जोड़ते कि प्राणों के ही वसूल होते हैं जनाब. ऐसे किरदार मरते नहीं हैं लिलि, वह तो अमर हो जाते हैं, सदा सदा के लिए.

सच तो यह है कि उनमें आत्मविश्वास इतना था कि जेब में पैसे नहीं होने के बावजूद मुंबई के ताजमहल होटल में एक कमरा बुक करा लिया था, जबकि उन्होंने एक फोटोग्राफर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. तन्ख्वाह थी महज 200 रुपये. जी हां, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि काम जरूर मिलेगा. यह उनका आत्मविश्वास ही था कि अंतत: काम मिला और खूब और खूब मिला. इतना काम मिला कि आज भी लोग उन्हें और उनकी अदाकारी को याद करते हैं. उनके हर एक किरदार को याद करते हैं, चाहे उपकार का मलंग चाचा हो, या राम और श्याम का गजेंद्र बाबू या फिर जिस देश में गंगा बहती है का राका.

प्राण के बारे में कहा जाता है कि वे जिस रोल को करते थे, उसमें बहुत गहराई से उतर जाते थे. विलेन के रूप में लोगों ने उनसे नफरत हो, लेकिन असल जिंदगी में वह बेहद नेकदिल इंसान थे. साल 1940 में यमला जट फिल्म में पहली बार प्राण बड़े पर्दे पर दिखाई दिए. प्राण खलनायक ही नहीं, एक सशक्त चरित्र अभिनेता भी रहे. 1968 में उपकार, 1970 में आंसू बन गए फूल और 1973 में बेईमान फिल्म के लिए प्राण को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर अवॉर्ड से नवाजा गया. इसके बाद उन्हें सैकड़ों सम्मान और अवॉर्ड मिले. इस साल यानी 2013 में प्राण को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से भी नवाजा गया था.

»» प्राण के बारे में कहा जाता है कि वे जिस रोल को करते थे, उसमें बहुत गहराई से उतर जाते थे. विलेन के रूप में लोगों ने उनसे नफरत किया हो, लेकिन असल जिंदगी में वह बेहद नेकदिल इंसान थे. साल 1940 में यमला जट फिल्म में पहली बार प्राण बड़े पर्दे पर दिखाई दिए. प्राण खलनायक ही नहीं, एक सशक्त चरित्र अभिनेता भी रहे.

प्राण का जन्म एक सरकारी ठेकेदार लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर 12 फरवरी, 1920 को दिल्ली में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई–लिखाई कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर जैसे शहरों में हुई. साल 1945 में प्राण की शादी शुक्ला से हुई, जिनसे उन्हें दो बेटे अरविंद और सुनील व एक बेटी पिंकी हुईं. पचास और साठ के दशक का दौर, जो हिन्दी सिनेमा का स्वर्णिमकाल माना जाता है, में यदि कोई कलाकार खलनायकी का पर्याय था, तो वे थे प्राण. पर्दे पर तमाम दिग्गज हीरोज से टक्कर लेने वाले प्राण ने एक के बाद एक इतनी हिट फिल्मों में खलनायकी की थी कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना ही बंद कर दिया था. एक खलनायक के रूप में प्राण पर्दे पर खौफ पैदा कर देते थे. प्राण के करियर में ऐतिहासिक मोड़ आया वर्ष 1967 में, जब मनोज कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म उपकार में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक रोल ऑफर किया.

उपकार की कहानी थी देश के आम किसान भारत (मनोज कुमार) और उसके इर्द–गिर्द के पात्रों की. इन सबके बीच थे मलंग चाचा यानी प्राण, जो गांव की अंतरात्मा को आवाज देते थे. मलंग चाचा के रोल में प्राण ऐसे डूबे कि वह और मलंग चाचा एकाकार हो गए. उन पर फिल्माया गया गीत कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं बातों का क्या... इस फिल्म को दार्शनिक ऊंचाई देता है. कहते हैं कि जब कल्याणजी–आनंदजी को पता चला कि इंदिवर के जिस गीत को उन्होंने किसी खास अवसर के लिए सहेजकर रखा था, वह प्राण पर फिल्माया जाने वाला है, तो उन्होंने मनोज कुमार से शिकायत की कि प्राण तो पर्दे पर इस गीत का सत्यानाश कर देंगे! बाद में जब उन्होंने गीत का फिल्मांकन देखा, तो प्राण का लोहा मान लिया. उपकार के लिए प्राण को फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें मिला, वह था दर्शकों की नजर में पूरी तरह बदली उनकी छवि का.

फिल्म पत्रकार बन्नी रूबेन ने प्राण की बॉयोग्राफी और प्राण में लिखा है, 11 अगस्त को बच्चे का पहला जन्म दिन था. पत्नी की जिद थी कि वे इस मौके पर साथ हों. फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त प्राण बमुश्किल लाहौर से निकले और इंदौर पहुंचे. उसी समय वहां सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे. प्राण फिर कभी लाहौर नहीं लौट पाए. वह बेघर थे. और उनके पास कुछ नहीं था. आठ महीने बाद वह इंदौर से किस्मत आजमाने मुंबई गए. कई महीनों के इंतजार और कोशिशों के बावजूद कहीं काम नहीं मिला. लाहौर से जितने पैसे ला पाए थे, खर्च हो गए. फाकाकशी की नौबत आई, तो उन्होंने नन्हे अरविंद को बेहतर परवरिश के लिए फिर इंदौर छोड़ा. प्राण ने कहा, मैं फिर कभी लौट नहीं सका, क्योंकि 15 अगस्त (1947) को मेरा घर विदेश बन चुका था. प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था. उन्हें सिगरेट पीना काफी पसंद था, सो उनके पास सिगरेट पाइप्स का बड़ा कलेक्शन था.

प्राण बड़े शर्मीले थे. शौकत हुसैन की फिल्म खानदान में वह नूरजहां के हीरो बनकर आए. यह फिल्म सुपरहिट हुई, मगर प्राण नायक के रोल में काम करते हुए बेहद संकोच करते थे. वह कहते थे कि पेड़ों के पीछे चक्कर लगाना अपने को जमता नहीं था. वह दोबारा हीरो नहीं बने. प्राण फोटोग्राफर बनना चाहते थे और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की ए दास कंपनी में काम शुरू कर दिया था. प्राण के पिता एक सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, इसलिए उनकी पढ़ाई भारत के अलग–अलग हिस्सों में हुई. प्राण ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वह शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आएगा. जब अखबार में उनका पहला इंटरव्यू छपा था, तो उन्होंने अखबार ही छुपा लिया, लेकिन फिर भी उनके पिता को इन सबकी जानकारी मिल गई. प्राण के इस करियर के बारे में जानकर उनके पिता को भी अच्छा लगा था, जैसा कि प्राण ने कभी नहीं सोचा था. उन्होंने शुरुआती फिल्मों में से एक में हीरो का किरदार भी निभाया था. फिल्म का नाम था खानदान, जो 1942 में आई थी. ■

मेहनत से मिली मंज़िल

कटरीना कैफ आज बॉलीवुड की सबसे सफलतम अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने बेहद मेहनत की. न सिर्फ हिंदी बोलना सीखा, बल्कि बॉलीवुड के तौर–तरीके भी समझने की कोशिश की. लंदन में पली–बढ़ी कटरीना ने बॉलीवुड में फिल्म बूम से अपने करीयर की शुरुआत की. फिल्म में कटरीना ने जमकर अंग प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म फिर भी नाकाम रही. उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत के कारण ही आज वह इस मुकाम पर हैं. दरअसल, व्यक्तिगत जीवन में वह एक सरल लड़की हैं, शायद इसीलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को मीडिया से दूर रखना ज्यादा पसंद करती हैं. कटरीना का जन्म 16 जुलाई, 1984 को हॉन्गकॉन्ग में हुआ था. उन्हें बार्बी गर्ल के नाम से भी जाना जाता है. उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ और मां का नाम सुज्जन है. कटरीना ने करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में मॉडलिंग से की. उनका पहला मॉडलिंग गहनों के लिए था. बाद में उन पर फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद की नजर पड़ी और उन्होंने कटरीना को फिल्म बूम का ऑफर दिया. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन कमजोर पटकथा के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई. इसके बाद वह फिल्म सरकार में नजर आईं, लेकिन यह फिल्म भी उनके करियर का ग्राफ नहीं बढ़ा पाई. फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनका संघर्ष जारी रहा. फिल्मों में स्ट्रगल करने के साथ ही वह मॉडलिंग भी करती रहीं. शुरुआती दिनों में हिंदी न आने की वजह से निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से हिचकते थे. उनकी शुरुआती फिल्मों में उनकी आवाज़ को डब किया जाता था. अपनी इस कमी को दूर करने के लिए कटरीना ने काफी मेहनत की. उन्होंने अपने बोलने के अंदाज़ को भी भारतीय बनाया.

उनकी पहली सफल फिल्म थी, वर्ष 2007 में नमस्ते लंदन. इस फिल्म में उनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ थी. दर्शकों को उनकी जोड़ी बेहद पसंद आई. दोनों ने साथ में कई और सफल फिल्में दीं. सिंह इज किंग, वेलकम और हमको दीवाना कर गए इस जोड़ी की सफल फिल्में हैं. बॉलीवुड के असफल फिल्मों के दौर में सिर्फ अक्षय और कटरीना की जोड़ी निर्देशकों का सहारा बनी. वह इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. कई बड़ी अभिनेत्रियां ऐश्वर्या और करीना को पीछे छोड़ने के साथ ही कटरीना बॉलीवुड और दर्शकों की चहेती बन गईं. उन्होंने नकारात्मक भूमिका भी की, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया. इसके अलावा, फिल्म राजनीति में भी उनके काम को काफी सराहा गया. यही नहीं, उन्हें आइटम डांसर के रूप में भी काफी सराहा गया. चिकनी चमेली, शीला की जवानी और बॉडीगार्ड जैसे आइटम कर उन्होंने दर्शकों की काफी वाहवाही बटोरी.■

विविध भूमिकाओं में सोनम

सोनम कपूर को बस एक हिट का इंतजार था, जो आखिर मिल ही गया. उनकी फिल्म रांझणा में उनके काम की काफी तारीफ हुई. वहीं फरहान अख्तर स्टारर फिल्म भाग मिल्खा भाग में भी सोनम कुछ अलग भूमिका में नजर आईं. फिल्म में उनका रोल काफी छोटा जरूर था, लेकिन प्रभावी था. फिल्म में उनके किरदार का नाम बीरो नाम की लड़की का है. बीरो मिल्खा के स्टार मिल्खा बनने से पहले का एक सपना है. वहीं फिल्म रांझणा में वह जोया के किरदार में नजर आईं. फिल्म के बारे में सोनम कहती हैं कि इसकी शूटिंग में तकरीबन एक साल लगे. वह कहती हैं कि जोया का किरदार उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था. जोया के किरदार में मुझे एक संतुलन साधना था. जोया से दर्शक एक साथ नफरत और प्यार दोनों करें, इसके लिए तैयारी जरूरी थी. यह सब करना बहुत मुश्किल था. जोया आज की मुस्लिम लड़की है, जिसे बहुत छूट दी गई है. वह रूढ़िवादी और आधुनिक दोनों है. वह आज की उन लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, जिन्हें अपनी मर्जी का काम तो करना ही है और साथ ही अपने परिजनों का अप्रवूल भी लेना है. फिल्म में एक सीन था, जहां वह अपनी मां से कहती है कि वह किसी अनपढ़–गंवार लड़के से शादी नहीं कर सकती. आज की लड़कियां ऐसी ही होती हैं. बाहरी दुनिया से परिचित लड़की कैसे यूं ही किसी से शादी कर लेगी? ऐसी सूरत में उसके सामने जोया जैसा व्यवहार करने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था. वह मेरे लिए बहुत रीयल कैरेक्टर था. आज मैं देखती हूं कि हर दूसरी–तीसरी लड़की जोया जैसी ही है. उसे निगेटिव नहीं कहा जा सकता.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

29 जुलाई–04 अगस्त 2013

बिहार – झारखंड

ढाका नगर पंचायत कार्यालय में खुलेआम राशि का बंदरबांट

करोड़ों का घोटाला

भ्रष्टाचार का केंद्र बने ढाका नगर पंचायत कार्यालय में विभागीय आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. आवंटित राशि का खुलेआम बंदरबांट हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं?

इंतेज़ारुल हक़

कदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाक़ाम ढाका नगर पंचायत इन दिनों भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बना हुआ है. बीते तीन वर्षों में इस कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से एक तरफ़ जहां करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है, तो वहीं विभागीय नियमों और आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं. नगर की सफाई का मामला हो या फिर नगर पंचायत की जनता के लिए संचालित अन्य विकासात्मक योजनाओं का, सभी की स्थिति एक जैसी ही है. खुलेआम राशि का बंदरबांट किया गया है तथा नगर विकास विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखाया गया है. चौथी दुनिया को घोटालों से संबंधित जो काग़ज़ात मिले हैं, इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि यहां भ्रष्टाचार का खेल काफ़ी पुराना है और सभी इस बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हुए हैं. यहां बगैर वित्तीय प्रभार के ही लाखों-करोड़ों रुपये की निकासी कर ली जाती है और कई महीनों तक किसी को कानों-कान भनक भी नहीं लगती है. पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी सह वरीय उपसमाहर्ता राजेश्वर प्रसाद के बगैर वित्तीय प्रभार के 60 लाख रुपये की निकासी इसका ताजा उदहारण है. इस घोटाले में कार्यालय के प्रधान सहायक सह नाजिर पंकज कुमार की भी भूमिका संदिग्ध रही है और उनकी मिलीभगत से घोटालों का खेल बेरोक-टोक किया गया है. जब इसकी भनक नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सबीला खातून समेत अन्य पार्षदों को लगी तो पहले उन्हें गुमराह किया गया और फिर जब बात नहीं बनी तो उनकी उपेक्षा की जाने लगी. जानकार बताते हैं कि नगर पंचायत कार्यालय में भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी सोमनाथ सिन्हा ने जब वरीय उप समाहर्ता धर्मेंद्र कुमार को नगर पंचायत का प्रभार दिया था, तब प्रधान सचिव पंकज ने रोकड़-बही प्रस्तुत नहीं किया था. रोकड़-बही प्रस्तुत नहीं किए जाने के चलते वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि समय-समय पर लेखा का संधारण नहीं किया गया है और यहां वित्तीय अनियमितता का खेल काफ़ी पुराना है. 5 मार्च, 2013 को जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जब राजेश्वर प्रसाद की प्रतिनियुक्ति की गई, तब उन्हें भी वित्तीय प्रभार नहीं मिला.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

22 बच्चों की मौत से तो यही लगता है कि यह मिड डे मील नहीं, मिड डे मर्डर था, जो बच्चों की थाली में जहर के रूप में परोसा गया. कुछ अबोध बच्चों ने खाने से मना भी किया, लेकिन उन्हें डांट डपटकर खाने को बाध्य कर दिया गया. आज घर के घर श्मशान हो गए हैं.

बुझ गया घरों का चिराग

मिड डे मील या मिड डे मर्डर

शशि सागर

बिहार में मिड डे मील खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई है. 9 बच्चे तो एक ही परिवार के थे. पूरा घर ही श्मशान बन गया. कल तक जिन घरों में बच्चों के वृंदगं बजते थे, आज उन्हीं घरों में मातम पसरा है. आखिर कौन है उन बच्चों का हत्यारा? क्या करती रही हत्यारी सरकार और उसके भ्रष्ट महकमे. बेशर्म नेताओं की हद देखिए कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद राजनीतिज्ञों ने बच्चों की मौत पर सियासत का एक भी मौका नहीं छोड़ा. सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उंगली में फ्रैक्चर के बहाने पीड़ित परिवारों को देखने तक नहीं गए. लालू घर बैठे बयानबाजी करते रहे हैं और आशचर्य की बात तो यह है कि अन्य दलों के नेता या सरकार का कोई बड़ा अधिकारी उन परिवारों की खोज-खबर लेने तक नहीं गया. ऐसे मिड डे मील का क्या फायदा, जिसकी स्थिति भिक्षा से भी बदतर है. भिक्षा में भी कोई जहर नहीं देता, यहां तो भूखे बच्चों की थाली में ही जहर परोस दिया गया. देश के लगभग हर जगह से मिड डे मील में सांप, छिपकली, कॉकरोच और चूहे मिलने के समाचार आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन सरकार और उसके महकमों को लूट से फुर्सत हो, तब न. मिड डे मील बच्चों को परोसने से पहले स्कूल की शिक्षक-शिक्षिकाओं को चखना अनिवार्य है, तो क्यों नहीं चखा गया उस भोजन को. कहीं सबकुछ पहले से ही तय तो नहीं था? कहीं यह सियासत का मिड डे मील तो नहीं था? जब मिड डे मील के बहाने मिड डे मर्डर ही परोसना है, तो बेहतर होगा कि ऐसे मील को बंद ही कर दिया जाए.

बिहार में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर विवाद उठते रहे हैं. कभी खाने में छिपकली का मिलना, कभी कॉकरोच, तो कभी कुछ. आए दिन खबरें आती रहती हैं कि खाने के बाद बच्चे बिमार हो गए, उन्हें हॉस्पिल में भर्ती कराया गया, वगैरह-वगैरह, लेकिन छपरा के मशरक स्थित नव सृजित स्कूल में जो हुआ, वह दिल दहला देने वाला था. 22 बच्चों की मौत हो गई. ये बच्चे दस वर्ष से भी कम उम्र के थे. तीस से अधिक बच्चे बिमार हैं. समाचार लिखे जाने तक कई की स्थिती नाजुक बनी हुई थी. उसी दौरान यह भी खबर आई कि मधुबनी में भी मिड डे मील खाने से पचास बच्चे बिमार हो गए. बताया जाता है कि खाने में छिपकली गिर गई थी. ठीक उसी दिन यह भी ख़बर मिली कि गया में मध्याह्न भोजन के बाद बीस बच्चे बिमार हो गए. उनमें से एक की मृत्यु हो गई. उस दौरान सारण बंद हुआ. तोड़-फोड़ हुए. पुलिस की गाड़ियां जला दी गईं. ये सब गुस्साये स्थानीय लोगों ने किया, जिनके बच्चे खेलने-कूदने की उम्र में मौत को प्यारे हो गए.

इसी बीच सूबे की राजनीति का दूसरा चेहरा भी देखने को मिला. घटना के बाद से विपक्षी पार्टियों और सत्ताधारी पार्टी के बीच दोषारोपण का दौर शुरू हो गया. पटना के पीएमसीएच के शिशु वार्ड में पीड़ित परिजनों के रोने-सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं. जिन लोगों के बच्चे को काल ने लील लिया था, वे दहाड़ मार कर रो रहे थे. और कुछ इस भय से अवाक थे कि उनका बच्चा बच पाएगा कि नहीं. इस बीच सूबे के राजनीतिक दलों के नेताओं का आना भी लगातार जारी रहा. मातम पुर्सी के लिए पहुंचने वाले इन नेताओं से इलाज कर रहे डॉक्टरों को भी खासी परेशानी हो रही थी. हद तो तब हो गई, जब लोजपा के रोहित कुमार शिशु वार्ड के ही पास धरना पर बैठ गए. पीड़ित परिजनों ने बताया कि डॉक्टर अपनी तरफ़ से बेहतर इलाज करने की कोशिश कर ही रहे हैं. यहां आने वाले नेताओं से हमारी, मरीजों और डॉक्टरों की परेशानी भी बढ़ रही है. अपने बच्चे का इलाज करा रहे शैलेश कहते हैं कि ये नेता मौत पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते हैं.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

प्रमोशन में पहुंची संगीता

– यशवंत सिंह

पत्रकारों को मिले पेंशन

– शिवानी पांडेय

कार्य बाधित

– श्याम कुमार

बीजेपी से सीधी टक्कर : रामचंद्र

– यशवंत सिंह

धान के कटोरे में घोटालों की सच्चाई

धान और गेहूं की खरीदारी के दौरान खूब अनियमितताएं बरती गईं और इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी, लेकिन इन घोटालों की किसी ने भी सुध नहीं ली. क्या है इन घोटालों की सच्चाई

ममता चौहान

feedback@chauthiduniya.com

नेपाल के पानी से मचेगी तबाही !

कोसी पर चीन बांध बना कर भारतीय क्षेत्र में तबाही की पृष्ठभूमि तैयार करने में लगी है, तो दूसरी ओर नेपाल भी अब भारतीय क्षेत्र में जल प्रलय की स्थिति बनाने को आतुर है. इस सबके बावजूद सरकार अभी भी गहरी नींद में सोई है...

वाल्मीकि कुमार

feedback@chauthiduniya.com

बंद हो गई एक और बुलंद आवाज

खादी पुरुष के नाम से चर्चित त्रिपुरारी शरण जी की मृत्यु से शोक का माहौल है. उनके नाम कई उपलब्धियां हैं. रेशम उत्पादन के तकनीक पर उन्होंने एक पुस्तक भी अंग्रेजी में लिखी है. इस पुस्तक को पढ़कर ही महर्षि महेश योगी ने त्रिपुरारी बाबू को 1981 में सिल्क सम्राट से विभूषित किया था.

विजेंद्र सिंह

feedback@chauthiduniya.com

करोड़ों का घोटाला

पृष्ठ 17 का शेष...

feedback@chauthiduniya.com

मिड डे मील या मिड डे मर्डर

पृष्ठ 17 का शेष...

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

बदहाल खादी भंडार

– श्याम कुमार

पदाधिकारियों की बैठक

– यशवंत कुमार

एमडीएम से वंचित

कमिटी गठित

– अरविंद सिंह

सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी

ओवरब्रिज निर्माण को लेकर शिकायत

– नंदकिशोर शर्मा

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

पांच जून को बैकुंठ के अपहरण के बाद उसके बेटे ने शक़ के आधार पर पांच लोगों के नाम पुलिस को बताया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया. इसमें से एक आरोपी सीमेंट व्यवसायी डब्लू मिश्रा ने पूछताछ के क्रम में लखापुर निवासी मुन्ना सिंह का नाम बताया. कांड में नाम आने के बाद पुलिस के भय से मुन्ना ने न्यायालय में समर्पण किया.

आख़िर कब शुरू होगा जयप्रभा सेतु

बिहार व यूपी को जोड़ने वाली जय प्रभा सेतु का शिलान्यास 28 अक्टूबर, 1986 को हुआ था, पर आज भी इसका उद्घाटन नहीं हो सका है...

विजेंद्र सिंह

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताबदियारा के सरयू नदी पर वर्षों पूर्व बनाए गए जयप्रभा सेतु का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रयास से उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ने वाली हाजीपुर से गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का शुभारंभ किया गया था. निर्माण के बाद इसके लोकार्पण की पहल वर्ष 2006 में चंद्रशेखर ने की थी. लोगों को यह उम्मीद थी कि जेपी जयंती के अवसर पर दूसरा उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया जाएगा. दुर्भाग्यवश उसी समय चंद्रशेखर जी की तबीयत ख़राब हो जाने के कारण यह मामला अधर में लटक गया. वर्ष 2008 में उनके निधन के बाद यह कार्यक्रम आज तक खटाई में पड़ा हुआ है. इस दौरान बिहार ख़ासकर सारण ज़िले में कितने ही पुल-पुलियों का निर्माण कार्य संपन्न हो गया.

बिहार व यूपी को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण जयप्रभा सेतु का शिलान्यास 28 अक्टूबर, 1986 को हुआ था. लंबे समय तक यूपी बिहार के क्षेत्रीय विवाद केकारण पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पहल पर इस परियोजना को अंतत: केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. उस समय बिहार में जयप्रकाश नारायण के शिष्य राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार थी. कुल मिलाकर इस सेतु का निर्माण लगभग 19 वर्षों तक चलता रहा. वर्ष 2005 में दूसरा कार्य पूर्ण होने के बाद इस सेतु पर परिचालन 2008 में शुरू हो सका. जयप्रभा सेतु बिहार एवं यूपी दोनों राज्यों की सीमांत क्षेत्र में है. हाल के वर्षों में बिना उद्घाटन के ही पुल पर आवागमन चालू हो जाने से इसके रख-रखाव पर प्रतिकूल असर पड़ा है. जयप्रभा सेतु के बदौलत ही राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का कार्य संभव हो सका. कहा जाता है कि जयप्रभा सेतु के निर्माण के समय दोनों राज्य की सरकारों की आपसी खींचतान को विराम देने के लिए चंद्रशेखर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर इससे होकर गुजरने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 19 के रूप में कराने का सुझाव दिया था. बावजूद इसके इस ऐतिहासिक राजमार्ग का विधिवत उद्घाटन आजतक संभव नहीं हो सका है, जबकि यूपी वाले हिस्से में वाहनों से टोल-टैक्स की वसूली बदस्तूर जारी है.

बिहार और यूपी को जोड़ने वाली जयप्रभा सेतु का शिलान्यास 28 अक्टूबर, 1986 को हुआ था. लंबे समय तक यूपी बिहार के क्षेत्रीय विवाद के कारण पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पहल पर इस परियोजना को अंतत: केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. उस समय बिहार में जयप्रकाश नारायण के शिष्य राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार थी. कुल मिलाकर इस सेतु का निर्माण लगभग 19 वर्षों तक चलता रहा.

चंद्रशेखर जी के जमाने में जयप्रकाश जयंती के अवसर पर देश के महत्वपूर्ण राजनेताओं का प्रतिवर्ष उनके जन्म-स्थान सिताबदियारा में जमावड़ा लगा करता था. जयप्रभा सेतु की उपेक्षा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षाविद् एवं छपरा जगदम कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रमेंद्र रंजन सिंह का कहना है कि अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनेता समय समय पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की महिमा गान करने की महज रस्म अदायगी करते हैं, जबकि जयप्रभा सेतु का विधिवत उद्घाटन करने की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है. उनका कहना है कि जयप्रभा सेतु का निर्माण केंद्र सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है, इसलिए इसके उद्घाटन का दायित्व केंद्रीय सरकार के द्वारा लाजिमी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बैकुंठ अपहरण कांड में उलझी पुलिस

राजेश कुमार

5 जून को जमुई के नवीनगर पंचमंदिर से अगवा व्यवसायी बैकुंठ वर्णवाल का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है. बैकुंठ अपहरण कांड में पुलिस की भूमिका और ग़लत दिशा में चल रही कार्रवाई ने कांड को और भी रहस्यमय बना दिया है. जमुई पुलिस की अपरिपक्व कार्रवाई और हिटलरशाही निर्णय का ही नतीजा है कि ख़ुद विभाग को शर्मिंदगी और असफलता झेलनी पड़ रही है. साथ ही पुलिस की साख़ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस कांड से जुड़े तीन अनुसंधानकर्ताओं को एक माह के अंदर बदला जाना इसका जीता जागता सबूत है.

पांच जून को बैकुंठ के अपहरण के बाद उसके बेटे ने शक़ के आधार पर पांच लोगों के नाम पुलिस को बताया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया. इसमें से एक आरोपी सीमेंट व्यवसायी डब्लू मिश्रा ने पूछताछ के क्रम में लखापुर निवासी मुन्ना सिंह का नाम बताया. कांड में नाम आने के बाद पुलिस के भय से मुन्ना ने न्यायालय में समर्पण किया. अपहृत का मोबाइल पुलिस ने झारखंड से ट्रेस किया और वहां से भी एक गिरफ्तारी हुई. आरोपी मुन्ना सिंह के न्यायालय में समर्पण के पश्चात 20 जून को पुलिस ने उसे दो दिनों की रिमांड पर लिया तथा दो दिनों तक उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता रहा. 22 जून को उसे वापस जेल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति देखकर सभी कैदियों ने हंगामा मचाया तथा भूख हड़ताल कर दी. 23 जून को मुन्ना को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया. वहां इलाज के दौरान एक जुलाई को उसकी मौत हो गई. साथ ही बैकुंठ अपहरण कांड की दिशा भी बदल गई. अब उसका स्थान मुन्ना कांड ने ले लिया. कुल मिलाकर बैकुंठ अपहरण कांड में सात आरोपियों को जेल भेजा गया, जिसमें एक आरोपी कैदी मुन्ना सिंह की पुलिस की अमानवीय पिटाई से मौत हो गई, जबकि तीन आरोपी युवराज सिंह, कुणाल मंडल व लखीसराय का कुख्यात रंजीत डॉन अब तक फ़रार है.

पुलिस रिमांड पर लिए गए मुन्ना सिंह की मौत ने बहरहाल बैकुंठ वर्णवाल अपहरण कांड में अनुसंधान को जहां हाशिए पर ला खड़ा किया है, वहीं जमुई पुलिस की अदूरदर्शी भूमिका भी कठघड़े में आ खड़ी हुई है. मुन्ना की मौत के बाद फ़ज़ीहत झेल रही जमुई पुलिस अब बैकफुट पर आ खड़ी हुई है. इस कांड से जुड़े विभाग के दो-दो थानाध्यक्षों के निलंबन के बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश तथा एक सब इंस्पेक्टर के निलंबन के साथ खुद आरक्षी अधीक्षक का तबादला हो गया, यह साबित करने के लिए कि ग़लत दिशा में चल रहे अनुसंधान में उनकी भूमिका नहीं है. अब देखना यह है कि नए पुलिस कप्तान के आने के बाद पुलिस का आचरण कैसा रहता है और कितनी जल्दी अपहरण कांड की गुत्थी सुलझ जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

लोजपा में आपसी कलह

लोजपा का कमान सीतामढ़ी ज़िला में दो नेताओं के हाथों में है. पार्टी के अंदर भी गुटबाज़ी ज़ोरों पर है. ऐसे में देखना यह है कि आगामी चुनाव में पार्टी का क्या हश्र होता है...

वाल्मीकि कुमार

तक़रीबन 12 साल से सीतामढ़ी ज़िले में पार्टी का झंडा लहराने वाले लोजपा जिलाध्यक्ष की कुर्सी अब दांव पर लगी हुई है. इसीलिए प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आगामी अक्टूबर माह में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी के ज़िला संगठन में हलचल की शुरुआत हो गई है. सीतामढ़ी ज़िला में पार्टी का कमान फिलहाल दो नेताओं के हाथों में बताई जा रही है. नतीजतन, पार्टी के अंदर गुटबाज़ी का मामला भी ज़ोर पकड़ रहा है. एक ओर, पार्टी की पूर्व विधायक नगीना देवी कार्यकर्ताओं के बीच रह कर पार्टी संगठन की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं, तो दूसरी ओर प्रयासरत हैं पिछले विधान सभा चुनाव में जीत के क़रीब पहुंच कर भी हार का सामना करने वाले पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव राघवेंद्र सिंह कुशवाहा. इन दोनों ही नेताओं पर ज़िला में पार्टी की जीवंतता कायम रखने की चर्चा है. वैसे हाल के महीनों में दोनों ही नेताओं के बीच शुरू तक़रार अब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पहेली बनी है. फिलहाल, दो खेमों में विभक्त लोजपा पार्टी संगठन का असली चेहरा तब उजागर होने की उम्मीद बताई जा रही है, जब महज दो माह बाद होने वाले जिलाध्यक्ष चुनाव में दोनों ही अपने चहेते को उक्त कुर्सी पर बैठाने को लेकर आमने-सामने होंगे. बताया यह भी जाता है कि वर्ष 2001 से लेकर अब तक लगातार सीतामढ़ी ज़िला में लोजपा जिलाध्यक्ष के रूप में मोहन झा विराजमान रहे हैं. इस बीच पार्टी के अंदर दर्जनों ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता उभर कर सामने आए हैं, जो पार्टी संगठन के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं. इनमें जिलाध्यक्ष झा के अलावा, सवीह अहमद और नसीबुल हक़ का भी नाम लिया जा रहा है.

चर्चाओं पर भरोसा करें, तो आसन्न जिलाध्यक्ष के चुनाव में झा के अलावा वे दोनों भी चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, जिसमें अहमद का पलड़ा भारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. पार्टी का एक खेमा जहां प्रदेश प्रधान महासचिव कुशवाहा को पार्टी हित के लिए उपयुक्त नहीं मानता, तो वहीं पूर्व विधायक नगीना देवी को आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के रूप में शिवहर अथवा सीतामढ़ी जिला से चुनावी समर में आने की संभावना जता रहे हैं. फिलहाल पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन झा से भी कुशवाहा का छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है. झा का कहना है कि अब तक के कार्यकाल में तक़रीबन डेढ़ लाख सदस्य बनाने का काम पूरे ज़िले में किया है. इसे बढ़ा कर अब ढाई लाख तक ले जाने का इरादा है. उनका कहना है कि पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को जनता की मानसिकता को समझने की आवश्यकता है. अन्यथा ज़िले में पार्टी संगठन इस क़दर कमजोर पड़ सकती है कि आने वाले समय में इसे संभालना आसान नहीं होगा. अब सामने लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं लोजपा ज़िले में अपनी स्थिति को कायम रख पाती है या आपसी कलह के भंवर में फंस कर रह जाएगी, यह फिलहाल कहना मुश्किल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

वजूद खोता विश्व प्रसिद्ध अरेराज मंदिर

बिहार में सरकार की उदासीनता के कारण ऐतिहासिक इमारतों की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है. चंपारण का अरेराज मंदिर आस्था का प्रतीक है, लेकिन अब यह आवारा कुत्तों और सुअरों की चारागाह बन गया है...

मुकुल कुमार पांडेय

पूर्वी चंपारण ज़िले में स्थित अरेराज मंदिर की हालत काफ़ी ख़राब है. तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए स्थापित धर्मशाला जहां एक तरफ़ अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी ओर मंदिर से सटा मंडप आवारा कुत्तों और सुअरों की चारागाह बना हुआ है. इसके अलावा, माता पार्वती के नाम से बना पार्वती कुंड जिसमें भक्त स्नान कर मंदिर में प्रवेश करते थे, उसका किनारा मूत्रालय में तब्दील हो गया है और इसीलिए कुंड का जल भी दूषित हो गया है. लाखों-करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनकर महादेव की जयकार से हमेशा गूंजने वाले इस तीर्थ स्थल को विकसित करने व ज्वलंत समस्याओं को निपटाने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं समिति द्वारा तो ज़रूर बनाई जाती हं, लेकिन इन पर अमल नहीं किया जाता. ऐसी बात नहीं है कि विकास के लिए फंड नहीं है. कड़वा सच तो यह है कि भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है. जानकार बताते हैं कि श्री सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर एवं अरेराज मठ न्यास समिति से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी केवल विकास के नाम पर खानापूर्ति करते हैं और राशि का बंदरबांट होता है. स्थानीय पंडा पुजारियों की मानें, तो कुंड की सफाई के नाम पर नाटक किया जाता है और लाखों रुपये हजम कर लिए जाते हैं. श्रावण, अनंत चतुर्दशी, शिवरात्रि, दशहरा व बसंत पंचमी आदि मौक़ों पर तीर्थ यात्री अनेक समस्याओं से जूझते रहते हैं. इधर, मंदिर न्यास समिति बोर्ड के अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी शंभुशरण पांडेय व सचिव मदन मोहन नाथ तिवारी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

29 जुलाई–04 अगस्त 2013

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

लखनऊ

यूपीपीएसी में आरक्षण

छात्रों का भविष्य दांव पर

उत्तर प्रदेश एक बार फिर आरक्षण की आग में जल रहा है. इस बार मामला राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में आरक्षण का है. छात्रों का आरोप है कि आरक्षण की नई व्यवस्था जाति विशेष को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है.

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण की आग सुलगने लगी है. 15 जुलाई को इलाहाबाद की सड़कों पर उपद्रव के रूप में इसका नजारा भी देखने को मिला. इसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) के कर्ता-धर्ता ही ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने बिना सोचे-समझे पीसीएस परीक्षा समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण ओवर लैपिंग का विवादित फार्मूला प्रारंभिक परीक्षा से ही लागू कर दिया है. गौरतलब है कि पीसीएस 2011 की मुख्य परीक्षा में ओवर लैपिंग लागू होने के बाद बड़ी संख्या में सामान्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए थे. नई आरक्षण नीति सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों पर कहर बनकर टूटी, तो पांच दिनों तक शांतिपूर्वक चलने वाला उनका आंदोलन पांचवें दिन हिंसा के रूप में सड़क पर आ गया. न केवल सरकारी और निजी संपत्ति का नुक़सान हुआ, बल्कि 50 से भी अधिक लोग घायल हो गए. दिन भर हिंसा का दौर चला. मामला जब ज़्यादा गरमाने लगा, तो शाम को लोकसेवा आयोग के सचिव ने छात्रों को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, कार्रवाई का भरोसा दिलाकर मामला शांत कर दिया. हालांकि यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन समय रहते कुछ नहीं किया गया. सच तो यह है कि यदि यूपीपीएससी के अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से आंदोलन के पहले ही दिन बातचीत कर ली होती (जब उन्होंने नई आरक्षण नीति के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी थी), तो शायद युवाओं को अपनी मांगें मनवाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना पड़ता.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश सरकार को उन कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है, जिनके चलते राज्य लोकसेवा आयोग की आरक्षण नीति के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे. छात्रों की मानें, तो आयोग की परीक्षाओं में आरक्षण की जो नई व्यवस्था की गई है, वह एक जाति विशेष (यादव बिरादरी) को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए की गई है. इस जाति विशेष को लाभ पहुंचा कर सरकार का वफादार बनने की चाहत रखने वाले यूपी लोकसेवा आयोग के सदस्य गुरुदर्शन सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने अदालत की गाइडलाइन की परवाह नहीं करते हुए 27 मई, 2013 को आयोग के अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखा था कि लोकसेवा आयोग चयन परीक्षा के प्रत्येक चरण में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक़, आरक्षण का लाभ किसी भी परीक्षा के अंतिम परिणाम में ही दिया जाता है. कुल रिक्त सीटों के मुक़ाबले आरक्षित सीटें तय की जाती हैं. और इसी के आधार पर परिणाम में कोटा तय होता है. गुरुदर्शन सिंह दबाव में थे या फिर अपना नंबर बढ़ाना चाहते थे, यह तो वही जानें, लेकिन सिंह के चलते राज्यपाल की अनुमति के बिना इस प्रस्ताव को इसी दिन मंज़ूरी मिल गई. यह ख़बर फैलते ही सामान्य श्रेणी के प्रतियोगी छात्र ग़ुस्से में आ गए.

इस घटना से पहले भी कुछ छात्र अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके थे, जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण नियमों में बदलाव किए जाने पर राज्य सरकार व आयोग से जवाब तलब मांग रखा था. सुधीर कुमार और अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एल के महापात्र तथा न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है. याचिका में परीक्षा के दौरान हर स्तर पर आरक्षण की नई नीति लागू करने को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की आड़ में एक जाति विशेष को नाजायज़ लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. इस व्यवस्था से सामान्य वर्ग के प्रतियोगियों का भविष्य आयोग दांव पर लगा रहा है. याची का कहना है कि 1994 की आरक्षण नियमावली के तहत पद के सापेक्ष नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन आयोग ने चयन प्रक्रिया के हर स्तर पर आरक्षण लागू कर सामान्य वर्ग के प्रतिभागियों के अवसर को कम कर दिया है. आरक्षित जातियों को आरक्षण की 50 फीसद सीमा से अधिक सीटों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मखौल उड़ाया जा रहा है. इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमावली के तहत ही आरक्षण दिया जा रहा है. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा मेरिट में स्थान पाने पर सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना विधिसम्मत है. अदालत के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या चयन प्रक्रिया में हर स्तर पर आरक्षण देकर परिणाम घोषित किया जा सकता है?

खैर, पूरे प्रकरण को देखने के बाद सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है. इस मामले में छात्रों की उद्दंडता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है. छात्रों ने जो कुछ किया, वह इसलिए उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मामला कोर्ट में है. छात्रों को उच्च न्यायलय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी. जब छात्रों ने आरक्षण नीति में बदलाव के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी थी, तब उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था. हालांकि इन बातों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कुछ परीक्षाओं में जाति विशेष के लोगों को खास प्रश्रय दिया गया है. इस संदर्भ में

छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के जो आंकड़े सामने रखे हैं, वे कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में नई आरक्षण नीति पर ही सवाल खड़े करते हैं. लगता है, सपा सरकार राजनीतिक हित साधने के लिए आरक्षण की व्यवस्था का मनमाना इस्तेमाल कर रही है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े तबकों के उत्थान के लिए है, न कि किसी विशेष जाति या वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए. अब देखना यह है कि राज्य सरकार और राज्य लोकसेवा आयोग की ओर से नई आरक्षण नीति को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए सवाल का क्या जवाब दिया जाता है. भाजपा प्रवक्ता विजय पाठक ने इलाहाबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सपा सरकार के इशारे पर छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं. छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की बजाए युवा सीएम ने इनकी ज़ुबान बंद करने का फार्मूला ज़्यादा बेहतर समझा. अगर ऐसा न होता, तो छात्रों की समस्या का समाधान हो सकता था. एक तरफ यूपी लोकसेवा आयोग का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर महासभा ने लोकसेवा आयोग का समर्थन किया है. महासभा के अध्यक्ष डॉ लालजी प्रसाद निर्मल का कहना था कि सामान्य वर्ग की रिक्तियां केवल सामान्य जातियों के लिए आरक्षित नहीं हैं, बल्कि सामान्य कोटे के पद सभी वर्गों के लिए होते हैं. इसलिए लोकसेवा आयोग के आरक्षण फार्मूले का विरोध उचित नहीं है.■

लखनऊ

कांग्रेस को मोदी फोबिया!

लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अमित शाह को, तो कांग्रेस ने मिस्त्री को चुनावी दंगल में उतार दिया है. हालांकि मोदी के कद के सामने कांग्रेस के मिस्त्री बौने हैं और इसी कारण उन्हें मोदी फोबिया हो गया है.

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की धरती इस समय दो गुजरातियों की राजनीतिक रणभूमि बन चुकी है. भाजपा को शाह, तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए मिस्त्री मिल गया है. जी हां, इस समय उत्तर प्रदेश में मिस्त्री के कंधों पर कांग्रेस की बुनियाद मज़बूत करने की ज़िम्मेदारी है. कांग्रेस यूपी में क़रीब दो दशकों से संघर्ष कर रही है. भाजपा भी अपनी सीट बढ़ाने में प्रयासरत है, लेकिन दोनों ही दल भीतरघात और आपसी कलह जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. 2009 के लोकसभा और 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने काफी कोशिश की थी कि किसी तरह से पार्टी को इन समस्याओं से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन उनकी हसरत परवान नहीं चढ़ सकी. लोकसभा चुनाव में राहुल पार्टी की लाज जरूर बचा ले गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका ग्राफ नीचे गिर गया. वैसे, दोनों ही बार वह ही मैन की तरह यूपी वालों के सामने प्रकट हुए और लोगों के दिलोदिमाग पर छा गए. राहुल का कुर्ते की बांहें चढ़ा कर भाषण देने का अंदाज़ खूब चर्चा में रहा. युवराज का प्रचार अभियान काफी धमाकेदार रहा और मीडिया ने भी उनको कुछ ज़्यादा कवरेज दीं. जनता ने उनकी (राहुल) बातें सुनीं तो ज़रूर, पर विश्वास नहीं किया. यही कारण है कि वह लोकसभा चुनाव 2009 में सिर्फ 22 सीटें ही कांग्रेस को दिला पाने में सफल हुए और 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से धुल गई. यह तब हुआ, जब कांग्रेसी एकजुट होकर राहुल गांधी का टेम्पो हाई कर रहे थे. राहुल सेना के कमांडर की तरह आगे बढ़कर मोर्चा संभाले हुए थे, पर कांग्रेसी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा. पिछली हार से सबक लेते हुए और अधिक बदनामी से बचने के लिए राहुल ने अपने आप रोल बैक कर लिया है और गुजरात के नेता और सांसद मधुसूदन मिस्त्री को इस बार फ्रंट पर खड़ा कर दिया है.

मधुसूदन गुजरात में कभी नरेन्द्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाए, मगर यूपी में उनके खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं. वह यूपी की जनता को मोदी की हकीक़त बता रहे हैं. इन्हें (मोदी को) कारपोरेट घराने का एजेंट क़रार दे रहे हैं. जिस तरह की भाषा वह बोल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अन्य तमाम कांग्रेसियों की तरह मिस्त्री भी मोदी को लेकर ख़ौफज़दा हैं. एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि कहीं कांग्रेस ने मिस्त्री को प्रभारी बना कर चूक तो नहीं कर दी. अमित शाह और इनके गुरु मोदी को लेकर मिस्त्री अजीब से पशोपेश में दिखते हैं. मोदी का कद उन्हें परेशान कर रहा है. इसीलिए वह मोदी के खिलाफ बोलते हुए गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हैं. पिछले दिनों उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईश्वर करे कि किसी राज्य में गुजरात जैसी स्थिति न हो. वह यह भूल गए कि वह ऐसा कहकर उन छह करोड़ गुजरातियों के इस निर्णय को नकार रहे हैं, जिन्होंने मोदी को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया था और कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा था.

हालात यह है कि अमित शाह आगे-आगे चल रहे हैं और मिस्त्री पीछे-पीछे. अमित शाह को देखकर कांग्रेसी मिस्त्री से कार्यक्रम तय कर रहे हैं. भाजपा ने अमित शाह का कार्यक्रम अयोध्या में रखा, तो कांग्रेस ने मिस्त्री का प्रोग्राम बना दिया. कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की हरकतों से इसके मुस्लिम वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा. मिस्त्री मोदी फोबिया से बुरी तरह से ग्रस्त हैं. यह बीमारी वह गुजरात से ही लेकर आए हैं. आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि कहीं पूरी कांग्रेस को ही वह मोदी फोबिया से ग्रस्त न कर दें.■

उत्तराखंड आपदा को निमंत्रण!

उत्तराखंड आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन आज भी देश के तमाम हिस्सों में अवैध खनन, निर्माण और जंगलों की कटाई जारी है. ताजा उदाहरण सहारनपुर का है, जहां खुलेआम अवैध खनन का खतरनाक खेल खेला जा रहा है. पढ़िए यह रिपोर्ट...

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड त्रासदी में आज भी कई परिवार लापता हैं. करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, सो अलग. सरकारी आंकड़े भले ही इस आपदा में मरने वालों की संख्या हजार के आसपास बता रहे हों, लेकिन इस आपदा में मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है. स्थानीय नागरिकों और इस हादसे से बचकर आए लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, वह दिल दहला देने वाला है. वे कहते हैं कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या दस हजार से अधिक हो सकती है. इस हादसे ने एक और विवादास्पद बहस को जन्म दे दिया है. बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हादसा पूरी तरह से प्राकृतिक था, जिसे रोकना असंभव था? या फिर यह एक मानव जनित आपदा थी? भू-वैज्ञानिकों की मानें, तो बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं तो प्राकृतिक ही होती हैं, लेकिन उनकेचलते जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ, वह पूरी तरह से मानव निर्मित था. विशेषज्ञों के अनुसार, नदियों के फ्लड जोन में अतिक्रमण, संवेदनशील इलाकों में खनन और मोटर रोड या विद्युत परियोजनाओं आदि को बनाने केलिए ब्लास्टिंग करना, ऐसे हादसों के महत्वपूर्ण कारणों में से एक हैं.

भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस भूल से जब कोई सबक न ले और उसके बाद दूसरी भूल करे, तो आनेवाला समय संकटपूर्ण होना स्वाभाविक है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश केसहारनपुर जिले का है, जहां उत्तराखंड जैसी त्रासदी के बाद भी लोगों ने कोई सीख नहीं ली. जिला प्रशासन केसंरक्षण में यहां लंबे समय से अवैध खनन और स्टोन क्रशर चलाए जा रहे हैं. हथनीकुंड बैराज जैसा संवेदनशील इलाका भी इससे अछूता नहीं है. इस बैराज केआस-पास कई स्टोन क्रशर काम कर रहे हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि इन क्रशरों केलिए खनन सामग्री भी अवैध रूप से इसी इलाकेसे निकाली जा रही है, जिससे यह इलाका असुरक्षित होता जा रहा है. स्थानीय नागरिक इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, इसकेबावजूद जिले में आज तक अवैध खनन पर रोक नहीं लग सकी है. 2011 में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सैनी ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार केसंबंधित विभागों केसाथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय को सहारनपुर में हो रहे अवैध खनन केसंबंध में पत्र लिखा. सर्वोच्च न्यायालय इसे गंभीरता से लेते हुए आशीष केपत्र का संज्ञान भी लिया और 25 सितंबर, 2011 को इसकी जांच केआदेश दे दिए.

सर्वोच्च न्यायालय केआदेश पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस मामले की जांच की. कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट 4 जनवरी, 2012 को न्यायालय में पेश की. जांच में जो बात सामने आई, उसके बारे में पता चलने के बाद लोगों के होश उड़ गए. एक बार फिर देश के अन्य भागों की तरह ही सहारनपुर में भी नेताओं, अधिकारियों और स्थानीय दबंगों के गठजोड़ की बातें सामने आईं. रिपोर्ट में बताया गया है कि सहारनपुर जिले में कई खनन पट्टे अवैध रूप से आवंटित किए गए हैं,

जिनमें खनन धड़ल्ले से जारी है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अवैध खनन का यह काम जिला प्रशासन केसंरक्षण में हो रहा है, जो कि ध्यान देने लायक है. आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस अवैध काम को रोकने के लिए प्रशासन का गठन किया गया है, उसके लाव-लश्कर भी इस काम को नहीं रोक पा रहे हैं, उल्टे प्रशासन की आड़ में इन कार्यों को बढ़ावा ही दिया जा रहा है. जांच में यह भी पाया गया कि यमुना केआस-पास 70 स्टोन क्रशर अवैध तरीकों से चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कइयों को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त या सील किया हुआ दिखाया गया है. इस रिपोर्ट केआधार पर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को गैरकानूनी तरीकेसे चल रहे खनन कार्यों एवं स्टोन क्रशरों पर तुरंत रोक लगाने केआदेश दिए. सूत्रों के अनुसार, जांच में सिर्फ 90 स्टोन क्रशर ही वैध पाए गए.

सच्चाई यह है कि नियमानुसार पट्टों केनवीनीकरण और आवंटन केलिए नीलामी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, लेकिन ये सभी पट्टे बिना नीलामी केही आवंटित कर दिए गए. हद तो तब हो गई, जब इन पट्टों को उन्हीं लोगों को आवंटित किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय की जांच में अवैध खनन केदोषी पाए गए थे. ऐसा करते समय लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी परवाह नहीं की. पट्टे धारकों पर इस मेहरबानी से प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. हम यह बात अनायास ही नहीं कह रहे, बल्कि इन अवैध कार्यों में राज्य में बड़े और रसूखदार नेताओं के जो नाम सुनने में आ रहे हैं, उसी के आधार पर यह बात कही जा रही है. सूत्रों के अनुसार, बसपा नेता मोहम्मद इकबाल केलोगों केपास ही सारे खनन पट्टे हैं. यह अपने आप में प्रशासन और नेताओं के गठजोड़ की कहानी कहता है. भले ही प्रशासन इस बात से कितना भी इंकार करे, लेकिन यह सच है कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे ही हो रहा है.

सवाल सिर्फ पट्टों का ही नहीं, बल्कि इस तरह के उन सारे कार्यों का है, जो पर्यावरण विरोधी हैं. चाहे जंगल की कटाई हो, जलाशयों को दूषित करने की बात या फिर वायू को प्रदूषित करना, ये सारे कार्य पर्यावरण विरोधी हैं, जो आने वाले समय में उत्तराखंड जैसी त्रासदी को ही जन्म देते हैं. जब आपदा सिर पर आती है, तो चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. सरकारें हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाती हैं और नेताओं को भाषणबाजी से फुर्सत नहीं होती. ऐसे में आने वाले समय में सिस्टम के ठीक होने की भी कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि सरकारें देश या राज्य के विकास के मूल एजेंडे से हट गई हैं और दिन-रात भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. हर दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं. ऐसे में एक बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि क्यों न हम खुद से ही कुछ ऐसा करें, जिससे कि पर्यावरण और मानव विकास में संतुलन बनी रहे. अगर हम तथाकथित विकास के बदले विनाश को न्योता नहीं देंगे, तो नदियां, जंगल और पहाड़ प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रकृति प्रेम से ही संभव है.

इसके लिए हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि वह अपने आस-पास पेड़-पौधों को लगाए, जलाशयों को दूषित न करे, बेवजह पानी बर्बाद न करे और एसी, कार या अन्य प्रदूषक चीजों का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करे. ■

feedback@chauthiduniya.com

बलिया

डाकघर बचत स्कीम : आम आदमी का सहारा

यह नाइंसाफी क्यों

यदि डाकघर में चलने वाली बचत स्कीमों को बंद कर दिया जाए, तो लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा और डाकघर सिर्फ शो-पीस बनकर रह जाएंगे. सरकार को चाहिए कि ऐसी योजनाओं पर वह विशेष ध्यान दे, क्योंकि लालफीताशाही के चंगुल में फंसकर ये योजनाएं धीरे-धीरे अपना आकर्षण खो रही हैं.

शिवनाथ चतुर्वेदी

अफसरों की लालफीताशाही के चलते आम जनता में लोकप्रिय राष्ट्रीय बचत योजनाओं का आकर्षण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. और ऐसे में लाखों की तादाद में लगे अभिकर्ताओं की रोज़ी-रोटी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. गौरतलब है कि बचत की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से डाकघरों द्वारा इन्हें संचालित किया जाता है. इन योजनाओं में किए गए निवेश के भुगतान की गारंटी केन्द्र सरकार की होती है. यह ध्यान देने की बात है कि यदि डाकघर से इन योजनाओं को अलग कर दिया जाए, तो डाकघर सिर्फ एक शो-पीस बनकर रह जाएंगे. चिट्ठी-पत्री का ज़माना तो लद गया. रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट की आय से भारी-भरकम अफसरों और कर्मचारियों की तनख्वाह पूरा कर पाना नामुमकिन हो जाएगा.

पूर्व राजग सरकार ने कार्पोरेट घरानों के चक्कर में आकर इन बचत स्कीमों का भट्ठा बैठाना शुरू कर दिया था, इसलिए किसान विकास पत्रों पर मिलने वाले आकर्षक ब्याज को प्रतिवर्ष कम किया जाने लगा. ब्याज राशि निरंतर घटाते जाने से धन दुगना होने की समय सीमा बढ़ने के कारण लोगों का रुझान डाकघरों की बजाय बैंकों की तरफ हो गया है. ऐसे में कार्पोरेट घरानों की मंशा पूरी हो गई है और बैंको के माध्यम से इसका फायदा भी उन्होंने भरपूर उठाया. राजग ने अपने कार्यकाल में बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने की बजाय अपना सारा ध्यान उन्हें हतोत्साहित करने में लगाई और जनता जब इस बात को भलीभांति समझ गई, तो उसने चुनाव में भाजपा सरकार को उसकी ताकत समझा दी.

गनीमत यही है कि संप्रग-1 सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इन योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की, पर संप्रग-2 का कार्यकाल इस संदर्भ में काफी निराशाजनक ही रहा. किसान विकास पत्र योजना, यद्यपि राजग सरकार में ही आठ वर्ष सात माह में धन दुगना करने वाली हो गई थी, फिर भी इसकी खासियत यह थी कि जरूरत पड़ने पर इसे ढाई वर्षों बाद जब चाहे निकाला जा सकता था. इसके लचीलेपन की वजह से ही लोग इसके मुरीद थे, किन्तु दुर्भाग्य की बात यह हुई कि संप्रग-2 सरकार भी कार्पोरेट घरानों के चक्कर में पड़कर इन योजनाओं को तहस-नहस करने पर तुल गई. एक सुनियोजित साजिश के तहत राष्ट्रीय बचत योजनाओं की समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई. इस कमेटी में यद्यपि योजनाओं के ब्याज में बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया, पर राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले अभिकर्ताओं की कमीशन राशि को 1 प्रतिशत की बजाय 0.5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया, जिसे सरकार ने अंततः मान लिया. कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कमीशन मद में भारी राजस्व के खर्च का आंकड़ा तो दिखाया गया, पर उसके एवज में अभिकर्ताओं द्वारा लोगों को प्रेरित कर राष्ट्रीय पैमाने पर कितनी धनराशि जमा कराई गई, उसका कुछ भी जिक्र नहीं है. दरअसल, जो कमेटी गठित की गई, उसमें न तो राष्ट्रीय बचत योजनाओं के विशेषज्ञों को शामिल किया गया और न ही अभिकर्ताओं और संगठनों के प्रतिनिधियों को. जाहिर है, कमेटी की रिपोर्ट एकतरफा और पूर्वाग्रह ग्रस्त रही, जिसको आधार बनाकर सरकार ने अभिकर्ताओं की रोजी-रोटी से खिलवाड़ किया. इसे लेकर अभिकर्ताओं ने जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन भी किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला. दरअसल, इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके साथ यह नाइंसाफी हुई है.

संप्रग-2 सरकार ने कमेटी की एकतरफा रिपोर्ट को आधार बनाकर अभिकर्ताओं की कमीशन राशि को तो एक प्रतिशत की बजाय 0.5 प्रतिशत कर ही दिया. सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आम लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय किसान विकास पत्रों का प्रचलन बन्द करके इसकी जगह पांच वर्षीय और 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों को जारी किया गया. गौरतलब है कि इन पत्रों में निवेश किए गए धन को बीच में भुनाने की सुविधा ही नहीं है. कम से कम तीन वर्ष बाद भुनाने की सुविधा रखी गई होती, तब भी लोगों को सहूलियत होती, पर योजनाकारों ने इस बात को पूरी तरह से नज़रंदाज़ कर दिया. इस संबंध में राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संगठनों द्वारा भेजे गए उपयोगी सुझावों को कोई महत्व नहीं दिया गया. दूसरी बात यह हुई कि राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया कि इसके चलते लोग किनारा करने लगे. अब जरूरत इस बात की है कि इस संबंध में रचनात्मक और आम लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली नीतियां बनाई जाएं, ताकि राष्ट्रीय बचत योजनाओं में लोगों का विश्वास पुनः बहाल हो सके. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

बलिया

विनाश को न्योता

पर्यावरण की कीमत पर मानव तथाकथित विकास को न्योता दे रहा है. फलस्वरूप झील-झरनों सहित अन्य जल स्त्रोत तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं. समय रहते अगर हम नहीं संभले, तो आने वाला समय विकास का नहीं, विनाश का होगा. उत्तराखंड त्रासदी इसका ताजा उदाहरण है.

शिवनाथ चतुर्वेदी

लालच, लापवाही के परिणाम और आधुनिक विकास के अनियोजित मॉडल ने प्रकृति और पर्यावरण के पूरक मानव को इसका प्रतिद्वंद्वी बना दिया है. जलाशय, नाले, गड़हिया झीलों और झरनों को भरा और पाटा जा रहा है. दूसरी ओर, बंद-पहाड़ों को काट-छांट कर नष्ट-भ्रष्ट और अतिक्रमित किया जा रहा है. बरसात के जल का ठहराव न होने से जल-स्तर चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है. शासन के कई विभागों द्वारा जल संरक्षण के नाम पर चलाई जा रही आधी-अधूरी योजनाएं मुंह चिढ़ा रही हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे इससे जुड़े प्रकृति के अन्य तत्वों को बचाया जाए. यह समस्या मानव समाज के सामने एक बड़ी चुनौती बन कर उभरी है. जल संरक्षण के वास्तविक हालात और इसके निदान पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं.

समाजसेवी अजय कुमार बताते हैं कि ग्रामीण भारत के पुरातन तौर-तरीके नकार कर आधुनिक विकास के जो मॉडल स्वीकार किए गए हैं, उनमें जल, जंगल और जानवर को कहीं भी स्थान नहीं मिल सका है. उनका दोहन किया जा रहा है. ऐसे में ग्राम पंचायतों और शासन के कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित होना ही चाहिए. कृषि वैज्ञानिक डॉ कठिन सिंह ने बताया कि गांव में पाटी गई प्राचीन गड़हियों और तालाबों को पूर्वस्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए. उनका सौंदर्यीकरण जरूरी है और उनके रख-रखाव के लिए पंचायत और शासन को समान रूप से उत्तरदाई बनाया जाना चाहिए. जल संरक्षण की दिशा में अगर ठोस प्रयास नहीं किया गया, तो भविष्य में भीषण संकट खड़ा हो सकता है. इस संकट से सभ्यता और संस्कृति के विनाश का खतरा भी हो सकता है.

व्यंग्यकार भोला प्रसाद आग्नेय का मानना है कि मैदानों को समतल कर आवासीय कालोनियां बनाई जा रही हैं. वृक्षारोपण व मनरेगा सहित अन्य योजनाओं को कागज पर पूरा कर दिया जा रहा है. ऐसे में जल संरक्षण की बात करना बेमानी ही है. जन जागरुकता के साथ ही प्रशासनिक प्रतिबद्धता के बिना जल संरक्षण नहीं किया जा सकता.

हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति) के राष्ट्रीय महासचिव डी पी यादव कहते हैं कि पानी है, तो मानव का जीवन है. छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोग अपने ही जीवन से खेल रहे हैं. अगर इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. अधिवक्ता हंसराज तिवारी कहते हैं कि निरंतर पेड़ कट रहे हैं. वनों के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है. नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है. गांव में जलाशय और गड़हियों को पाट कर अतिक्रमण किया जा रहा है. ऐसे में भाषण की बजाय जल और जंगल से लोगों को जोड़ कर उन्हें पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाना चाहिए. और इसके लिए प्रशासनिक कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. जब इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल होगी, तभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है.

युवा पत्रकार हृदयानंद आजाद का कहना है कि मानव अपने विकास के क्रम में प्रकृति के साथ समन्वय कभी नहीं रख पाया. जल संरक्षण की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम तेजी से विनाश की दिशा में बढ़ते ही जा रहे हैं. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

देहरादून

इस सरकार को तत्काल बरखास्त किया जाए : राज्यलक्ष्मी

राजकुमार शर्मा

हाल ही में टिहरी लोकसभा की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान आपदा के बाद का जो नजारा उन्होंने देखा, उससे वह काफी दुखी हुईं. उन्होंने अपना दुख बांटते हुए कहा कि सांसद की हैसियत से जनता का जितना दुख दर्द बाटा जा सकता है, उतना मैं हर जगह घूम घूम कर बांट रही हूं. सांसद रानी का मानना है कि जो सरकार जनता की विपत्ति में न दिखे और उनकी विपत्ति में उनका सहारा न बने, उस सरकार को बने रहने का कोई हक ही नहीं है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनके युवराज केवल पिकनिक मनाने के लिए हेलिकाप्टर का प्रयोग कर रहे हैं. साकेत के हेलिकाप्टर के प्रयोग के औचित्य पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आपदा में युवराज दिखने का नाटक बंद होना चाहिए. गौरतलब है कि रानी ने टिहरी उपचुनाव में विजय बहुगुणा की सीट से उनके पुत्र साकेत को भारी मतों से पराजित कर अपनी जीत प्राप्त की थी. सांसद ने सरकार को कोसते हुए कहा कि ऐसी सरकार, जो आपदा में लोगों का साथ नहीं दे सकती, उसे बर्खास्त कर देना ही बेहतर होगा. ■

सुदूर क्षेत्रों में सरकार का न पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण : निशंक

उत्तरकाशी के सुदूर हिमालयी गांव का पैदल भ्रमण कर दुर्घटना होने से बाल-बाल बच गए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक. उन्होंने आपदा में जनता की अपेक्षा पर सरकार के खरा न उतरने पर सरकार को खूब और खूब कोसा और कहा कि आज एक माह व्यतीत होने के बावजूद आपदा पीड़ितों तक सरकारी तंत्र का न पहुंचना इस बात का आभास भी जनता को करा रहा है कि सूबे में कोई सरकार ही नहीं है. निशंक का मानना है कि अकेले उत्तरकाशी में इतनी तबाही हुई है कि जनता के समक्ष दो जून की रोटी की समस्या मुंह बाए खड़ी है. कई ऐसे गांव है, जहां लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकारी तंत्र और सरकार को उसका संज्ञान भी नहीं है. निशंक ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से फेल है. जब मुखिया और उसका परिवार संवेदनहीन हो, तो अफसरशाही किस तरह की सेवा कर सकती है, यह स्वंय इस आपदा की घड़ी में जमीनी हकीकत से पता लगाया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ

गाजियाबाद में वर्चस्व की लड़ाई जारी

घमासान की संभावना

गाजियाबाद में अधिकारियों की तैनाती में वरिष्ठता नहीं, वफादारी और बिरादरी देखी जाती है और इस तरह के ट्रांस्फर-पोस्टिंग का सारा काम सपा के प्रोफेसर और मैडम देखती हैं. पक्षपात इसी तरह से चलता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब वर्चस्व की लड़ाई में घमासान लगभग तय है.

अजय कुमार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद हमेशा सुर्खियों में रहता है. राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त जिला गाजियाबाद राजनेताओं, नौकरशाहों, दौलतमंदों, सरकारी अधिकारियों, फिल्म निर्देशकों, भू-माफियाओं और दबंगों को खूब रास आता है. जमीन यहां सोना उगलती है, तो गगनचुंबी इमारतें आसमानों से बातें करती हैं. विकास के नाम पर यहां सरकारी खजाने की खूब लूट होती है. इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि विकास के मामले में यह गाजियाबाद इलाका राज्य से काफी आगे निकल गया है. उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, इसके लिए गाजियाबाद और गौतम बुद्धनगर (नोएडा) जिला हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि यहां सत्तारूढ़ दल के नेताओं की पसंद वाले अधिकारियों को ही पोस्टिंग मिलती है. कई मामलों में तो गाजियाबाद और गौतम बुद्धनगर को लखनऊ से भी अधिक महत्व मिला हुआ है. गाजियाबाद के कुछ थाने कमाई के मामले में देश में नंबर वन हैं. कहने को तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यहां के सांसद हैं, लेकिन बसपा और सपा सरकारों के सामने वह कई मामलों में असहाय नजर आते हैं.

दोनों जिलों में दिग्गज नेता अपनी पसंद के अधिकारियों की तैनाती देखना चाहते हैं, ताकि वह भी बंदरबांट का हिस्सा बन सकें. यहां तैनात अधिकारी अपने आकाओं को खुश रखना अपना फर्ज समझते हैं. इन जिलों में सारा खेल सेटिंग-गेटिंग से होता है. गौरतलब है कि मायाराज में भी यहां भ्रष्टाचार की गंगा बही थी और सपा राज में भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अधिकारियों को यहां तैनाती के लिए काफी हाथ-पैर मारना पड़ता है और पोस्टिंग के बाद इसे बचाए रखने के लिए गोटी बिछानी पड़ती है. समाजवादी सरकार ने यहां पूर्ववर्ती बसपा सरकार की ही तरह अपनी पंसद के अधिकारियों की तैनाती कर रखी है. बसपा राज में यहां कैप्टन साहब की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता था, तो अखिलेश शासन में इन जिलों में अधिकारियों की तैनाती से लेकर सभी छोटे-बड़े फैसले सपा के प्रोफेसर और मैडम लेती हैं. दोनो में कौन कितना पॉवरफुल है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है. मजे की बात तो यह है कि यहां अधिकारियों की तैनाती में वरिष्ठता नहीं, वफादारी और बिरादरी देखी जाती है. यही वजह थी कि पिछले दिनों गाजियाबाद के एसएसपी नितिन तिवारी को इनके पद से हटाया गया, तो विपक्ष से लेकर आम जनता तक के कान खड़े हो गए. सरकार की तरफ से कहा गया कि गाजियाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, इसलिए नितिन को हटाया गया, जबकि हकीकत यह थी कि सपा के प्रोफेसर साहब इनसे खुश नहीं

थे. नितिन की जगह वरिष्ठता की परवाह न करते हुए 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी धमेन्द्र यादव को गाजियाबाद का नया कप्तान आनन-फानन में बना दिया गया. इसकी खास वजह उनका एक खास बिरादरी से होना और सपा नेताओं के साथ करीबी बताई जा रही है, जबकि उनसे (धमेन्द्र) काफी सीनियर अधिकारियों को मेरठ रेंज के ही छोटे जिलों की कप्तानी से संतोष करना पड़ रहा है. 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी राजू बाबू सिंह को बागपत और एके राघव को हापुड़, 2004 बैच के डॉ परमिंदर सिंह को गौतम बुद्धनगर, 2005 बैच के दीपक कुमार को मेरठ जैसे कम महत्वपूर्ण जिलों का भार मिला हुआ है.

गाजियाबाद की स्थिति यह है कि यहां के पुलिस महकमे में एक वर्ग विशेष का दबदबा बना हुआ है. यहां एसएसपी के पद पर धर्मेन्द्र यादव, एसपी सिटी के पद पर शिव शंकर यादव और अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर किरण यादव की तैनाती पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है. इतना ही नहीं, साहिबाबाद, इन्द्रापुरम, कवि नगर आदि थानों में 90 प्रतिशत पोस्टिंग एक वर्ग विशेष के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली हुई है. गाजियाबाद में जो अधिकारी तैनात होता है, उसकी हनक-धमक लखनऊ तक में सुनाई देती है. उन्हें सत्ता का करीबी मानकर उनके साथ शासन-प्रशासन सभी सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार करते हैं. वैसे, गाजियाबाद में पूर्व में तैनात एसएसपी नितिन तिवारी और प्रशांत कुमार के कार्यकाल में अपर पुलिस अधीक्षक की ही ज्यादा धमक थी, अब धर्मेंद्र यादव की तैनाती के बाद किरण यादव की कितनी हनक रहेगी, यह वक्त ही बताएगा, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर घमासान लगभग तय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ

राजनीति में जातिवाद और धर्म का तड़का

उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए जाति और धर्म का तड़का डालने से कभी परहेज ही नहीं किया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा जातिगत रैलियों पर रोक के फैसले के बाद अब नेताओं के माथे पर पसीना साफ झलकने लगा है. बिना किसी देरी के पिछले दरवाजे से नेताओं ने किसी भी तरह से अदालती आदेश का तोड़ खोजना भी शुरू कर दिया है.

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति जोड़ो रैलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इन रैलियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये रैलियां सत्ता के समीकरण ही नहीं बदलती हैं, बल्कि तख्ता भी पलट देती हैं. जाति जोड़ो के नाम पर समाज को तोड़ने वाले नेताओं की उत्तर भारत में भरमार है. देश के सबसे बड़े सूबे (यूपी) की जनता कभी गर्व करती थी कि यहां कभी जाति तोड़ो, समाज जोड़ो का नारा गूंजता था, लेकिन आज कोई भी राजनीतिक दल और उसके अनुयायी सर्वसमाज की बात नहीं करते. न ही किसी दल के नेता की यह महत्वाकांक्षा रहती है कि उसे सर्वमान्य नेता का तमगा मिले. कारण साफ है, क्योंकि सर्वमान्य नेता का तमगा हासिल करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं और विकास की गंगा बहानी पड़ती है. साथ ही भ्रष्टाचार से तौबा करनी होती है और अपराधियों को जेलों की सलाखों के पीछे भेजना पड़ता है, लेकिन आज के नेता शॉर्टकट अपनाकर जल्द से जल्द सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं. उनकी भरसक कोशिश यही होती है कि कुछ बिरादरियों को साथ लेकर और जोड़-तोड़ के सहारे सत्ता पर काबिज होने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े की व्यवस्था कर ली जाए.

उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की बात की जाए या फिर राजनीतिक दलों की, सभी नेताओं को जातिवाद की राजनीति में महारथ हासिल है. राज्य में इस समय पांच बड़े राजनीतिक दल हैं, जिनकी राजनीति में 90 से 95 प्रतिशत तक भागीदारी है. पांच बड़े दलों कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा और कुछ हद तक राष्ट्रीय लोकदल को इस श्रेणी में रखा जा सकता है. उक्त दलों के ही नेता करीब-करीब सभी तरह के चुनावों में जीत हासिल करते हैं, लेकिन वोट बैंक सबका बंटा हुआ है. समाजवादी पार्टी को मुसलमानों, पिछड़ों और यादवों पर भरोसा है. बसपा को दलित वोटरों से काफी उम्मीदें रहती हैं. भाजपा के पक्ष में ब्रा मण और वैश्य समुदाय के अलावा कुछ अन्य सर्वण वर्गों का झुकाव रहता है. इसी तरह से कभी मुसलमान-ब्रा मण और दलित कांग्रेस के साथ होते थे, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस को टुकड़ों में बंटे वोटों के सहारे चुनावी जंग लड़नी पड़ रही है. जातिवाद की राजनीति के समीकरण अक्सर बनते-बिगड़ते भी रहते हैं. यह जरूरी नहीं होता है कि जो जाति आज किसी विशेष पार्टी के साथ खड़ी है, वह कल भी खड़ी रहेगी. जातियों के मोहभंग होने का फायदा और नुकसान दोनों ही राजनीतिक दलों को उठाना पड़ता है

हाल ही में एक जनहित याचिका पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों के आयोजन पर अस्थाई रोक लगा कर इन दलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. जाति आधारित रैलियों पर अभी अस्थाई रोक ही लगी है. लिहाजा, इस पर कुछ अधिक बोलना ठीक नहीं होगा. बसपा ने तो इसका विरोध भी अभी से ही शुरू कर दिया है. वहीं समाजवादी पार्टी को भी अदालत का यह फरमान रास नहीं आ रहा है. हालांकि सपाई अभी खुल कर कुछ नहीं बोल रहे हैं. उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग के साथ-साथ चार प्रमुख दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नोटिस भी जारी कर दिया है. नोटिस का जवाब भी आएगा, सारी औपचारिकताएं भी पूरी होंगी और अंदर-अंदर खेल भी होगा, बाहर नैतिकता की ऊंची-ऊंची बातें होंगी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचने वालों की भी बड़ी तादात है. इसके साथ-साथ हाईकोर्ट के फैसले ने कई नये सवाल भी खड़े कर दिए हैं. जाति रैलियों पर रोक का हाईकोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है, जब उत्तर प्रदेश के 40

जिलों में बहुजन समाज पार्टी का दलित-ब्रा मण भाईचारा सम्मेलन चल रहा है. अदालत के फैसले के बाद इन सम्मेलनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई. अभी पिछले ही दिन लखनऊ में ऐसी ही एक रैली को बसपा प्रमुख मायावती ने संबोधित किया था. समाजवादी पार्टी ने भी कुछ समय पहले लखनऊ में ऐसा ही एक सम्मेलन बुलाया था. उस समय याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी, तो फैसला कहां से आता. सपा ने भी ब्रा मण, मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किया था.

सच्चाई यही है कि कोई भी दल जातिगत रैलियों से अछूता नहीं है. बसपा और सपा खुलकर, तो कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल चालाकी से राजनीति में जातिवाद और धर्म का घालमेल कर रहे हैं. बड़ा सवाल यह उठता है कि राजनीतिक पार्टियों को ही जाति और धर्म की राजनीति के लिए दोषी क्यों ठहराया जाए, समाज के लोग भी तो इसी तरह की राजनीति चाहते हैं. वे क्या कम दोषी हैं? ब्रा मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, कायस्थ महासभा, वैश्य सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, पासी सम्मेलन, दलित सम्मेलन, पसमंदा समाज का सम्मेलन समाज और राजनीतिज्ञों के गठजोड़ की कहानी बयां करता है. प्रदेश की सभी जातियों के अलग-अलग सम्मेलन हो रहे है. ऐसे सम्मेलनों में एक खास समाज के लोग भागीदारी करते हैं, तो उनको अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीतिक दलों के आका अपने नुमांइदों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं. वह उन जातियों के हित चिंतक का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. इसी के चलते विभिन्न जातियों के अलग-अलग नेता पैदा हो रहे हैं. कोई ब्रा मण नेता, तो कोई क्षत्रिय, तो कोई वैश्य, कोई यादव तो कोई पासी नेता बना फिर रहा है. इसी तरह धर्मों के भी नेता हैं, लेकिन देश का नेता बनने का किसी में माद्दा नहीं. सच्चाई यह है कि कोई देश का नेता बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि देश इन नेताओं की प्राथमिकताओं में शामिल है ही नहीं. इस ओछी मानसिकता में फंसा यह देश महापुरुषों को भी जाति के फंदे में कस देता है. महात्मा गांधी कभी देश के बापू हुआ करते थे, लेकिन वे दिन लद गए. अब गांधी जी बनिया जाति के हैं. स्वामी विवेकानंद कभी राष्ट्र के गौरव होते होंगे, अब कायस्थ जाति के हैं. समाजवादी विचारधारा के चिंतक डॉ राम मनोहर लोहिया जी अब अग्रवाल हो गए हैं. राष्ट्र के लिए त्याग, तपस्या और शौर्य के लिए कभी स्थापित रहे होंगे महाराणा प्रताप, कभी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा, लेकिन आज महाराणा प्रताप राजपूत जाति के हैं, तो बाबा साहब को दलित जाति की पहचान से नवाजा जा रहा है. सरदार वल्लभभाई पटेल कभी राष्ट्रीय एकता के पर्यायवाची रहे होंगे, लेकिन आज कुर्मी जाति के हैं. सारे महापुरुष किसी न किसी जाति के फ्रेम में बांध दिए गए हैं.

बात पिछले कुछ दशकों की करें, तो इस दौर में भी कई सर्वमान्य नेताओं को उनके समर्थकों ने समय-समय पर जातिवाद की चासनी में खूब डुबोया. भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी, कलराज मिश्र, मुरली मनोहर जोशी को ब्रा मण, कल्याण सिंह को लोध, राजनाथ सिंह को क्षत्रिय, ओम प्रकाश सिंह को पिछड़ा समाज, विनय कटियार को हिन्दुत्व का चेहरा बनाकर खूब राजनीति की. इसी तरह से कांग्रेस ने पहले कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, राम प्रकाश गुप्ता, महावीर प्रसाद जैसे तमाम नेताओं का इस्तेमाल जातिवाद की राजनीति को हवा देने के लिए की और अब यही काम केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेता कर रहे हैं. तीन बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने आप को पिछड़ों और मुसलमानों के नेता के रूप में प्रचारित-प्रसारित करते रहे. यही काम अब उनके पुत्र अखिलेश यादव कर रहे हैं. सपा मे आजम खां अपने आप को अल्पसंख्यकों का रहनुमा, तो नरेश अग्रवाल वैश्य समाज का ठेकेदार समझते हैं. मायावती तो अपने आप को दलितों का मसीहा ही मानती हैं. भले ही उनके विरोधी कहते रहते हैं कि मायावती दलित की नहीं, दौलत की बेटी हैं. सही मायने में देखा जाए, तो जातिवाद की राजनीति ने राष्ट्र को खोखला कर दिया है. इसके लिए जितने जिम्मेदार नेता हैं, उतनी ही देश की जनता दोषी है. जनता के खंड-खंड में बंटने से नेताओं की जातिवाद की दुकान चलती रहती है. इसके लिए अंग्रेज भी कम कसूरवार नहीं हैं, जिन्होंने भारत पर राज करने के लिए हिन्दुस्तानियों के साथ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी. वह जानते थे कि हिन्दुस्तान की जनता की यह कमजोर नब्ज है. वह तो विदेशी थे. उन्हें भारत के भविष्य से कुछ लेना-देना नहीं था, लेकिन हमारे नेताओं को इन सब से क्या मतलब. आजादी के बाद से राजनेता देशवासियों के बीच फूट डालकर राज कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

29 जुलाई–04 अगस्त 2013

लखनऊ

भाजपा की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती है. इसके 47 में से 25 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 25 में से 14 विधायकों पर गंभीर आरोप हैं. वहीं, कांग्रेस के 28 में से 13 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. यूपी इलेक्शन वॉच के मुताबिक, 2007 में सूबे में दागी विधायकों की संख्या 235 थी.

देहरादून

लखनऊ

यूपी में बदलेगा राजनीति का चेहरा

राजनीति में अपराधीकरण रोकने पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने राजनीतिज्ञों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों में साफ-सुथरी छवि वाले नेताओं की कमी है. कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

अजय कुमार

दो वर्ष से अधिक की सज़ा पाए लोगों के लिए राजनीति का दरवाज़ा बंद होने से उत्तर प्रदेश के कई दागी नेताओं के माथे पर पसीना आ गया है. उच्चतम न्यायालय के फैसले का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है. लखनऊ के एक सामाजिक संगठन लोकप्रहरी की पीआईएल पर आठ वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो कथित माननीयों की नींद उड़ गई. लखनऊ से अपनी जंग का आगाज करने वाले लोकप्रहरी के संरक्षक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आर के द्विवेदी और इसके कर्ता-धर्ता पूर्व आईएएस एसएन शुक्ला के चेहरे पर अदालत के फैसले के बाद संतोष देखने को मिला. इसके साथ ही उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि इस फैसले से राजनीति की साफ-सुथरी छवि बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन लोकप्रहरी इस बात से भी इत्तेफाक रखता है कि विभिन्न राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सेंध लगाने के लिए कोई गुप-चुप मुहिम चला कर संसद में नया कानून बना सकते हैं.

यूपी में इस फैसले के बारे में कुछ राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राज्य की राजनीति में पिछले कुछ दशकों से अपना दबदबा बना रहे सपा और बसपा को इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है. सबसे अधिक नुक़सान बसपा को होने की उम्मीद है. समाजवादी पार्टी के लिए भी राह ज्यादा आसान नहीं है. सपा में भी आपराधिक प्रवृत्ति के नेता शामिल हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी बात यह है कि मुलायम के अलावा, सपा का कोई और बड़ा नेता इस फैसले से प्रभावित नहीं होगा. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती सहित कई दिग्गज नेताओं का तो राजनीतिक करियर भी समाप्त हो सकता है. अदालत के फैसले से उन दबंगों के चेहरे की रौनक भी चली गई है, जो बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने में सफल हो जाते थे, यानी अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो जल्द ही भविष्य की राजनीति का सूरत-ए-हाल बदल सकता है.

अगर बात यूपी की करें, तो उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधायकों में से 189 (47 प्रतिशत) विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 98 पर हत्या और बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं. 2012 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर तैयार यूपी इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के 224 विधायकों में से 111 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 56 के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. सपा के बाद दूसरा नंबर बसपा का है. इसके 80 विधायकों में से 29 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं. इनमें से 14 पर गंभीर मामले दर्ज हैं.

भाजपा की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती है. इसके 47 में से 25 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 25 में से 14 विधायकों पर गंभीर आरोप हैं. वहीं, कांग्रेस के 28 में से 13 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. यूपी इलेक्शन वॉच के मुताबिक, 2007 में सूबे में दागी विधायकों की संख्या 235 थी. गंभीर अपराधों वाले टॉप टेन विधायकों पर नज़र दौड़ाई जाए, तो पहले नंबर पर सपा के बीकापुर से विधायक मित्रसेन यादव का नाम आता है. सेन के खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं. इनमें से 14 मामले हत्या के हैं. सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मित्रसेन को अपना प्रत्याशी बना रखा है. उनके नाम की घोषणा हाल में ही की गई थी. अपराधी माननीयों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर माफिया डॉन बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह का नाम है. सकलडीहा से निर्दलीय विधायक सुशील सिंह पर 20 मामले दर्ज हैं. इनमें से 12 मामले हत्या के हैं. तीसरे नंबर पर जसराना के सपा विधायक रामवीर सिंह का नाम है. रामवीर के खिलाफ कुल 18 मामले दर्ज हैं. मऊ के कौमी एकता दल से चुने गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी हत्या के आठ मामलों सहित 15 रिपोर्ट दर्ज हैं. माफिया बबलू श्रीवास्तव, बाहुबली धनंजय सिंह, अभय सिंह, रामू द्विवेदी और घपले व आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रंगनाथ मिश्र, राका राकेशधर त्रिपाठी, बादशाह सिंह, रामवीर उपाध्याय, रामअचल राजभर समेत कई नेताओं की सियासी उम्मीदों पर अदालत के फैसले के बाद पानी फिर सकता है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब कम से कम बड़े सियासी दल दागी-दबंगों को अपना उम्मीदवार बनाने से बचेंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हल्कान हैं और इसीलिए नपी-तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी से जब पूछा गया, तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपराधमुक्त राजनीति की शुरुआत होगी. राजनीतिक दलों के लिए टिकट देने में सावधानी बरतने की बाध्यकारी परिस्थितियां पैदा होंगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फैसले को अमल में लाते हुए सुप्रीम कोर्ट को सभी मुकदमों को दो भागों में बांटकर गाइड लाइंस तय करनी चाहिए. पहली श्रेणी में जन समस्याओं के लिए संघर्ष करते हुए राजनीतिक द्वेष से 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट या अन्य धाराओं में दर्ज केस और दूसरी श्रेणी में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के केस होने चाहिए. जन आंदोलनों के मुक़दमों को इससे अलग कर दिया जाना चाहिए. अन्यथा, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष की धार कुंद पड़ जाएगी. जघन्य अपराधों के मामलों में तो केस दर्ज होने पर ही चुनाव लड़ने से रोक लगनी चाहिए. यह भी देखना होगा कि अल्पमत सरकारें बहुमत साबित करने के लिए विपक्षी दलों पर झूठे मुकदमे दायर कर उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं करेंगी. उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. वह कहती हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है. बीते 20 वर्षों में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है. धनबल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ गया है. उम्मीद है कि सभी दल इस पर गंभीरता से विचार करेंगे.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉ सीपी राय का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्रांतिकारी कदम है, पर उस समाज के लिए, जहां व्यवस्था व सत्ता आदर्शवादी हो, जहां पुलिस रोज सैकड़ों फर्जी मुकदमे लिखती हो, आंदोलनकारियों को पीटती हो, उन पर गोली चलाती हो, उन पर मुकदमा लगाती हो और फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार डालती हो, ऐसे समाज में ऐसी व्यवस्था प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है. कहीं ऐसा न हो कि इस फैसले से लोकतंत्र ही मर जाए! लोकतंत्र की बुनियाद है विरोध और धरना-प्रदर्शन. दुर्भाग्य से इस देश में अपराधियों और आंदोलनकारियों, दोनों के लिए एक आईपीसी है. इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए कि लोकतंत्र कहीं पुलिस के हाथ की कठपुतली न बन जाए! इस फैसले को अगर सरकार व सत्ता ने विपक्ष के उत्पीड़न का माध्यम बना लिया, तो आपातकाल से भी बुरी स्थिति बन जाएगी. क्या सर्वोच्च न्यायालय इस पर भी विचार करेगा कि जो सिस्टम जवाबदेह नहीं है, उसकी भी ज़िम्मेदारी तय की जाए और जो समय पर काम न करे, उसे छोड़ दिया जाए. बहरहाल, स्थिति जो भी हो, आने वाले समय में राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर बनने वाली है. ■

दागियों की ताजपोशी क्यों

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागियों को राजनीति से दूर रखने का फैसला सुना दिया है, लेकिन सपा ने जिस तरह से बसपा से निकाले गए पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की ताजपोशी की है, उससे यह साफ हो जाता है कि अभी भी पार्टी को दागियों से कोई परहेज नहीं है.

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में सभी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन दागी नेताओं से कोई भी दल मोहभंग नहीं कर पा रहा है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए चार दिन भी नहीं बीते थे कि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए बसपा से निकाले गए पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा से नजदीकियां बढ़ा ली है. बाबू सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है. इसी कारण बाबू सिंह को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया था. जब बाबू सिंह बसपा में थे, तो सपा उनको फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी. बड़ी बात यह है कि ताजपोशी के दौरान सपा प्रमुख मुलायम सिंह भी मौजूद थे, लेकिन जब मीडिया से मुखातिब होने की बारी आई, तो सपा प्रमुख सामने नहीं आए, जबकि उन्हीं के नाम से प्रेस कांफ्रेंस बुलाई गई थी.

मीडिया के सामने सपा प्रवक्ता और मंत्री राजेन्द्र चौधरी, बाबू सिंह कुशवाहा के भाई और पत्नी को लेकर उपस्थित हुए, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब देने में उनके पसीने छूट रहे थे. जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट राजनीति से दागियों को दूर रखने के लिए अहम कदम उठा रहा है और आप दागी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहें हैं, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने गोल-मोल शब्दों में दिया. गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की तरह ही भाजपा ने भी बीते दिनों संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड के आरोपी सोनू और मोनू सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी. भाजपा के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि सोनू और मोनू को पार्टी में लिया जाए, लेकिन वरुण गांधी के चलते उनकी एक नहीं चली. सोनू और मोनू को भाजपा में शामिल होने से यह संकेत मिल रहा है कि वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी राजनीतिक ताक़त बढ़ाना चाहते हैं. फिलहाल सोनू, मोनू और बाबू सिंह जेल की हवा खा रहे हैं.

वैसे, यहां यह बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय भाजपा कुशवाहा वोट की लालच में बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर खामियाजा भुगत चुकी है. गौरतलब है कि तब समाजवादी पार्टी ने ही भाजपा पर कुशवाहा को शामिल करने के लिए जबर्दस्त हमला बोला था. ■

देहरादून

आखिर उत्तराखंड की सुध कौन लेगा

जलप्रलय, भूस्खलन और भूकंप की इस तिकड़ी के बीच उत्तराखंड पूरी तरह फंस कर रह गया है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. करीब 300 गांव जल प्रलय और चार ज़िले भूकंप के कारण अति संवेदनशील हैं. हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में भी नेता भाषणबाजी में व्यस्त हैं?

जबर सिंह वर्मा

नवोदित राज्य उत्तराखंड में आए जलप्रलय से निपटने में हर मोर्चे पर असफल रही बहुगुणा सरकार अब भविष्य के ख़तरों से निपटने के लिए भी तैयार नहीं दिखती. इस त्रासदी में जान-माल का कितना नुक़सान हुआ, पुनर्वास और विस्थापन की व्यवस्था कब और कैसे होगी, इस पर चर्चा करने की बजाय सीएम और उनके कैबिनेट को चारों धाम को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की चिंता है. नरेंद्र मोदी जैसे देश के नेता बनने की चाह रखने वालों का भी यही हाल है. बहरहाल, प्रदेश सरकार तीन धाम 30 दिसंबर तक खोलने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन त्रासदी का दंश झेल चुके या झेल रहे लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा. सरकार आपदा के बाद केदार और यमुना घाटी के तबाह हो चुके इलाक़ों के पुनर्निर्माण की बात तो कर रही है, लेकिन भविष्य में आने वाली आपदा में यह निर्माण कैसे मज़बूती से खड़ा रह सकेगा, इसकी कार्य योजना फिलहाल सरकार के पास कहीं दिख नहीं रही. जो कुछ दावे-वादे किए जा रहे हैं, उन पर भी अमल नहीं हो पा रहा है. इसमें कोई शक नहीं कि देवभूमि में मानसून की शुरुआत में जो त्रासदी देखने को मिली, बरसात में उसका शिकार फिर लोग हो सकते हैं. बादल फटने, मकान ढहने, ज़मीनें, पुलिया-सड़कें बहने के साथ ही भूस्खलन में मरने की ख़बरें प्रदेश के सभी हिस्सों से आए दिन सामने आ रही हैं. अभी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जबकि मौसम विभाग भीषण बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है.

16-17 जून को केदार और बद्रीनाथ क्षेत्र में बारिश के बाद मची तबाही से साफ हो चुका है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन पूरी तरह पटरी से उतरा हुआ है. इधर, जलप्रलय की तरह ही भूकंप के रूप में सामने आने वाली आपदा से निपटने के लिए प्रदेश

का सरकारी तंत्र पूरी तरह तैयार नहीं है. प्रदेश के 13 में से चार ज़िले भूकंप के लिहाज़ से अति संवेदनशील, जबकि पांच आंशिक रूप से संवेदनशील जोन में आते हैं. आपदाओं से होने वाले संभावित नुक़सान का आकलन सरकार ने अभी तक नहीं किया है. आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक़, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर समेत कई पर्यटक स्थलों पर क़रीब 1109 भवन ऐसे हैं, जो भूकंप का झटका सहन करने लायक नहीं हैं. यही नहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, 16-17 जून को आई आपदा के कारण केदार घाटी से लेकर सोनप्रयाग के बीच करीब 192, जबकि बद्रीनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच क़रीब दो दर्जन नए भूस्खलन जोन विकसित हो गए हैं. ऐसे में, भूकंप का हल्का झटका भी सूबे में भारी तबाही का कारण बन सकता है. रुद्रप्रयाग में भूकंप का हल्का झटका हाल ही में महसूस भी किया गया. ज़ाहिर है, जलप्रलय के चलते अति संवेदनशील हो चुके करीब तीन सौ गांवों पर ख़तरा अब और बढ़ गया है. भूकंप के बाद की आपदा नियंत्रण की स्थिति को जानने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है, लेकिन यह कार्यक्रम भी सिर्फ चमोली जनपद और उसके आसपास के क्षेत्र में सिमट कर रह गया है. मसूरी, नैनीताल समेत दूसरे हिल स्टेशनों के लिए भूकंप की दृष्टि से तैयार की गई रिपोर्ट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आपदा प्रबंधन विभाग की इस रिपोर्ट में हिल स्टेशनों के कई पुराने और जर्जर भवनों को ख़तरा बताया गया है, जिन्हें कई साल पहले मानकों में ढील देकर पुनर्निर्माण की स्वीकृति देने की सिफारिश की गई थी. अकेले मसूरी में ही ऐसे 500 से अधिक भवन हैं. कुल मिलाकर जलप्रलय, भूस्खलन और भूकंप की इस तिकड़ी के बीच उत्तराखंड पूरी तरह फंस कर रह गया है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. ■